राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 23

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, शनिवार, 3 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14



लद्दाख में यथास्थिति बहाल न हुई तो अप्रत्याशित कदम उठा सकता है भारत : रावत

>>3

जागरण विशेष

सलई का गोंद बदल रहा आदिवासियों की किस्मत



ग्वालियर : मप्र के श्योपुर जिले में पाए जाने वाले सलई के पेड़ से निकलने वाला गोंद आदिवासियों की किस्मत बदल रहा है। गुजरात की एक कंपनी यहां पौधारोपण करा रही है। पेड़ बनने पर इन्हें आदिवासियों को सौंपा जाएगा ताकि वह गोंद बेच सकें। (पेज-10)

बंगाल हिंसा के सभी पीड़ितों के केस दर्ज करे पुलिस

कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त ▶ एनएचआरसी की समिति की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर की कई गंभीर टिप्पणियां

पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा व राशन मुहैया करने का भी राज्य सरकार को दिया निर्देश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सख्त रुख अख्तियार करते हुए पुलिस को आदेश दिया कि वह हिंसा पीड़ितों के सभी मामलों को प्राथमिकी के रूप में दर्ज करे। अदालत ने राज्य सरकार को सभी पीड़ितों (घायलों) के लिए चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने और राशन कार्ड न होने पर भी प्रभावितों के लिए राशन मुहैया करने का भी निर्देश दिया है। हिंसा की जांच के लिए हाई कोर्ट के निर्देश पर गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर अदालत ने उक्त निर्देश दिए हैं। साथ ही रिपोर्ट के आधार पर ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर टिप्पणियां भी कीं। पूर्व में भी हाई कोर्ट ममता सरकार को फटकार लगा चुका है, जब उसने हिंसा की बात को नकार दिया था।

दरअसल, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का आरोप लगाने वाली कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जस्टिस आइपी मुखर्जी, हरीश टंडन, सौमेन सेन और सुब्रत तालुकदार की पांच सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा, एनएचआरसी की समिति की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया कदम सही दिखता है, जिसमें चुनाव के बाद हिंसा की बात कही गई है। रिपोर्ट में कार्यकर्ताओं की बेरहमी से हत्या, महिलाओं संग दुष्कर्म व बर्बरता आदि का जिक्र है, जिसका याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है। लोग मर रहे थे। नाबालिग लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया। कई लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। कई लोगों को दूसरे राज्य जाना पड़ा। इससे ममता बनर्जी सरकार की गलती दिखती है, पर वह मुकर रही है।

एनएचआरसी की समिति पर हमले को लेकर नोटिस: पीठ ने हिंसा की जांच के लिए मौके पर गई एनएचआरसी की समिति पर 29 जून को जादवपुर इलाके में हुए हमले पर भी सख्त रवैया अपनाया। पीठ ने हालात काबू करने में विफल रहने के लिए दक्षिण कोलकाता के पुलिस उपायुक्त राशिद मुनीर खान को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए?

डीएम-एसपी पर क्यों न चलाया जाए अवमानना का मामला : पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को चुनाव बाद हुई हिंसा से संबंधित सभी दस्तावेज को सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं। एनएचआरसी समिति द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर पीठ ने यह निर्देश दिए हैं। पीठ ने कुछ क्षेत्रों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी नोटिस जारी कर पूछा है कि हिंसा रोकने में विफल रहने पर उनके खिलाफ क्यों न अवमानना का केस चलाया जाए।

हिंसा की बात को नकारने पर ममता सरकार को पहले भी फटकार लगा चुका है हाई कोर्ट



एनएचआरसी की समिति की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया कदम सही दिखता है, जिसमें चुनाव के बाद हिंसा की बात कही गई है। ममता बनर्जी की सरकार की गलती दिखती है, पर वह मुकर रही है। -कलकत्ता, हाई कोर्ट

एनएचआरसी की जांच को 13 जुलाई तक बढ़ाया

पीठ ने चुनाव बाद हिंसा की एनएचआरसी की जांच को 13 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई भी अब 13 जुलाई को ही होगी। अदालत ने राज्य सरकार को जो भी निर्देश दिए हैं, उसकी कार्रवाई के संबंध में 13 जुलाई को स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। गौरतलब है कि हाई कोर्ट के आदेश पर मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच कर रही एनएचआरसी की समिति ने इससे पहले हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और पीड़ितों से बातचीत के बाद 30 जून को पिछली सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष सीलबंद लिफाफे में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी।



सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा है जवाब

बंगाल हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। इस पर उसने राज्य व केंद्र सरकार के साथ ही चुनाव आयोग को एक जुलाई को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब तलब किया है। मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनाया गया है, मगर उनको नोटिस जारी नहीं किया गया है।

चुनाव नतीजों के बाद 41 कार्यकर्ताओं की हो चुकी है हत्या : भाजपा

प्रदेश भाजपा का दावा है कि चुनाव नतीजों के बाद से अब तक हिंसा में उसके 41 कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। हालांकि, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस हिंसा में हाथ होने से इन्कार करती रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार कह चुकी हैं कि भाजपा द्वारा हिंसा को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।

भाजपा कार्यकर्ता के शव का दोबारा हो पोस्टमार्टम

पीठ ने भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के शव का कोलकाता के कमांड अस्पताल में फिर से पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है, जिनकी चुनाव के बाद की हिंसा में भीड़ द्वारा कथित रूप से हत्या कर दी गई थी।

बंगाल विस में हंगामा, चार मिनट अभिभाषण पढ़ने के बाद बाहर निकल गए राज्यपाल पेज>>4

लक्षद्वीप प्रशासन ने वापस बुलाए अपने शिक्षा कर्मचारी

कोच्चि : एक विवादित कदम के तहत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासन ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के कर्मियों को कोच्चि से वापस बुलाने का आदेश जारी किया। कोच्चि में तैनात शिक्षा अधिकारी से कहा गया है कि कर्मियों को इस निर्देश के साथ कार्यमुक्त किया जाए कि सात दिनों के भीतर वे लक्षद्वीप में रिपोर्ट करें। (पेज-3)

'एक जिला-एक उत्पाद' के लिए 707 जिलों के प्रस्ताव मंजूर

नई दिल्ली : केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश के 707 जिलों को 'एक जिला-एक उत्पाद' के लिए अनुमोदित किया है। इसके लिए 17 राज्यों में 50 से अधिक इंक्यूबेशन केंद्रों की मंजूरी भी दी गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में एक वर्ष के भीतर कई पहल की गई है। (पेज-7)

बिहार में दो से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

पटना : बिहार सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरियों के चुनाव में दो से अधिक बच्चे वालों को अयोग्य घोषित करने का मसौदा तैयार कर रहा है। सरकार यह प्रविधान इस बार के चुनाव में लागू नहीं करेगी, अगर चुनाव टला तो फिर दो से अधिक बच्चे वालों पर नए कानून की गाज गिरनी तय है। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

दुष्कर्म पीड़िता का नाम लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रसन्नता जताई

नई दिल्ली : छत्तीसगढ़ की एक सत्र अदालत द्वारा अपने फैसले में दुष्कर्म पीड़िता का नाम लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रसन्नता जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसे मामलों से निपटते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह पूरी तरह स्थापित है कि किसी कार्यवाही के दौरान पीड़िता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 5

मुनव्वर राना के बेटे ने खुद पर चलवाई थीं गोलियां, चार गिरफ्तार

रायबरेली : शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना ने ही खुद पर गोलियां चलवाई थीं। उसने संपत्ति विवाद में चाचा और चचेरे भाई को फंसाने के लिए यह साजिश रची थी। पुलिस ने शूटर समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। तबरेज अभी फरार है। सोमवार शाम उप्र के रायबरेली जिले में त्रिपुला चौराहे के पास तबरेज पर कथित तौर पर हमला हुआ था। पेट्रोल पंप के सीसी कैमरे और तबरेज के फोन की काल डिटेल से सच्चाई सामने आ गई।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 7

चीनी मिल मामले में अजीत पवार व उनकी पत्नी ईडी के निशाने पर

मुंबई : गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त की गई जरंडेश्वर चीनी मिल के मामले में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार एवं उनकी पत्नी सुनेत्रा भी अब ईडी के निशाने पर हैं। अजीत पवार ने अपने परिवार पर लग रहे आरोपों का खंडन किया है। उधर शिवसेना नेता संजय राउत अजीत पवार के बचाव में उतर आए हैं। ईडी इन दिनों महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में हुए घोटाले की जांच कर रही है।

स्पोर्ट्स ▶ पृष्ठ 12

माना को विश्वविद्यालय कोटा से मिला टोक्यो का टिकट

नई दिल्ली : भारतीय महिला तैराक माना पटेल को भी टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिल गया है। भारतीय तैराकी महासंघ (एएफआइ) ने शुक्रवार को बताया कि माना की विश्वविद्यालय कोटा से टोक्यो ओलंपिक में भागीदारी की पुष्टि हो गई है। माना टोक्यो खेलों में 100 मीटर बैकस्ट्रोक में भाग लेंगी। वह इन खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाली तीसरी भारतीय तैराक हैं।

पुलवामा मुठभेड़ में पांच आतंकी ढेर, जवान शहीद

- मारे गए आतंकियों में लश्कर का जिला कमांडर और एक पाकिस्तानी भी शामिल
- आतंकियों की मौत से पुलवामा में लश्कर का नेटवर्क लगभग खत्म



पुलवामा में शुक्रवार को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल के जवान। प्रेट्र >>

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के हांजिन में सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को लश्कर-ए-तैयबा के पांच लाख के इनामी आतंकी निशाज हुसैन उर्फ खिताब और उसके चार साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी भी है। करीब 16 घंटे चली इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद और एक जख्मी हुआ है। मारे गए आतंकियों के पास से दो एसाल्ट राइफल, सुरक्षाबलों से लूटी गईं दो एसएलआर राइफल और दो पिस्तौल व अन्य सामान मिले हैं। निशाज व उसके चार साथियों की मौत को दक्षिण कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा की कमर पर सुरक्षाबलों की बहुत बड़ी चोट माना जा रहा है। अधिकारियों की मानें तो इन पांच आतंकियों की मौत से पुलवामा में लश्कर का नेटवर्क लगभग समाप्त हो गया है।

हांजिन में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर गुरुवार रात पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया था। आतंकियों ने खुद को फंसते देख घेराबंदी तोड़कर भागने के लिए जवानों पर फायरिंग की। जवानों ने भी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई थी।

कश्मीर परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आइजीपी) विजय कुमार ने बताया कि आतंकियों को आत्मसमर्पण करने का पूरा मौका दिया गया, लेकिन वे गोलियां दागते रहे। इसी दौरान एक सैन्यकर्मी गोली लगने से जख्मी हो गया। उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां वह वीरगति को प्राप्त हो गया। सेना के प्रवक्ता ने शहीद सैन्यकर्मी का नाम काशीर बम्मानाली बताया है। प्रवक्ता ने मुठभेड़ में घायल एक अन्य जवान की पुष्टि नहीं की है।

सेना के प्रवक्ता ने बताया कि एक आतंकी शुक्रवार तड़के ही मारा गया था जबकि दो अन्य दोपहर 12 बजे तक ढेर कर दिए गए थे। इसके बाद करीब एक घंटे तक फायरिंग बंद रही। जवानों ने जब मुठभेड़स्थल की तलाशी ली तो उन्हें चौथे आतंकी का शव मिला। इसी दौरान वहां छिपे एक अन्य आतंकी ने फिर से जवानों पर गोली चला दी। इसके बाद मुठभेड़ फिर शुरू हो गई। कुछ ही देर में उसे भी मार गिराया गया। यह अभियान लगभग 16 घंटे चला है।

गोलाबारी के बीच लोगों को निकाला गया

आइजीपी विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों पहचान की पुष्टि की की जा रही है। उन्होंने बताया कि आतंकियों ने जहां ठिकाना बना रखा था, वहां आसपास के घरों से कई लोगों को सुरक्षाकर्मियों ने आतंकियों की गोलीबारी के बीच ही सुरक्षित निकाला था।

जम्मू में 100 से अधिक लोगों को मारने की थी साजिश पेज>>5

इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के ऊपर भी मंडराता दिखा ड्रोन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ भारत ने इमरान सरकार से की शिकायत, पाक का इन्कार

▶ पिछले हफ्ते हुई इस घटना को सुरक्षा के लिए माना जा रहा खतरा

दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में लगातार जुटे रहने वाला देश पाकिस्तान अब ड्रोन को अपनी नापाक कोशिशों के लिए स्थायी माध्यम बना चुका है। अभी जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिये विस्फोट करने का मामला सुलझा भी नहीं है कि अब इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के कार्यालय के उपर ड्रोन मंडराने की खबर आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस सूचना की पुष्टि की है।

भारत ने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के समक्ष इस मुद्दे को उठाया भी है। जम्मू में ड्रोन से बम विस्फोट कराने के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने के बाद भारत दुनिया की इस सबसे बड़ी पंचायत में इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग की सुरक्षा का मुद्दा भी आने वाले दिनों में उठा सकता है। भारत की तरफ से इस मुद्दे पर सख्ती दिखाने पर पाकिस्तान ने इस बात से इन्कार किया है कि भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में कोई खामी है।



अरिंदम बागची। फाइल/ इंटरनेट मीडिया

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के भवन के उपर पिछले हफ्ते ड्रोन देखा गया है। हमने पाकिस्तान सरकार को इसकी जांच करवाने को कहा है क्योंकि यह बड़ी सुरक्षा चूक है। बागची ने पाक को आतंकी संगठनों के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई करने की याद दिलाते हुए कहा, अन्य देशों के साथ ही भारत भी यह उम्मीद करता है कि पाक आतंकवाद के खिलाफ ठोस, निर्णायक व साफ तौर पर दिखने वाला कदम उठाएगा और मुंबई व पठानकोट हमले को अंजाम देने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेगा।

भारत की इस चिंता की एक वजह यह भी है कि उच्चायोग के ऊपर तकरीबन उस समय ड्रोन देखा गया जब आतंकियों ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर (26-27 जून की रात) ड्रोन से दो बम गिराये थे। इसकी जांच अभी जारी है। शुरुआती संकेत बताते हैं कि इसमें पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठनों का हाथ है। बहरहाल, भारत की तरफ से इस बारे में बयान आने के तुरंत बाद पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि भारत के ड्रोन संबंधी दावे के पीछे कोई सत्यता नहीं है। भारत ने कोई भी ऐसा साक्ष्य साझा नहीं किया है जिसकी जांच करवाई जाए।

सीमा पर जासूसी करने घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने भगाया पेज>>5

खुदरा और थोक व्यापार को मिला एमएसएमई का दर्जा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

खुदरा व थोक व्यापारी भी अब एमएसएमई को मिलने वाले सभी लाभ ले सकेंगे। सरकार ने खुदरा व थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) का दर्जा दे दिया है। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। काफी लंबे समय से खुदरा व थोक व्यापारी इस दर्जे की मांग कर रहे थे। एमएसएमई की परिभाषा में इस बदलाव से 2.5 करोड़ खुदरा व थोक व्यापारियों को लाभ मिलेगा।

गडकरी ने कहा कि खुदरा व थोक व्यापार अब तक एमएसएमई के दायरे से बाहर थे। नए बदलाव से इन्हें भी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के तहत प्राथमिकता पर बैंकों से कर्ज मिल सकेगा। इसके तहत बैंक कृषि, एमएसएमई व कुछ अन्य सेक्टर को सस्ती दरों और प्राथमिकता के आधार पर कर्ज देते हैं। एमएसएमई के दायरे में शामिल होने के बाद अब खुदरा व थोक व्यापारी उद्यम पोर्टल पर पंजीयन करा सकेंगे।



नितिन गडकरी। फाइल/ इंटरनेट मीडिया

व्यापारी भी ले सकेंगे छोटे उद्यमियों को मिलने वाले लाभ, बैंकों से प्राथमिकता के आधार पर मिल सकेगा सस्ता कर्ज

रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ कुमार राजगोपालन के मुताबिक, कोरोना की दूसरी लहर की चुनौतियों का सामना कर रहे रिटेलर्स को इस फैसले बड़ी राहत मिलेगी। रिटेलर्स कारोबार पुनर्जीवित करने के लिए आसानी से कर्ज ले सकेंगे। पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गारंटी मुक्त लोन से जुड़ी स्कीम में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड देने की घोषणा की है। इसके तहत 30 सितंबर तक कर्ज लिया जा सकता है। अब खुदरा व थोक व्यापारी भी गारंटी मुक्त लोन स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। छोटे व्यापारी अब सरकारी पोर्टल जेम पर उत्पादों की बिक्री भी कर सकेंगे।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिया इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, देहरादून



तीरथ सिंह रावत।

शुक्रवार रात सवा 11 बजे राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा इस्तीफा

इस साल 10 मार्च को ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार देर रात पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले तीन दिन से दिल्ली में रुके तीरथ को शुक्रवार दोपहर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके विधानसभा उपचुनाव में आ रही संवैधानिक अड़चन की जानकारी देते हुए साफ कर दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद तीरथ उन्हें अपने इस्तीफे की पेशकश का पत्र सौंप देहरादून लौट आए। मुख्यमंत्री तीरथ ने रात्रि सवा 11 बजे राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर करते हुए नए मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने को कहा। नया नेता चुनने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक शनिवार दोपहर तीन बजे देहरादून में बुलाई गई है। यह लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार नए नेता का चयन विधायकों में से ही किया जाएगा।

त्रिवेंद्र के बाद तीरथ की भी नाटकीय विदाई : गुजरे मार्च में जिस तरह नाटकीय और अप्रत्याशित तरीके से मुख्यमंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत रुखसत हुए थे, कुछ वैसी ही तीरथ सिंह रावत की विदाई की पटकथा भी रही। 17 जून को ही अपने कार्यकाल के सौ दिन पूरे करने वाले तीरथ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उपचुनाव लड़ने का मौका न मिल पाने के कारण उन्हें इतनी जल्दी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अगर उन्हें ऐसा आभास होता तो शायद वह अपने छोटे से कार्यकाल में हुए सल्ट (अल्मोड़ा) विधानसभा सीट के उपचुनाव में ही स्वयं मैदान में उतर जाते।

संवैधानिक अड़चन के कारण तीरथ को छोड़ना पड़ा पद पेज>>4

भविष्य की चिंता

स्कूल खुलने तक पंचायतों में टीवी से पढ़ायें

शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने दिया सुझाव, सभी छात्रों तक आनलाइन शिक्षा की पहुंच बनाने को समिति ने बुलाई थी अहम बैठक, उप्र, बिहार समेत आधा दर्जन राज्य सेटेलाइट चैनेल की सुविधा के इस्तेमाल पर राजी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना काल में बच्चों को घर बैठे पढ़ाने के लिए शुरू हुई आनलाइन शिक्षा को सभी की पहुंच में लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने शुक्रवार को सरकार को एक अहम सुझाव दिया है। जिसमें कहा गया कि जब तक कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य नहीं होती और स्कूल नहीं खुलते तब तक बच्चों को आनलाइन पढ़ाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में एक बड़ा टेलीविजन लगाया जाए। जिसे खुली जगह या फिर किसी बड़े सभागार में लगाया जाए। जहां स्मार्ट फोन या टीवी से वंचित बच्चे निर्धारित समय पर आकर अपनी पढ़ाई कर सकें।

शिक्षा मंत्रालय की इस संसदीय समिति ने इस दौरान दिव्यांग बच्चों का भी ख्याल रखने का सुझाव दिया। खास बात यह है कि समिति ने आनलाइन शिक्षा को लेकर यह पहल तब की जब हाल ही में आई रिपोर्ट में यह सामने आया कि सिर्फ तीस फीसद बच्चों के पास ही स्मार्ट फोन या इंटरनेट जैसी सुविधाएं हैं। ऐसे में बाकी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है।

समिति ने इसके बाद ही मंत्रालय से आनलाइन पढ़ाई से जुड़ा पूरा ब्योरा तलब किया। जिसके बाद आनलाइन पढ़ाई में ढिलाई दिखाने वाले आधा दर्जन राज्यों को पहले चरण में तलब भी किया। आने वाले दिनों में कुछ और राज्यों को भी इस मामले में तलब किया जाएगा।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय समिति के अध्यक्ष डाक्टर विनय सहस्रबुद्धे की अगुवाई में हुई इस बैठक में समिति ने आनलाइन शिक्षा को सभी तक पहुंचाने के लिए सेटेलाइट चैनेल की सुविधा का इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया। साथ ही इसरो और प्रसार भारती से भी इस पर राय ली। खास बात यह है कि इसरो की मदद से शिक्षा के लिए सेटेलाइट चैनेल की सुविधा मुहैया कराई जाती है। आनलाइन शिक्षा को लेकर ढिलाई दिखाने के मामले में तलब किए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना से जानकारी ली गई। उनसे पूछा गया कि वे सेटेलाइट चैनेल की सुविधा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर राज्यों ने भरोसा दिया, कि वे जल्द ही इसे शुरू करेंगे।



फाइल फोटो/ इंटरनेट मीडिया

2022 में परीक्षा न होने पर नए पैटर्न से होगा मूल्यांकन

समिति ने इस दौरान शिक्षा मंत्रालय से 2022 की परीक्षा तैयारियों को लेकर भी सवाल पूछा। जिस पर मंत्रालय ने बताया कि स्थिति सामान्य रही तो परीक्षाएं होंगी। बावजूद इसके इस बार मूल्यांकन की एक नई प्रक्रिया पर काम हो रहा है, जिसे परीक्षा न होने की स्थिति में इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसे पहले से ही तैयार रखा जाएगा, ताकि बाद में भ्रम की स्थिति पैदा न होने पाए।

केस बढ़ने पर केंद्र ने छह राज्यों में भेजी टीमें

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के छह राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर केंद्र सरकार ने वहां विशेषज्ञों की टीमें भेजी हैं। ये टीमें संक्रमण को रोकथाम व महामारी से निपटने के राज्यों की मदद करेंगी। केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ व मणिपुर में मामले बढ़ रहे हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय टीम इन राज्यों को संक्रमण को रोकने और महामारी पर प्रभावी तरीके से काबू पाने में मदद करेंगी। हर टीम में दो सदस्य हैं जिसमें एक क्लीनिकल और एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ शामिल हैं।

केंद्रीय टीमें तत्काल राज्य का दौरा करेंगी और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों पर नजर रखेंगी। खासकर जांच, सतर्कता और रोकथाम जैसे उपायों पर। इसके अलावा कोरोना से बचाव के उपायों को सही तरीके से लागू करने, अस्पताल में बेड, एंबुलेंस, वेंटिलेटर, आक्सीजन इत्यादि की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगी। साथ ही समस्याओं को दूर करने के उपाय भी सुझाएंगी। कोरोना महामारी से निपटने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर अपनी तरफ से विशेषज्ञों की टीम भेजती रही है। ये टीमें राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर हालात का जायजा लेती हैं और फिर उसी के मुताबिक उनसे निपटने के उपाय भी बताती हैं। मंत्रालय ने कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया है, ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाया जा सके।

कोरोना से जंग

- दो सदस्यीय टीम में एक क्लीनिकल और एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ शामिल
- केरल, अरुणाचल, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में बढ़ रहे मामले



कोरोना वैक्सीन की 34 करोड़ से ज्यादा लगीं डोज

नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना रोधी वैक्सीन की अब तक 34 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। गत 24 घंटे के दौरान 42 लाख से ज्यादा डोज लगाई गईं। टीकाकरण अभियान के 167वें दिन एक जुलाई को 42,64,123 डोज दी गईं। (पेज-6)

केंद्र सरकार ने कहा, दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, लापरवाही न बरतें पेज>>6

73 सौ मेगावाट के ऊपर पहुंच गई शुक्रवार को अपराह्न सवा तीन बजे बिजली की मांग। बिजली की खपत बढ़ने के साथ ही घनी आबादी वाले इलाके में बिजली की अघोषित कटौती भी शुरू हो गई।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 3 जुलाई, 2021

सब्जियों के जरिये थाली तक पहुंच रहा यमुना का जहर

सेहत के लिए खतरा ▸ यमुना के प्रदूषित पानी से उगने वाली सब्जियों में भी पाए गए हैं हानिकारक तत्व

तटवर्ती इलाकों में उपजी सब्जियां गाजीपुर मंडी से लेकर कई छोटे बाजारों तक बिक रहीं

आशीष गुप्ता, नई दिल्ली

यमुना के तटवर्ती इलाकों में इसके प्रदूषित पानी से उपजी सब्जियां उन लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा हैं, जो लगातार इनका सेवन कर रहे हैं। देखने में ये सब्जियां भले ही हरी, ताजी और चमकदार दिखती हों, लेकिन असल में इन सब्जियों को खाना कैंसर को न्यौता देने के बराबर है।

कई अध्ययन इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि यमुना खादर में उगने वाली सब्जियों में जहर घुला है, लेकिन इसकी रोकथाम व हालात में बदलाव की कोशिशें करने के बजाय सरकारी महकमे हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, जिसकी वजह से यमुना में घुला जहर लोगों की थाली तक पहुंच रहा है। प्रदूषण और उसके नुकसान की हकीकत से वाकिफ होने के बाद भी यमुना खादर में बड़े स्तर पर सब्जियों की खेती की जाती है। यहां उगने वाली सब्जियां गाजीपुर सब्जी मंडी पहुंचती हैं, जहां से ये पूरे एनसीआर में पहुंचती हैं।



आइटीओ यमुना किनारे उगाई गई सब्जियों की देखरेख करते हुए युवा। ध्रुव कुमार

ललचाती है ताजगी : कई किसान छोटी मंडियों में खुद जाकर प्रदूषित पानी से उपजी सब्जियां बेचने जाते हैं। इनकी ताजगी लोगों को ललचाती है। अक्सर तमाम लोग इन्हें सेहत के लिए अच्छी समझकर खाते हैं।

जल और जमीन दोनों प्रदूषित : यमुना के पानी का प्रदूषण तो दूर से दिखता है, लेकिन इसके तटवर्ती क्षेत्रों में जहां सब्जियों की खेती की जाती है वह जमीन भी प्रदूषित है और उन तमाम खतरनाक प्रदूषक तत्वों से भरी है जो पानी को प्रदूषित करते हैं। धर्मशिला नारायणा अस्पताल के कैंसर विशेषज्ञ डा. अंशुमान कुमार ने इस संबंध में अध्ययन किया है। डा. अंशुमान बताते हैं कि उन्होंने यमुना खादर के अलग-अलग स्थानों से मिट्टी और उसमें उगने वाली सब्जियों के नमूने लिए थे। जांच करने पर मिट्टी प्रदूषित पाई गई। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह पता चली कि उस जमीन में उग रहीं सब्जियां भी जहरीली थीं।

मानकों पर खरी नहीं हैं सब्जियां : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के मानकों के अनुसार सब्जी में सीसा की मात्रा 0.1 पीपीएम से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन यमुना खादर में उपजी सब्जियों में इसकी मात्रा 28.06 पीपीएम तक पाई गई है। ऐसे ही कैडमियम की मात्रा 3.42 पीपीएम तक पाई गई, जोकि स्वीकृत मात्रा 0.1 से 0.2 पीपीएम से काफी अधिक है। पारा की मात्रा 105 से 139 पीपीएम पाई गई, जबकि यह एक पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आर्सेनिक भी काफी मात्रा में पाया गया, जोकि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।

हमारा प्रदूषण हमारी ही सेहत का दुश्मन : डा. अंशुमान के मुताबिक यमुना में प्रदूषण पूरी तरह से इंसानी कारणों से है। मसलन, तमाम फैक्ट्रियों और घरों का मैला पानी नालों से नदी में पहुंचकर इसे प्रदूषित करता है। यमुना का जल स्तर बढ़ने पर ये तत्व पानी के साथ खादर क्षेत्र में मिट्टी को प्रदूषित व जहरीला कर देते हैं। उसी मिट्टी के में उपजी सब्जियों के जरिये यह जहर वापस हमारी थाली में आ जाता है।

प्रदूषण बढ़ने के साथ घट रही पैदावार : सब्जियों की पैदावार उतनी नहीं रही, जितनी पहले हुआ करती थी। यमुना खादर में खेती कर रहे किसानों का कहना है कि जैसे-जैसे यमुना के पानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उसी अनुपात में उपज कम होती जा रही है। किसानों की मानें तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी यमुना के प्रदूषण का कुप्रभाव पड़ रहा है। यही वजह है कि काफी किसान यहां से जा चुके हैं। खादर की काफी जमीन का हिस्सा वन विभाग ने अपने कब्जे में लेकर उसमें पेड़ लगाने के बाद तारबंदी कर दी है। ऐसे में सब्जियों की पैदावार लगातार कम हो रही है। किसान कहते हैं कि यमुना की सफाई पर ध्यान दिया जाता तो खेती के सहारे रोजगार के बड़े अवसर यहां पैदा किए जा सकते थे।

यहां हो रही यमुना खादर में खेती: जैतपुर से लेकर जैतपुर पार्ट-2, खड्डा कालोनी, गीता कालोनी, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन, मयूर विहार फेज-1 और चिल्ला के आपपास अब भी सब्जियां पैदा की जा रही हैं।

इन सब्जियों की होती है खेती: तोरई, घीया, भिंडी, सीताफल, मिर्च, खीरा, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, पालक, धनिया, टमाटर, गाजर, करेला के अलावा कुछ जगह गेहूं और सरसों की पैदावार भी होती है।

> यमुना खादर में उगने वाली सब्जी दूषित होती है, लेकिन मंडी के स्तर पर वहां से आने वाली सब्जी पर रोक लगा पाना मुमकिन नहीं है। सब्जी बेचने वाला किसान यह नहीं बताता कि वह खेती कहां कर रहा है। हर किसान से यह पूछ पाना भी मुमकिन नहीं है। प्रदूषित यमुना के खादर क्षेत्र में खेती पर एनजीटी को रोक लगा देनी चाहिए। सब्जी की खेती बंद हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा।
> – सत्यदेव प्रसाद गुप्ता, चेयरमैन, गाजीपुर सब्जी एवं फल मंडी

> यमुना नदी के पानी में जो हानिकारक तत्व हैं वे जमीन में घुलते हैं, जाहिर है उनका असर इस जल से सिंचित जमीन पर उपजी सब्जियों पर भी पड़ेगा। इसका हल यही है कि यमुना को साफ किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता, खेती पर रोक लगे।
> – डा. जितेंद्र नागर, पर्यावरणविद

> पहले घर में यमुना खादर के खेतों से ताजी सब्जी आती थी। अब यहां की सब्जी घर नहीं आती, क्योंकि नदी पूरी तरह गंदी हो चुकी है। नाले का पानी इसमें आता है।
> – सत्येंद्र पाल, निवासी, मयूर विहार फेज-एक

शेखावत बोले, यमुना की सफाई पर गंभीर नहीं है दिल्ली सरकार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार से करोड़ों रुपये की मदद मिलने के बाद भी यमुना की स्थिति नहीं सुधरी है। इसे लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखाकर यमुना को साफ करने को लेकर उनके चुनावी वादे को याद कराया है।

शेखावत ने पत्र में बताया कि यमुना नदी का सिर्फ दो फीसद हिस्सा ही दिल्ली में आता है, जबकि प्रदूषण के लिए दिल्ली 80 फीसद जिम्मेदार है। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के तहत यमुना की सफाई से संबंधित 13 परियोजनाओं के लिए दिल्ली सरकार को 2,419 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई है। इससे रोजाना 1,385 मीलियन लीटर सीवर के पानी के शोधन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार ने इस पर गंभीरता से काम नहीं किया और निविदा को अंतिम रूप देने में बहुत विलंब किया गया, जिसकी वजह से निर्माण कार्य में 15 से 27 महीने की देरी हो रही है।

पवित्र नदी गंदा नाला बनी: उन्होंने पत्र में लिखा कि दिल्ली के 18 नालों से प्रतिदिन 3,500 मीलियन लीटर गंदा पानी शोधित किए बिना यमुना में बहाया जाता है। दिल्ली सरकार की इस लापरवाही से दिल्ली में यह पवित्र नदी गंदे नाले में तब्दील हो गई है।

न्यूज गैलरी

सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आदेश टला

नई दिल्ली : सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शुक्रवार को विशेष अदालत ने अपना आदेश 27 जुलाई के टाल दिया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से अर्जी दाखिल कर एक सप्ताह का समय मांगा गया था। विशेष अदालत ने अर्जी को मंजूर कर लिया। शुक्रवार को विशेष अदालत को फैसला सुनाना था कि कांग्रेस नेता एवं मृतका के पति शशि थरूर के खिलाफ ट्रायल चलेगा या नहीं। 17 जनवरी, 2014 को सुनंदा पुष्कर का शव एक पांच सितारा होटल के कमरे में मिला था। पुलिस ने पहले अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। बाद में प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में शशि थरूर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। थरूर इस मामले में जमानत पर हैं। (जासं)

कनाट प्लेस के पांच सितारा होटल में युवती से दुष्कर्म

नई दिल्ली: कनाट प्लेस स्थित पांच सितारा होटल में एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर कनाट प्लेस थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया है, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। दक्षिणी दिल्ली निवासी 26 वर्षीय पीड़िता एक कंपनी में इवेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रही है। कुछ माह पहले उसकी फेसबुक के जरिये गोरखपुर निवासी पीयूष से दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती रही। उसने युवती को शादी का झांसा दिया था। 23 जून को पीयूष ने दिल्ली आने की बात कहते हुए पीड़िता को खाना खाने के लिए कनाट प्लेस के पांच सितारा होटल रेडिसन ब्लू मरीना में बुलाया। आरोप है कि यहां पेयजल में नशीला पदार्थ देकर आरोपित ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। (जासं)

राज्यसभा सदस्य के आवास पर लगी आग

नई दिल्ली : राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा के शाहजहां रोड स्थित आवास पर शुक्रवार रात आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। इस घटना में उनके परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस घटना की जानकारी राकेश सिन्हा ने खुद ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मेरे शाहजहां रोड स्थित आवास पर भीषण आग लगी है। परिवार सुरक्षित है। (जासं)

हाइब्रिड फाइनेंशियल माडल पर विकसित हो सकती है फिल्म सिटी

जासं, ग्रेटर नोएडा: यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित होने वाली फिल्म सिटी के लिए हाइब्रिड फाइनेंशियल माडल पर मुहर लग सकती है। यमुना प्राधिकरण ने इसके लिए शासन से संस्तुति करने का फैसला किया है।

यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में एक हजार एकड़ क्षेत्र में फिल्म सिटी विकसित होगी। कोल्डवैल बैंकर्स रिचर्ड एलिस सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। तीन चरण में विकसित होने वाली फिल्म सिटी के विकास पर करीब साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। एजेंसी ने फिल्म सिटी के विकास के लिए तीन फाइनेंशियल माडल का विकल्प दिया है। पहले विकल्प में विकासकर्ता से एकमुश्त रकम वसूलना, दूसरे विकल्प में फिल्म सिटी से होने वाली कमाई में तयशुदा अनुपात में हिस्सेदारी औरतीसरा विकल्प इन दोनों का हाइब्रिड है।

राजधानी में दूसरी लहर में 40 फीसद अधिक हुईं मौतें

राज्य ब्यूरो, नहीं दिल्ली

पहली लहर की तुलना में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अधिक घातक साबित हुई है। इस लहर में न सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों को आक्सीजन की जरूरत पड़ी, बल्कि पिछली लहर की तुलना में 40 फीसद अधिक लोगों की जान भी गई है। यह बात मैक्स हेल्थकेयर के एक सर्वे में सामने आई है। यह सर्वे 10 अस्पतालों में भर्ती कराए गए मरीजों पर किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत में स्थित मैक्स के 10 अस्पतालों में पहली लहर में भर्ती 14 हजार 398 व दूसरी लहर में भर्ती 5454 मरीजों पर यह अध्ययन किया गया। पहली लहर में भर्ती हुए 54.8 फीसद मरीज दूसरी बीमारियों से पीड़ित थे। वहीं दूसरी लहर में ऐसे मरीजों की संख्या 59.7 फीसद थी। 40 फीसद मरीजों को मधुमेह या हाइपरटेंशन की बीमारी थी। 13 फीसद किडनी के मरीज थे। पहली लहर में 63.4 फीसद मरीजों को आक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। वहीं दूसरी लहर में 74.1 फीसद मरीजों को आक्सीजन की जरूरत पड़ी। पहली लहर में 11 फीसद व दूसरी लहर में 28 फीसद मरीजों को बैक्टीरिया या फंगल संक्रमण हुआ था।

कोरोना के 93 नए मामले, 407 मरीज हुए ठीक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर 0.13 फीसद रह गई है। इससे शुक्रवार को 93 नए मामले मिले। वहीं 407 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर अब सिर्फ 1041 रह गई है। वहीं, अस्पतालों में 623 मरीज बचे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के दो मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में कोरोना के अब तक 14 लाख 34 हजार 374 मामले आ चुके हैं। इसमें से 14 लाख आठ हजार 350 मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे मरीजों के ठीक होने की दर 98.18 फीसद है।

एयरपोर्ट पर असुविधाओं को लेकर फिल्म निर्देशक ने किया ट्वीट

जासं, नई दिल्ली : जाने माने तेलुगु फिल्म निर्देशक एसएस राजमौली ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) एयरपोर्ट पर यात्रियों को होने वाली असुविधाओं के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि एयरपोर्ट पर फार्म भरने के लिए टेबल तक की सुविधा नहीं है। एयरपोर्ट पर रिवर्स ट्रांस्क्रिप्शन पालीमरेस चेन रिएक्शन (आरटीपीसीआर) जांच से जुड़े फार्म को भरने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं।

एयरपोर्ट के हैंगर व निकास द्वार पर कुत्तों की मौजूदगी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर इस तरह की असुविधा देखकर किसी विदेशी यात्री के मन में भारत के प्रति अच्छी छवि नहीं बनती होगी। उनके ट्वीट के जवाब में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ट्विटर हैंडल ने कहा कि जहां तक टेबल नहीं होने की बात है तो आरटीपीसीआरफार्म या इससे जुड़े अन्य कार्यों के लिए जो क्षेत्र निर्धारित हैं, वहां पर्याप्त टेबल रखे गए हैं।

इग्नू के ज्योतिष में मास्टर कोर्स के पक्ष में लामबंद हुए देशभर के शिक्षाविद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ शिक्षा मंत्री निशंक को लिखी चिट्ठी, कहा-विरोध करने वाले भारतीय ज्ञान और विज्ञान से परिचित नहीं, बल्कि पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में हाल में शुरू हुए ज्योतिष में मास्टर डिग्री कोर्स को लेकर हो रहे विरोध के खिलाफ अब देशभर के शिक्षाविद भी लामबंद हो गए हैं। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित दूसरे शिक्षण संस्थानों से जुड़े करीब 350 शिक्षाविदों ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग ज्योतिष की पढ़ाई का विरोध कर रहे हैं, वे भारतीय ज्ञान और विज्ञान से परिचित नहीं हैं, बल्कि पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक हैं।

शिक्षाविदों ने इग्नू के प्रोफेसर चंद्र भूषण शर्मा की अगुआई में लिखे इस पत्र में साफ कहा है कि मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्देशों के बाद सभी विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर आधारित कोर्स प्राथमिकता से शुरू किए जा रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी भारतीय ज्ञान आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है। ऐसे में हम सभी विश्वविद्यालयों सहित दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय ज्ञान आधारित कोर्सों को शुरू करने का समर्थन करते हैं। सरकार को भी भारतीय ज्ञान आधारित कोर्सों को शुरू करने की मुहिम को जारी रखना चाहिए।

शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखने वालों में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) आदि से जुड़े शिक्षाविद शामिल हैं। मालूम हो कि देश के कई विश्वविद्यालयों में पहले भी ज्योतिष से जुड़े डिग्री कोर्स शुरू किए थे, लेकिन विरोध के स्वर उठने के बाद इन कोर्सों को बंद कर दिया गया था।

मंदिर परिसर में मीट खाने व शराब पीने का विरोध करने पर युवक की हत्या

जागरण संवाददाता, मुरादनगर

▸ घायल दो लोगों की हालत गंभीर, अज्ञात के खिलाफ पुलिस में तहरीर

▸ मंदिर प्रबंधन ने वारदात को साजिश के तहत अंजाम देने का लगाया आरोप

मंदिर परिसर में गंगनहर के किनारे मीट खाने और शराब पीने का विरोध करना मंदिर के पुजारी व उनके सहयोगियों को भारी पड़ गया। आरोपितों ने लोहे की राड और शराब की बोतल से वार कर एक युवक की हत्या कर दी। घटना में दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद है। मामले में मंदिर के महंत मुकेश गोस्वामी ने अज्ञात के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

मोदीनगर की लंकापुरी कालोनी निवासी विनोद भगतजी गंगनहर की पटरी स्थित घाट पर बने मंदिर में पुजारी हैं। उनके सानिध्य में मेरठ के शोभापुर गांव निवासी प्रवीण व मुरादनगर की कृष्णा कालोनी निवासी देवेंद्र कोहली काफी समय से रह रहे थे और सहयोगी के रूप में काम करते थे। गुरुवार रात करीब दस बजे स्कूटी पर सवार तीन युवक आए और गंगनहर की पटरी स्थित मुख्य शनि मंदिर परिसर में बैठकर शराब पीने लगे। इसके बाद मीट खाने लगे। यह देख प्रवीण और देवेंद्र ने आपत्ति जताई। कहा कि मंदिर परिसर में शराब और मीट का सेवन न करें। आरोप है कि इसी बात से नाराज आरोपितों ने स्कूटी में रखी राड निकालकर उनपर हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर दूसरी ओर से विनोद भगतजी आ गए। उन्होंने बीच-बचाव कराया तो आरोपितों ने उनके सिर पर भी राड मारकर लहूलुहान कर दिया। गहरी चोट लगने से तीनों लोग गिर गए। इसके बावजूद आरोपित शांत नहीं हुए। शराब और बीयर की खाली बोतलें भी आरोपितों ने उनपर दे मारीं। तीनों को अधमरा समझकर आरोपित वहां से चले गए। इसी दौरान एक सेवादार वहां आया और इसकी सूचना मंदिर के महंत मुकेश गोस्वामी को दी।

मुकेश गोस्वामी रात्रि में ही उन्हें लेकर गाजियाबाद के अस्पताल गए। विनोद को गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि प्रवीण व देवेंद्र को दिल्ली रेफर कर दिया गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रवीण को मृत घोषित कर दिया गया। देवेंद्र को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत भी नाजुक बनी हुई है।

मंदिर प्रबंधन ने कुछ लोगों पर वारदात को सोची-समझी साजिश के तहत अंजाम देने का आरोप लगाया है। पूरा मामला मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। मामले में कोई लिखित शिकायत पुलिस को नहीं मिली है। मंदिर के महंत मुकेश गोस्वामी ने बताया कि इस प्रकार की घटना मंदिर परिसर में पहले भी हो चुकी है। कुछ लोग मंदिर में बिना आज्ञा के भी आते रहते हैं।

सूचना देने के बाद भी रोकथाम के लिए पुलिस-प्रशासन से कोई कदम नहीं उठाया जाता। मुकेश गोस्वामी ने बताया कि देवेंद्र पर पूर्व में भी कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था। गोस्वामी ने अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। इस बारे में एसएचओ मुरादनगर हरिओम सिंह का कहना है कि सूचना के आधार पर मामले की छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। आरोपितों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। एसएचओ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत कुछ स्पष्ट होगा।

बस खरीद की निष्पक्ष जांच के लिए सचिवालय के बाहर भाजपा का प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

बस खरीद में अनियमितता का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता इन दिनों सड़क पर उतर रहे हैं। गुरुवार को विधायकों और नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। वहीं, शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को पद से हटाने की मांग की।

भाजयुमो कार्यकर्ता व भाजपा नेता शुक्रवार को राजघाट के पास एकत्रित हुए और वहां से दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सचिवालय की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़कर वे सचिवालय के पास पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें किसी तरह से सचिवालय के बाहर ही रोक लिया।

प्रदर्शनकारियों को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये का बजट होने के बावजूद पिछले कई वर्षों से दिल्ली में बसों की खरीदारी नहीं हुई है। लो फ्लोर बस खरीद में हुई अनियमितता को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की।



डीटीसी बस खरीद घोटाला मामले के विरोध में दिल्ली सचिवालय पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करते भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकते पुलिस कर्मी। ध्रुव कुमार

विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि बस खरीद को लेकर भाजपा विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों का दिल्ली सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को जांच नहीं सौंप रही है। इसकी शिकायत उपराज्यपाल से की गई है। उपराज्यपाल ने जांच के लिए समिति गठित की है। बसों की खरीद पर जितनी राशि खर्च होगी, उससे अधिक राशि उसके रखरखाव पर खर्च करने के लिए करार किया गया है। वारंटी के दौरान रखरखाव की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कंपनी की होती है, लेकिन दिल्ली सरकार इसके लिए 3500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा, प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल और भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष वासु रुखड़ ने बस खरीद प्रक्रिया में अनियमितता की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

चिंताजनक

दिल्ली में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में प्रति शिक्षक 32.7 छात्र हैं, जबकि उससे पीछे सिर्फ बिहार

छात्र-शिक्षक अनुपात में दिल्ली 36वें नंबर पर

रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली

शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बहुत महत्वपूर्ण मापदंड होता है। छात्र गुणवत्तापरक और बेहतर शिक्षा हासिल करें, इसके लिए छात्र-शिक्षक अनुपात का कम होना बहुत जरूरी है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी प्राथमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात के मामले में देश के बाकी राज्यों से पीछे है। स्कूली शिक्षा के लिए वर्ष 2019-20 की संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआइएसई) द्वारा जारी रिपोर्ट में सामने आए हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 37 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में छात्र-शिक्षक अनुपात की रैंकिंग के मामले में दिल्ली 36वें नंबर पर है। उससे पीछे सिर्फ एक राज्य बिहार है। दिल्ली का छात्र-शिक्षक अनुपात 32.7 है, यानि 32.7 छात्रों पर यहां एक शिक्षक है। छात्र-शिक्षक अनुपात की रैंकिंग में सिक्किम पहले स्थान पर है। सिक्किम का छात्र शिक्षक अनुपात 6.7 और बिहार का 55.4 है। उच्च प्राथमिक शिक्षा के मामले में दिल्ली का छात्र-शिक्षक अनुपात 29.3 है, जो सभी राज्यों से पीछे होने के बाद भी मानक के अनुरूप है। इस वर्ग में लद्दाख 4.1 के साथ सबसे बेहतर है, जबकि बिहार का अनुपात 19.4 और उत्तर प्रदेश का 24.4 है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसूची में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित किया गया है। प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात 30 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 है।

शिक्षाविदों के मुताबिक, दिल्ली का खराब छात्र-शिक्षक अनुपात लर्निंग आउटकम (सीखने का परिणाम) और गुणवत्ता में पिछड़ने की एक प्रमुख वजह है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा पर देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआइ) 2019-20 जारी की थी। इसमें लर्निंग आउटकम में दिल्ली की रैंकिंग देशभर में 32वें स्थान पर थी। शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली में अगले साल तक स्कूलों में 18 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्राइमरी शिक्षकों के लगभग 95 फीसद पद भरे हुए हैं। पांच फीसद पद जो खाली हैं, उन्हें साल के अंत तक भरने की योजना है।

सरकारी स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का नामांकन बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी स्कूलों में सत्र 2019-20 में लड़कियों का नामांकन 12,51,936 रहा, जबकि लड़कों का नामांकन कुल 11,57,505 था। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और निजी स्कूलों में स्थिति इसके विपरीत थी।

प्राथमिक स्तर पर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का छात्र-शिक्षक अनुपात (2019-20)

सिक्किम	6.7	केरल	25.9
हिमाचल प्रदेश	15.3	गोवा	27.3
जम्मू कश्मीर	15.4	मध्य प्रदेश	27.5
उत्तराखंड	18.5	दादर और नागर हवेली	27.6
छत्तीसगढ़	19.3	पश्चिम बंगाल	29.5
कर्नाटक	20.9	गुजरात	29.8
राजस्थान	24.8	उत्तर प्रदेश	30.6
चंडीगढ़	25.1	दिल्ली	32.7
पंजाब	25.0	बिहार	55.4
महाराष्ट्र	25.7		

पूर्व विधायक का बेटा हुआ हनीट्रैप का शिकार, मांगे 10 लाख

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

बदरपुर के पूर्व विधायक और आप नेता का बेटा हनीट्रैप का शिकार हुआ है। युवती अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपये मांग रही थी। अब तक तीन बार में युवती 70 हजार रुपये की ठगी भी कर चुकी है। पीड़ित ने इस मामले की बदरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस की साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर बल्लभगढ़ के हैं।

पीड़ित तरुण कुमार अपने परिवार के साथ बदरपुर में रहते हैं। उनके पिता राम सिंह आप नेता हैं और बदरपुर से दो बार विधायक रह चुके हैं। पुलिस को दी शिकायत में तरुण ने बताया है कि उनके पास 30 मार्च की रात इंस्टाग्राम पर एक युवती ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। युवती ने बताया कि उसका नाम पीहू है और वह सुदर्शन पार्क, मीठापुर में रहती है। इसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई और बातें होने लगी। युवती ने तीन अप्रैल को कहा कि उसके पास तरुण की अश्लील फोटो हैं। अगर वह उसे पांच लाख रुपये नहीं देंगे तो वह तस्वीरों को स्वजन को भेज देगी। इससे दबाव में आकर तरुण ने सात अप्रैल को पहले 10 हजार, फिर 40 हजार रुपये उसे पेटीएम कर दिए। 11 अप्रैल को फिर पैसे मांगे तो उसे 20 हजार रुपये और पेटीएम कर दिए। इसके बाद युवती की मांग बढ़ गई और उसने 10 लाख रुपये नहीं देने पर फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। यही नहीं उसने यह भी कहा कि कुछ लोग उसे इन फोटो का एक करोड़ रुपये तक दे सकते हैं। उसकी धमकी से परेशान होकर तरुण ने 30 जून को मामले की शिकायत बदरपुर थाना पुलिस को दी।

1.51 लाख करोड़ रुपये की इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का आयात हुआ है चीन से वित्त वर्ष 2020-21 में। वहीं, इससे पहले के वित्तीय वर्ष में 1.42 लाख करोड़ रुपये का आयात हुआ था।

सरकार और कांग्रेस में तेज हुई टीके पर तकरार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच तीखी सियासी जंग छिड़ गई है। वैक्सीन की कमी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि जुलाई आ गई है, पर वैक्सीन नहीं आई। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन समेत भाजपा ने राहुल पर पलटवार किया। हर्षवर्धन ने कहा कि अहंकार और अज्ञानता के वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं है। कांग्रेस ने हर्षवर्धन पर प्रहार करते हुए उन्हें ट्रोल मंत्री करार दिया।

कोरोना के टीकाकरण की रफ्तार पर सवाल उठाते हुए राहुल ने बेहद संक्षिप्त ट्वीट में कहा, 'जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आयीं।' इस पर हर्षवर्धन ने राहुल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक दिन पहले ही उन्होंने जुलाई में वैक्सीन की उपलब्धता का ब्योरा रखा था। राहुल की समस्या क्या है? क्या वह पढ़ते और समझते नहीं हैं? उन्होंने कांग्रेस को यह सलाह भी दी कि उसे अपने नेतृत्व को पूरी तरह दुरुस्त करने के बारे में विचार करना चाहिए।

भाजपा ने बाकायदा प्रेस कान्फ्रेंस कर राहुल पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल की राजनीतिक परिपक्वता और समझ पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक जुलाई को 41.60 लाख डोज लगाई गई हैं। इसी तरह 62 लाख डोज प्रतिदिन के औसत से 21 जून से एक जुलाई के बीच 6.85 करोड़ टीके लगाए गए हैं।

भाटिया ने कहा कि आंकड़े टीकाकरण की दूसरी कहानी बयान कर रहे हैं जो साफ करते हैं कि सरकार युद्धस्तर पर टीकाकरण को गति दे रही है। आने वाले दिनों में टीकाकरण की रफ्तार और बढ़ेगी। अब तक 34 करोड़ से अधिक डोज देकर भारत ने अमेरिका और कनाडा जैसे देशों को भी टीकाकरण के मामले में पीछे छोड़ दिया है।

भ्रम फैला रहा है विपक्ष : भाटिया ने कांग्रेस शासित राज्यों में टीकाकरण में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल किए। साथ ही यह भी दावा किया कि विपक्ष टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने में जुटा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से लेकर भाजपा आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय समेत सरकार और पार्टी के कई नेताओं ने भी राहुल पर चौतरफा हमला बोला। गोयल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के समय राहुल गांधी को क्षुद्र राजनीति से बचना चाहिए।

कांग्रेस का पलटवार : कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल पर हर्षवर्धन के हमलों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार के मंत्री भूल जाते हैं कि संविधान की शपथ लेकर मंत्रालयों का काम देखने के बजाए वे दो रुपये के ट्रोल आर्मी की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उनका आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार और उसके मंत्री ढंग से काम करते तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बदहाल न होती और बेरोजगारी चरम पर न होती। सुप्रिया ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी में अभी केवल छह करोड़ लोगों को दोनों टीके लगाए गए हैं तो फिर सवाल पूछे जाएंगे हीं।

▸ टीकाकरण पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, जुलाई आ गई, पर वैक्सीन नहीं आई


उठाया सवाल : राहुल गांधी जागरण आर्काइव

▸ हर्षवर्धन का पलटवार, अहंकार और अज्ञानता के वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं


दिया जवाब : डा. हर्षवर्धन। जागरण आर्काइव

कोवैक्सीन करार पर भी सवाल

समाचार एजेंसी प्रेट्र के मुताबिक, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ब्राजील के साथ कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए हुए करार पर भी सवाल उठाए और उसकी जांच की मांग की। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ब्राजील ने फिलहाल इस करार पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के साथ मिलकर कोवैक्सीन को विकसित किया है। इसलिए ब्राजील के आरोपों पर सरकार को भी जवाब देना चाहिए।

राजस्थान और पंजाब के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में भी बढ़ रहा कलह

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

राजस्थान और पंजाब के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में भी राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोला हुआ है। अब हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हुड्डा अभी विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद अपनी समर्थक विधायक गीता भुक्कल को देना चाहते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि तीन प्रमुख राज्यों में नेताओं की आपसी गुटबाजी से पार्टी हाईकमान असहज है।

हुड्डा के समर्थक 19 विधायक गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल से मिल चुके हैं। इन विधायकों के दबाव के चलते बंसल ने अभी प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों की सूची भी रोकने का संकेत दिया है। हालांकि, सूची कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के पास मंजूरी के लिए जा चुकी है। हरियाणा के एक और नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला इस प्रकरण में अभी मौन हैं। वह सोनिया गांधी परिवार के निकट हैं और पार्टी नेतृत्व के लिए उनके संकेत भी महत्वपूर्ण होंगे। हुड्डा समर्थकों का कहना है कि यदि कांग्रेस की कमान हुड्डा जैसे जनाधार वाले जाट नेता के हाथ में नहीं रही तो जाट मतदाता ओमप्रकाश चौटाला के साथ लामबंद हो सकता है और कांग्रेस के लिए निकाय व पंचायत चुनाव जीतने में भी मुश्किल होगी। सैलजा को हटाने की मांग से कहीं यह संदेश न चला जाए कि हुड्डा अनुसूचित जाति विरोधी हैं, इसलिए हुड्डा गुट नेता प्रतिपक्ष पद पर अनुसूचित जाति की विधायक गीता भुक्कल का नाम आगे कर रहा है। हुड्डा के शासनकाल में भुक्कल शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं।


भूपेंद्र सिंह हुड्डा फाइल

ज्यादा प्रभावशाली भी नहीं हुड्डा : भड़ाना

किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सैलजा समर्थक राकेश भड़ाना कहते हैं कि हुड्डा सब्र रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2005 में कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व सीएम भजन लाल के प्रभाव की अनदेखी करते हुए हुड्डा को सीएम बनाया था। 2009 में दोबारा हुड्डा को सीएम बनाया। हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र को सैलजा की जगह राज्यसभा सदस्य बनाया। हुड्डा पहले भी दो बार राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। तब भी पार्टी राज्य में सरकार नहीं बना पाई थी। ऐसे में वह ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहे हैं।

मेरी रगों में दौड़ता है कांग्रेसी खून : सैलजा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि किसी भी विधायक को अपनी पार्टी के प्रदेश प्रभारी से मिलने का हक है। प्रभारी और विधायकों के बीच उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने की बात हुई होगी, इस बारे में न तो प्रभारी का बयान आया और न ही किसी विधायक ने ऐसी कोई बात कही। मैं कांग्रेसी हूं। मेरी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है। हो सकता है कि दूसरों की रगों में कांग्रेसी खून कम हो। मैं अपनी पहचान किसी दलित नेता के रूप में नहीं रखती। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं।


कुमारी सैलजा फाइल

न्यूज गैलरी

बार काउंसिल ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया

पटना : बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआई) की सात सदस्यीय समिति ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट (अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बीसीआइ के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा की रूप-रेखा तैयार कर ली गई है। प्रयास होगा कि संसद से इस विधेयक को जल्द पारित कर लिया जाए। विधेयक की ड्राफ्टिंग में समिति के वरीय अधिवक्ता एस प्रभाकरन, देवी प्रसाद ढल, बीसीआइ के सह अध्यक्ष सुरेश श्रीमाली, सदस्य शैलेंद्र दुबे, प्रशांत कुमार कुमार सिंह, ए रामी रेड्डी, श्रीनाथ त्रिपाठी शामिल थे। ड्राफ्ट में 16 धाराएं बनाई गई हैं। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, किसी अधिवक्ता या उसके परिवार को क्षति पहुंचाने या धमकी देने या दबाव बनाने को अपराध माना जाएगा, जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा छह माह से दो वर्ष तक सजा के साथ 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। (राब्यू)

केंद्र ने सरदार पटेल एकता पुरस्कार के लिए मांगे नामांकन

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 'सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार' के लिए नामांकन या सिफारिशें आमंत्रित की हैं। केंद्र सरकार भारत की एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को यह पुरस्कार प्रदान करती है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और इसकी अंतिम तारीख 15 अगस्त, 2021 है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर नेशनल यूनिटी अवार्ड पर जाकर आवेदन या सिफारिशें की जा सकती हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 'सुभाषचंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022' की खातिर भी नामांकन आमंत्रित किया है। (प्रेट्र)

संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक

नई दिल्ली : संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से आरंभ होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। लोस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, 17वीं लोकसभा का छठा सत्र 19 जुलाई को आरंभ होगा। सत्र का समापन 13 अगस्त को हो सकता है। राज्यसभा के आधिकारिक आदेश में कहा गया है, राष्ट्रपति ने राज्यसभा की बैठक 19 जुलाई को बुलाई है। सत्र का समापन 13 अगस्त को होगा। सत्र का आयोजन कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए होगा और शारीरिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा। (प्रेट्र)

लद्दाख में यथास्थिति बहाल न हुई तो अप्रत्याशित कदम उठा सकता है भारत

दो टूक ▸ सीडीएस जनरल बिपिन रावत की चेतावनी, कहा– हम कदम उठाने के लिए तैयार हैं

बोले, हमने सभी को हमेशा तैयार रहने के लिए कहा है, चीजों को हल्के में न लें

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत और चीन सामान्य तरीके से पूर्वी लद्दाख में पूर्व वाली यथास्थिति बहाल करने में सक्षम हैं। क्षेत्र में शांति और स्थिरता रहे, यह दोनों देशों के हित में है। यह बात तीनों सेनाओं के प्रमुख (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने कही है।

थिंक टैंक के एक कार्यक्रम में जनरल रावत ने कहा, भारत कोई भी अप्रत्याशित कदम उठाने के लिए तैयार है, जैसा कि पूर्वी लद्दाख इलाके में उठाया था। उन्होंने कहा, हमने सभी को हमेशा तैयार रहने के लिए कहा है। चीजों को हल्के में न लें। हम कोई भी अप्रत्याशित कदम उठाने और जवाब देने के लिए तैयार हैं। जैसा हमने भूतकाल में किया है, वैसा हम भविष्य में करने में भी सक्षम हैं। जनरल रावत ने यह बात एक सवाल के जवाब में कही। जाहिर है भूतकाल में उठाए कदम से उनका आशय पैंगोंग लेक के ऊंचाई वाले इलाकों में मई 2020 में रातों-रात सेना की तैनाती थी। इसके बाद घुसपैठ करने वाली चीनी सेना भारतीय सैनिकों के निशाने पर आ गई थी और उसी के बाद चीन के तेवर ढीले पड़ गए थे और वहां से चीनी सैनिकों को वापस अपनी सीमा में लौटना पड़ा था। इस समय डेप्सांग समेत कुछ इलाकों में चीनी सैनिक काबिज हैं और अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहे हैं।

चीन के अवैध कब्जे वाले इलाकों में सामान्य स्थिति की बहाली के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में जनरल रावत ने कहा, दोनों पक्ष राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रखें, समस्या का शांतिपूर्ण निदान निकल आएगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सामान्य तरीके से यथास्थिति बहाल करने का यही एकमात्र तरीका है। अगर पहले वाली यथास्थिति पैदा नहीं होती है तो जाहिर है कि अप्रत्याशित घटनाओं का खतरा बना रहेगा। इसलिए दोनों देशों को समझ लेना चाहिए कि पूर्व वाली स्थिति कायम होना क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। एक अन्य सवाल के जवाब में जनरल रावत ने कहा, चीन अगर पीछे हटने के अपने वचन से मुकरता है तो भारत भी अपने इलाके को वापस पाने के लिए सेना और संसाधन बढ़ाएगा।


सीडीएस जनरल बिपिन रावत जागरण आर्काइव

लक्षद्वीप प्रशासन ने वापस बुलाए अपने शिक्षा कर्मी

कोच्चि, प्रेट्र : एक विवादित कदम के तहत लक्षद्वीप के प्रशासन ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपने कर्मचारियों को कोच्चि से वापस बुलाने का आदेश जारी किया। इसमें कोच्चि में तैनात शिक्षा अधिकारी से कहा गया है कि कर्मचारियों को इस निर्देश के साथ कार्यमुक्त किया जाए कि सात दिनों के भीतर वे लक्षद्वीप में शिक्षा निदेशक को रिपोर्ट करें।

आदेश के मुताबिक, जिन कर्मचारियों को लक्षद्वीप आने का आदेश दिया गया है उनमें एक अकाउंटेंट, एक स्टेनोग्राफर, दो क्लर्क व एक एमएसई शामिल हैं। लक्षद्वीप प्रशासन के शिक्षा निदेशालय ने कोच्चि में अपने शिक्षा अधिकारी को यह निर्देश भी दिया है कि पांचों कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी कार्यालयी सामग्री को भी लक्षद्वीप में शिक्षा निदेशालय में स्थानांतरित किया जाए। बताते चलें कि लक्षद्वीप प्रशासन का कोच्चि में भी एक कार्यालय है जहां कई विभाग कार्यरत है। लक्षद्वीप प्रशासन के इस कदम को गलत बताते हुए वहां से सांसद (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) मुहम्मद फैजल पीपी ने कहा कि यह फैसला द्वीप के उन करीब चार हजार छात्रों पर प्रतिकूल असर डालेगा जो केरल के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं लिहाजा इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप प्रशासन का शिक्षा कार्यालय पिछले तीन दशक से कोच्चि में कार्य कर रहा है। इसको यहां इसलिए स्थापित किया गया था ताकि केरल के शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्रों की जरूरतें आसानी से पूरी की जा सकें। इनमें छात्रवृत्ति, भोजनालय (मेस) शुल्क, छात्रावास शुल्क और अध्यापन (ट्यूशन) शुल्क से जुड़ी जरूरतें शामिल हैं। केरल में पढ़ रहे छात्रों को इनसे जुड़ी परेशानियों के लिए लक्षद्वीप जाना पड़ेगा। फैजल ने आरोप लगाया कि लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने द्वीप के जनप्रतिनिधियों या जिला पंचायत की स्थायी शिक्षा समिति से विचार-विमर्श किए बिना एकपक्षीय फैसला लिया है।

'मंत्री सही नहीं हैं तो पीएम ध्यान रखेंगे, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने चीन के साथ एलएसी पर भारत की आधिकारिक स्थिति के संबंध में बयान देकर शपथ का उल्लंघन किया है। अदालत ने कहा, यदि कोई मंत्री अच्छा नहीं है तो इस पर प्रधानमंत्री को ध्यान देना होगा। अदालतें इस मामले में कुछ नहीं कर सकतीं। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना तथा हृषिकेश रॉय की पीठ ने तमिलनाडु निवासी चंद्रशेखरन रामासामी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। रामासामी खुद को विज्ञानी होने का दावा करते हैं। शुरुआत में पीठ ने कहा, अगर आपको किसी मंत्री का बयान पसंद नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप याचिका दायर करेंगे और उसे हटाने के लिए कहेंगे। पीठ ने कहा, यदि कोई मंत्री अच्छा नहीं है तो यह प्रधानमंत्री को ध्यान रखना है। अदालतें कुछ नहीं कर सकतीं। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि ऐसा लगता है कि आप एक विज्ञानी हैं, तो आपको अपनी ऊर्जा का उपयोग देश की खातिर कुछ करने के लिए करना चाहिए। हम इसे खारिज कर रहे हैं। याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह घोषित करे कि एलएसी पर चीन के साथ गतिरोध मामले में टिप्पणी कर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अपनी शपथ का उल्लंघन किया है।

महाराष्ट्र विधान परिषद के नामांकन के लिए दिशानिर्देश बनाने संबंधी याचिका खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधान परिषद के नामांकन के लिए मापदंड तय करने के राज्यपाल को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं और अदालतें उनके लिए दिशानिर्देश नहीं बना सकतीं।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने कहा कि राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को हटाने के लिए एक अलग तंत्र है और अदालतें दिशानिर्देश नहीं बना सकतीं कि वे कैसे काम करेंगे और विधान परिषद के सदस्यों को नामित करेंगे।

पीठ ने कहा, 'राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं और हम राज्यपालों के लिए दिशानिर्देश नहीं बना सकते कि वे कैसे काम करेंगे।' जब वकील ने इस पर जोर दिया तो पीठ ने कहा, 'आप हमसे संविधान में संशोधन चाहते हैं। माफ कीजिए। याचिका खारिज की जाती है।'

लातूर के एक स्कूल शिक्षक जगन्नाथ शामराव पाटिल ने विशेष क्षेत्रों से विवेकपूर्ण तरीके से राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद के नामांकन के लिए नियम बनाने के दिशानिर्देश देने का अनुरोध करते हुए जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि विशिष्ट नियम या मापदंड नहीं होने के कारण कई योग्य लोग महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्यों के तौर पर अपने नामांकन के लिए नामों पर विचार से वंचित रह जाते हैं।

▸ सुप्रीम कोर्ट ने कहा– मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं राज्यपाल, अदालतें नहीं बना सकतीं उनके लिए दिशानिर्देश


सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। जागरण आर्काइव

दुष्कर्म पीड़िता का नाम लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रसन्नता जताई

▸ छत्तीसगढ़ की एक सत्र अदालत ने अपने फैसले में लिया दुष्कर्म पीड़िता का नाम

▸ सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की ओर से दाखिल याचिका की खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र : छत्तीसगढ़ की एक सत्र अदालत द्वारा अपने फैसले में दुष्कर्म पीड़िता का नाम लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रसन्नता जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसे मामलों से निपटते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह पूरी तरह स्थापित है कि किसी कार्यवाही के दौरान पीड़िता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, हम सत्र न्यायाधीश के फैसले पर अप्रसन्नता जताते हैं, जहां पीड़िता के नाम का उल्लेख किया गया है। पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस विनीत शरण और एमआर शाह शामिल थे। पीठ ने अपने आदेश में कहा, हमारा मानना है कि सभी अधीनस्थ अदालतों को भविष्य में इस प्रकार के मामलों से निपटने के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए।

न्यायालय ने अपने आदेश में यह बात कही और दोषी की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी। याचिका में दुष्कर्म के मामले में उसे दोषी ठहराने के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

पीठ ने कहा, मामले के तथ्य के अनुसार हम इस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहते। याचिका खारिज की जाती है। हाई कोर्ट ने दिसंबर 2019 के अपने फैसले में दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई थी। 2001 में दर्ज मामले में महासमुंद की सत्र अदालत ने व्यक्ति को दोषी करार दिया था।

हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह सहमति से संबंध बनाने का मामला नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 के अपने एक आदेश में कहा था कि दुष्कर्म और यौन प्रताड़ना के पीड़ितों के नाम और उनकी पहचान उजागर नहीं की जा सकती, भले ही उनकी मृत्यु हो चुकी हो।

ईडी ने अटैच की अहमद पटेल के दामाद, डीनो मोरिया की संपत्ति

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद, अभिनेता डीनो मोरिया और संजय खान तथा डीजे अकील की संपत्ति अटैच की है। गुजरात स्थित दवा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक समूह से जुड़े मनी लांड्रिंग के एक मामले में यह कार्रवाई की गई है।

ईडी ने कहा कि मनी लांड्रिंग निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चार लोगों की संपत्ति अटैच करने के शुरुआती आदेश जारी किए गए हैं। संपत्ति की कीमत 8.79 करोड़ रुपये है। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इसमें से खान की अटैच की जाने वाली संपत्ति तीन करोड़ रुपये मूल्य की है। डीनो मोरिया की संपत्ति 1.4 करोड़ रुपये की है और डीजे अकील के नाम से प्रसिद्ध अकील अब्दुलखलील बचूअली की संपत्ति 1.98 करोड़ रुपये की है। पटेल के दामाद इरफान अहमद सिद्दीकी की 2.41 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है। ईडी ने कहा कि स्टर्लिंग बायोटेक समूह के भगोड़े प्रवर्तक नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा ने अपराध से अर्जित धन चारों लोगों को दिया। एजेंसी ने कहा कि नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, चेतन की पत्नी दीप्ति संदेसरा और हितेश पटेल को एक विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।

यादगार होगा आयोजन

दूसरे देशों के 250 से ज्यादा कैडेट एनसीसी के दस्ते में होंगे शामिल, अगले गणतंत्र दिवस के लिए खुली प्रतियोगिता से चुने जाएंगे विदेशी कैडेट

गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनेंगे 25 देशों के कैडेट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अगले साल गणतंत्र दिवस परेड समारोह में एनसीसी अपने कैडेटों की परेड को नया आयाम देगी। इस क्रम में 25 देशों के करीब 250 से अधिक युवा कैडेट गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर राजपथ पर तिरंगे को सलामी देंगे। खास बात यह होगी कि पहली बार इन विदेशी कैडेटों का चयन मेहमान देश की बजाय मेजबान भारत करेगा और इसके लिए बाकायदा वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिता कराई जाएगी।

इतना ही नहीं यह पहला मौका होगा जब इन देशों के प्रतिनिधि भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा होंगे। रक्षा सचिव डा. अजय कुमार ने प्रेस कान्फ्रेंस कर गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए एनसीसी के परेड में किए जा रहे इस बड़े परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड एनसीसी की सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी वाला कार्यक्रम है। अभी तक इसमें आमंत्रित मेहमान देश अपने कैडेट चुनकर भेजता था। इस बार हमने खुली प्रतियोगिता के जरिये इच्छुक कैडेटों के चयन का फैसला किया है। इसके लिए भारतीय दूतावास के सहयोग से उन देशों में भारत की संस्कृति, इतिहास, अर्थव्यवस्था और विकास से जुड़े विषयों पर सवाल पूछे जाएंगे। इसका मकसद साफ तौर पर भारत के बारे में विशेषकर न्यू इंडिया के आयामों से उन्हें रूबरू कराना है।

रक्षा सचिव ने कहा कि अब तक 10 देशों के कैडेट परेड में आते थे, मगर इस बार 25 देशों के कैडेट आएंगे। हर देश से 10 से 12 कैडेट और उनके दो ट्रेनर को चुना जाएगा। चयन प्रक्रिया की शुरुआत जुलाई में होगी और अक्टूबर में कैडेटों का चयन पूरा हो जाएगा। अगले साल 15 जनवरी को विदेशी कैडेट भारत आएंगे और गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के साथ ही कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों व शहरों का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से भी विदेशी कैडेट मिल सकेंगे। डा. अजय कुमार ने कहा कि अगले गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी के 2000 कैडेट शामिल होंगे। कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा। कोविड की चुनौती को देखते हुए सभी कैडेट 18 साल से अधिक की उम्र के होंगे और इन्हें दोनों वैक्सीन लेने की शर्त पूरी करनी होगी। पिछले साल कोविड के चलते केवल 1000 कैडेट ही परेड में शरीक हुए थे। उस बार कोई विदेशी कैडेट शामिल नहीं हो सका था। रक्षा सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल लालकिले से एनसीसी को बार्डर इलाकों में आगे बढ़ाने का सुझाव दिया था, जिस पर अमल हो रहा है। रक्षा मंत्री ने भी एनसीसी की ट्रेनिंग बेहतर करने के लिए एप लांच करने से लेकर कई कदम उठाए हैं।


अहम होगा पल। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

शशि थरूर ने 'पोगोनोट्राफी' शब्द से ट्विटर पर छेड़ी बहस

नई दिल्ली, प्रेट्र : अंग्रेजी के मुश्किल और अप्रचलित शब्दों के उपयोग के लिए मशहूर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को एक बार ट्विटर पर फिर से बहस छेड़ दी जब उन्होंने 'पोगोनोट्राफी' शब्द का उपयोग किया। दरअसल, ट्विटर पर एक महिला यूजर ने कहा कि वह उनसे एक नया शब्द सीखना चाहती है। थरूर ने कहा कि उन्होंने अपने एक मित्र से एक नया शब्द सीखा है पोगोनोट्राफी, जिसका अर्थ दाढ़ी बढ़ाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए इस शब्द का उपयोग किया। थरूर ने ट्वीट किया, 'मेरे मित्र रतिन राय ने मुझे एक नया शब्द सिखाया है : पोगोनोट्राफी। जैसा कि प्रधानमंत्री महामारी के दौरान दाढ़ी बढ़ाते रहे।' उनके इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर इस शब्द को लेकर बहस छिड़ गई।

कह के रहेंगे

माधव जोशी



4 से 6 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। माना जा रहा है कि इस दौरान मंडी संसदीय क्षेत्र व फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय होंगे।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 3 जुलाई, 2021

परिसीमन से बदल जाएगी जम्मू-कश्मीर की सियासी तस्वीर

नवीन नवाज, श्रीनगर

- विधानसभा सीटों की संख्या ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि जम्मू संभाग का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा
- चार दिवसीय दौरे पर छह जुलाई की शाम को जम्मू-कश्मीर पहुंचेगा परिसीमन आयोग

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग का दौरा तय होने के साथ ही प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल परिसीमन में अपने राजनीतिक आधार और वोट बैंक को बचाए रखने की कवायद में जुट गए हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में सिर्फ विधानसभा सीटों की संख्या ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि जम्मू-कश्मीर की सियासी तस्वीर भी बदल जाएगी। विधानसभा में जम्मू संभाग का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। इस बीच, परिसीमन आयोग प्रदेश के छह जुलाई से चार दिवसीय दौरे के दौरान दक्षिण कश्मीर, मध्य कश्मीर, किश्तवाड़ और जम्मू क्षेत्र में प्रदेश के सभी 20 जिला उपायुक्तों से मुलाकात करेगा। इसके अलावा सभी राजनीतिक, सामाजिक और अन्य संगठनों से भी मुलाकात कर उनकी राय ली जाएगी। गत वर्ष फरवरी में गठित इस आयोग का जम्मू-कश्मीर में यह पहला दौरा है।

जम्मू-कश्मीर में अंतिम बार परिसीमन 1995 में हुआ था। पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद जम्मू-कश्मीर राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में पुनर्गठित हुआ है। लद्दाख के अलग होने के बाद जम्मू-कश्मीर में 107 विधानसभा सीटें रह गई हैं। इनमें 24 गुलाम कश्मीर के लिए आरक्षित हैं। 46 कश्मीर व 37 सीटें जम्मू संभाग में हैं। इन सीटों में सिर्फ सात सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं और यह सिर्फ जम्मू संभाग के हिंदू बाहुल्य इलाकों में ही हैं। कश्मीर में एक भी सीट आरक्षित नहीं रही है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए भी कभी कोई सीट आरक्षित नहीं रही है। अनुसूचित जनजाति वर्ग जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी व डोगरा समुदाय के बाद तीसरा बड़ा समुदाय है। इसमें अगर गद्दी वर्ग को भी छोड़ दिया जाए तो सिप्पी, गुज्जर, बक्करवाल जनजातियां पूरी तरह से इस्लाम को मानने वाली हैं।

गुज्जर-बक्करवाल समुदाय के नाम पर बीते 73 साल से कुछ परिवार ही प्रदेश में सियासी ठेकेदारी कर रहे हैं, जो नेकां, पीडीपी और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। परिसीमन की प्रक्रिया में सात सीटों को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है और यह सीटें संभवतः जम्मू संभाग में ही बढ़ेंगी। इस प्रक्रिया के दौरान कश्मीर में सीटों की संख्या भी घट सकती है।

ऐसे बदलेगा सियासी स्वरूप

1. क्षेत्रफल के लिहाज से : परिसीमन की प्रक्रिया अगर पूरी निष्पक्षता से पूरी होती है तो जम्मू-कश्मीर का सियासी स्वरूप ही बदल जाएगा। कारण, जम्मू संभाग का क्षेत्रफल 26,293 वर्ग किलोमीटर है, जबकि कश्मीर का 15,948 वर्ग किलोमीटर।

2-आबादी के हिसाब से: जम्मू संभाग के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या कश्मीर में कई क्षेत्रों से अधिक है। जम्मू जिले के गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में 1.68 लाख और श्रीनगर के बटमालू विधानसभा क्षेत्र में 1.20 लाख मतदाता हैं। यह दोनों जम्मू और कश्मीर संभाग के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र माने जाते हैं। श्रीनगर और जम्मू दो जिलों की तुलना की जाए तो जम्मू के 11 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी ऐसा नहीं है, जिसमें मतदाताओं की संख्या श्रीनगर जिले के आठ विधानसभा क्षेत्रों से कम हो। अगर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आबादी को आधार बनाकर परिसीमन किया जाता है तो श्रीनगर जिले में आठ के बजाय छह और जम्मू में 11 के बजाय 13 विधानसभा सीटें होंगी।

3-भौगोलिक परिस्थितियां और सुविधाओं के आधार पर : परिसीमन में अगर क्षेत्रफल, किसी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों और सड़क व अन्य बुनियादी सुविधाओं को आधार बनाया जाता है तो भी जम्मू संभाग में सीटें बढ़ेंगी। इसके अलावा ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमा भी बदलेगी, जिनका एक हिस्सा किसी दूसरे जिले की तहसील में ही नहीं, बल्कि किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के बीच है। जम्मू में ऐसे कई क्षेत्र हैं और यह वह हैं जहां एक वर्ग विशेष को ही फायदा पहुंचता है। दक्षिण कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी यही स्थिति है

4. अनुसूचित जनजाति : अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए भी करीब 11 सीटें आरक्षित होंगी और अगर यह जनजातीय बहुल आबादी में हुई तो फिर इन वर्गों में एक नया राजनीतिक नेतृत्व भी उभरेगा। इसके अलावा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों का क्रम भी बदलेगा और वह जम्मू के हिंदू बहुल इलाकों के बजाय उन इलाकों में हो सकती हैं, जहां से आज तक कभी किसी अनुसुचित जाति के उम्मीदवार को विधानसभा में बैठने का अवसर नहीं मिला है।

इसलिए कोई गैर मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बन पाया : कश्मीर संभाग में अधिकांश सीटें होना और जम्मू संभाग के सात इलाकों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों को आरक्षित बनाए जाने का फायदा कश्मीर के राजनीतिकों विशेषकर मुस्लिम तुष्टीकरण और कश्मीर केंद्रित सियासत करने वालों को मिला। इसी कारण जम्मू-कश्मीर में कभी भी गैर मुस्लिम सीएम नहीं बन पाया।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद औद्योगिक क्रांति की नई सुबह

ललित कुमार, जम्मू

15,48 करोड़ के निवेश के लिए 15 औद्योगिक इकाइयों को सांबा व कठुआ में जमीन अलाट करने को मंजूरी

जम्मू-कश्मीर की जमीन पर अब औद्योगिक विकास की लकीर उभरने लगी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगभग दो साल में जम्मू-कश्मीर में उद्योग-व्यापार के लिए खुल रहे दरवाजे के भीतर अब निवेशक बेझिझक आने लगे हैं। शुक्रवार का दिन जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्रांति की नई सुबह लेकर आया। इतिहास में पहली बार जम्मू संभाग में 50 से 200 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले 15 औद्योगिक प्रस्तावों को स्वीकृति देते हुए इन इकाइयों के लिए जमीन अलाट करने को मंजूरी दी गई। इनमें एक-दो औद्योगिक इकाइयों को छोड़कर सभी इकाइयां 100 करोड़ व उससे अधिक निवेश कर रही है। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

जम्मू-कश्मीर उद्योग व वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव रंजन पी ठाकुर की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई जमीन आवंटन कमेटी की पहली बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कमेटी की यह पहली बैठक थी। इसमें जम्मू संभाग में निवेश करने के इच्छुक औद्योगिक घरानों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। विभाग की निदेशक अनु मल्होत्रा ने जम्मू संभाग के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 2,447 करोड़ रुपये के निवेश वाले 23 प्रस्तावों को कमेटी के समक्ष रखा। कमेटी ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा करने के बाद 1548 करोड़ के निवेश वाली 15 ऐसी इकाइयों के लिए जमीन अलाटमेंट की मंजूरी दी, जो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे सुरक्षित थीं और जिनमें रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की क्षमता थी।

उम्मीद है कि इन 15 औद्योगिक इकाइयों के लगने से पांच हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। कमेटी ने आठ प्रस्तावों को फिलहाल मंजूरी नहीं दी। इनमें पांच स्टील प्लांट थे, जबकि तीन सीमेंट प्लांट लगाने के प्रस्ताव थे।

चार मिनट अभिभाषण पढ़ने के बाद बाहर निकल गए राज्यपाल

बंगाल विस में हंगामा ▶ अभिभाषण में हिंसा का जिक्र नहीं किए जाने से भाजपा विधायकों ने जताया रोष

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल में ममता बनर्जी की अगुआई में लगातार तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नवगठित 17वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत ही शुक्रवार को जोरदार हंगामे के साथ हुई। विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा के विधायकों के हंगामे के कारण राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपना अभिभाषण भी पूरा नहीं पढ़ पाए और तीन-चार मिनट में ही इसे समाप्त कर वहां से बाहर निकल गए। भाजपा विधायकों ने राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर सदन में हंगामा किया। उनका आरोप था कि राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल को पढ़ने के लिए जो अभिभाषण दिया गया है, उसमें हिंसा के एक शब्द का भी जिक्र नहीं था।

राज्यपाल ने दोपहर दो बजे जैसे ही नवगठित विधानसभा में अपना पहला अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, भाजपा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के आसन के सामने आकर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन के दौरान भाजपा विधायक हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं और पीड़ितों की तस्वीरें भी हाथों में लिए हुए थे। विधानसभा सूत्रों के मुताबिक, भारी शोरगुल के कारण राज्यपाल केवल तीन-चार मिनट ही बोल सके और अपना अभिभाषण पूरी तरह से नहीं पढ़ पाने के बाद उसे सदन के मेज पर रखकर वहां से निकल गए।

राज्यपाल के सदन से बाहर निकलने के दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थीं। राज्यपाल अपनी गाड़ी में बैठ कर विधानसभा परिसर से बाहर निकल गए। इस मौके पर ममता बनर्जी और बिमान बनर्जी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इससे पहले जब अभिभाषण के लिए राज्यपाल विधानसभा परिसर पहुंचे तब उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ममता ने राज्यपाल को गुलदस्ता भी भेंट किया। राजभवन व राज्य सरकार में जारी टकराव के बीच राज्यपाल व ममता ने यहां कुछ देर तक बातचीत भी की। इससे पहले राज्यपाल ने विधानसभा परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहब डा. भीमराव आंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। गौरतलब है कि टकराव के बीच राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा लिखकर दिए गए अभिभाषण को हुबहू नहीं पढ़ने के पहले ही संकेत दिए थे।


कोलकाता में शुक्रवार को नवगठित बंगाल विधानसभा के उद्घाटन सत्र के दौरान राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। प्रेट्र

...तो शायद अभिभाषण के इन बिंदुओं पर था राज्यपाल को एतराज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में नवगठित 17वीं विस के पहले सत्र में राज्यपाल के संबोधन के लिए ममता सरकार की तरफ से तैयार किए गए अभिभाषण में आखिर ऐसा क्या था, जिसे लेकर विवाद गहरा गया था। वैसे तो यह अभिभाषण चौदह पन्ने का है, जिसमें करीब साढ़े दस पन्नों में ममता सरकार ने दस वर्षों के शासनकाल की उपलब्धियों का बखान किया है। करीब पौने दो पेज पर विशिष्ट जनों के निधन पर शोक जताया है और सवा पेज पर किसी का नाम लिए बिना हिंसा के लिए कुछ लोगों, संगठनों को दोषी ठहराने, दुष्प्रचार और राज्य के विभाजन की बातें करने वालों के खिलाफ लिखा गया है। शायद अभिभाषण के इसी सवा पेज पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ऐतराज था और उन्होंने ममता को पत्र लिखकर संशोधन की मांग की थी। हालांकि, आधिकारिक रूप से इस पर न तो राजभवन और न ही राज्य सरकार की ओर से कुछ कहा गया कि आखिर अभिभाषण को लेकर विवाद की वजह क्या थी? जो भी हो भाजपा के विरोध की वजह से राज्यपाल महज चार मिनट ही अभिभाषण पढ़ सके। अभिभाषण के 12 व 13 नंबर पन्नों पर लिखा है- 'बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जितनी भी घटनाएं हुई, उस समय तक राज्य में कानून-व्यवस्था का दायित्व चुनाव आयोग के हाथों में था।

सुवेंदु ने बताया-इसलिए किया प्रदर्शन

विधानसभा सत्र के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि भाजपा विधायक प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि विधायकों के बीच वितरित की गई अभिभाषण की प्रति में चुनाव बाद हुई हिंसा का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि हिंसा को लेकर कोई जिक्र रहता तो भाजपा विपक्षी दल के रूप में अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करती।

आशीष बनर्जी चुने गए डिप्टी स्पीकर

उधर, अभिभाषण के बाद जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर (उपाध्यक्ष) का चुनाव किया गया। बीरभूम जिले के रामपुरहाट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक आशीष बनर्जी को निर्विरोध डिप्टी स्पीकर चुना गया। दरअसल, भाजपा ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था।

टीएमसी ने तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने को पीएम को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने तुषार मेहता को देश के सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन, सुखेंदु शेखर राय और लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा की तरफ से लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा से जुड़े राजनेता एवं विभिन्न आपराधिक मामलों में आरोपित सुवेंदु अधिकारी ने देश के सॉलिसिटर जनरल से उनके निवास पर जाकर बैठक की है। इंटरनेट मीडिया पर प्रमुख हस्तियों ने इस पर सवाल उठाया है। यह बैठक सुवेंदु के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद हुई है। सुवेंदु नारद स्टिंग आपरेशन व सारधा चिटफंड घोटाले में आरोपित हैं, जिनकी सीबीआइ जांच कर रही है। नारद मामले में तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में सीबीआइ की पैरवी कर रहे हैं, वहीं सारधा चिटफंड घोटाले में भी वे सीबीआइ की तरफ से अदालत में पेश हो चुके हैं। पत्र में आगे कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के बाद सॉलिसिटर जनरल देश में द्वितीय सर्वोच्च विधि अधिकारी का पद है, जो भारत सरकार व उसके विभिन्न अंगों को महत्वपूर्ण कानूनी मसलों में परामर्श देता है।

रिहा हुए चौटाला, बोले-सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ करूंगा दौरा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। उन्होंने समर्थकों से कहा कि वह केंद्र की गलत नीतियों के विरोध में सारे देश का दौरा करेंगे और अगले सप्ताह कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को हौसला बढ़ाने धरनास्थलों पर जाएंगे।

शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा पूरी होने के बाद 88 वर्षीय चौटाला शुक्रवार सुबह रिहाई की औपचारिकताएं पूरी करने लगभग 11.15 बजे वकील अमित साहनी के साथ जेल नंबर चार के द्वार पर पहुंचे। अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला दादा को खुद कार ड्राइव कर ले आए। वकील अमित साहनी ने बताया कि जेल प्रशासन की तरफ से प्राप्त रिहाई की ई-मेल के आधार पर उन्होंने रिहाई की औपचारिकता पूरी करने के लिए आवेदन किया था। पैरोल पर चल रहे चौटाला ने पहले जेल अधीक्षक अधवेश्वर कांत के समक्ष सरेंडर किया। इसके बाद जेल अधीक्षक और अतिरिक्त अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने रिहाई की औपचारिकताएं पूरी की। लगभग 45 मिनट तक जेल के अंदर रिहाई की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चौटाला जैसे ही जेल से बाहर निकले, उन्हें उनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के समर्थकों ने घेर लिया। दिल्ली-गुरुग्राम की सीमा पर समर्थकों ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया।

आपदा को अवसर में बदलकर 'मिशन 2022' साधेगी सपा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : नई हवा है...नई सपा है...नारे के साथ समाजवादी पार्टी छवि बदलने की कोशिश में जुट गई है। इसी के तहत पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि कोरोना से निपटने में भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, वहीं, सपा समाज सेवा के लिए समर्पित है। पार्टी ने आपदा को अवसर में बदलकर 'मिशन 2022' की तैयारी भी शुरू कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को समाज सेवा में पूरी तरह जुटने के साथ ही चार सूत्र संपर्क, संवाद, सहयोग व सहायता पर चलने के लिए कहा है।

अब यह लगभग साफ हो गया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव में कोरोना बड़ा मुद्दा रहेगा। इसी नजरिए से समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी भी करेगी। सपा आम जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेताओं व कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे आमजनों की हर संभव मदद करें। गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने के लिए जगह-जगह समाजवादी रसोई चलाई जाएं। अखिलेश ने जरूरतमंदों को राशन वितरण करने के लिए भी कहा है। उन्होंने जनता से सीधे संपर्क व संवाद बनाकर सहयोग व सहायता करने के लिए कहा है।

आठ लाख का बिजली बिल न भरने वाले सिद्धू कैप्टन को दे रहे सलाह

जागरण टीम, चंडीगढ़

- दो जुलाई थी अंतिम तारीख, शाम तक नहीं भरा गया बिल, पंजाब के बिजली संकट पर कांग्रेस सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को महंगी बिजली व कटौती पर सलाह दी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुद सिद्धू पर आठ लाख से अधिक का बिजली का बिल बकाया है। सिद्धू ने शुक्रवार को कैप्टन सरकार को निशाना बनाकर कई ट्वीट किए हैं, लेकिन सिद्धू ने अपनी ही कोठी का 8.67 लाख रुपये का बिजली बिल नहीं भरा है। दो जुलाई को बिल भरने की आखिरी तारीख थी।

नवजोत सिंह सिद्धू विभागीय रिकार्ड के मुताबिक डिफाल्टर चल रहे हैं। पावरकाम के मुताबिक 15 दिसंबर, 2020 को सिद्धू को 15,86,730 रुपये बिल, 18 जनवरी को 16,55,880 रुपये, 18 फरवरी को 17,10,870 रुपये और 19 मार्च को 17,58,800 रुपये बिल जारी हुआ। विभाग के मुताबिक, सिद्धू ने मार्च का बिल जारी होने के बाद 10 लाख रुपये बिजली का बिल जमा करवाया। फिर 20 अप्रैल को उनका 7,89,310 रुपये का बिल और 22 जून को 8,67,540 रुपये बिल जारी हुआ। भुगतान की अंतिम तारीख दो जुलाई को शाम तक इसे जमा नहीं करवाया गया।

नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर खाता नंबर-3002908209 के तहत चल रहा बिजली का कनेक्शन 40-50 किलोवाट के करीब है। पावरकाम के चीफ इंजीनियर सकतर सिंह का कहना है कि बिल समय पर जमा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाती है। इस मामले में जो भी कार्रवाई बनती है, वह की जाएगी।

पंजाब में बिजली संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार से दफ्तरों के समय में बदलाव किया है। एसी चलाने पर पाबंदी लगाई है। उद्योगों पर भी बंदिश लगाई है। इस पर सिद्धू ने नौ ट्वीट करते हुए कहा कि सीएम ने समय रहते सही कदम उठाया होता तो दफ्तरों का समय बदलने व कटौती की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों को 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा सकती थी। कहा कि पंजाब 4.54 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रहा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.85 रुपये प्रति यूनिट है। बादल सरकार ने तीन प्राइवेट प्लांट के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) साइन किए, लेकिन इस एग्रीमेंट में गलत मदों के कारण हम आज तक 5,400 करोड़ रुपये दे चुके हैं। इन पीपीए के कारण सरकार नेशनल ग्रिड से सस्ती बिजली नहीं खरीद पा रही है।

इस्तीफे की बात पर मंत्री सहनी रहे मौन

जागरण टीम, पटना : बिहार में अफसरशाही से आहत होकर गुरुवार को इस्तीफा देने की बात कहने वाले समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी इस प्रकरण पर शुक्रवार को मौन रहे। शनिवार को वे पटना लौटेंगे। उसके बाद ही आगे कोई निर्णय लेंगे। वैसे उन्होंने अपने मन की बात इस तरह बताई कि वे यह चाहते हैं कि विभाग में ऐसे अधिकारी रहें, जो काम करें। बगैर काम के विभाग में रहने वाले अफसरों का क्या मतलब! ऐसे उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकरण पर सरकार के किसी भी स्तर से उनसे कोई बात नहीं हुई है।

मदन सहनी दरभंगा में बहादुरपुर के विधायक हैं। कुशेश्वरस्थान विधायक शशिभूषण हजारी की अंत्येष्टि में शामिल होने वे शुक्रवार को रामपुर रौंता पहुंचे थे। जब वे घर से निकले तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेता उनके साथ थे। उनके व्यवहार से यह कहीं नहीं झलका कि वे संगठन से नाराज हैं।

समाज कल्याण विभाग में तबादले की फाइल का मसला यूं तो अब मुख्य सचिव के स्तर पर सुलझाया जाना है, लेकिन कुछ बातें सार्वजनिक होने लगी हैं। बताया जा रहा कि तबादले की जो सूची थी उसमें दो दर्जन नाम ऐसे थे, जिन्होंने अपने स्थानांतरण के लिए न तो आवेदन दिया था और न ही स्थानांतरण की अवधि के मानक में फिट थे।

संवैधानिक अड़चन के कारण छोड़ना पड़ा पद

प्रथम पृष्ठ से आगे

रामनगर में तीन दिनी चिंतन शिविर के तत्काल बाद भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली तलब कर लिया था। इस तरह अचानक आए बुलावे से राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया। बुधवार दोपहर दिल्ली पहुंचे तीरथ की मध्य रात्रि के आसपास गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। इसके बाद तीरथ अपने दिल्ली स्थित आवास चले गए। उन्हें गुरुवार को लौटना था, लेकिन पार्टी ने उन्हें दिल्ली में ही रुकने को कहा। शुक्रवार दोपहर लगभग एक बजे तीरथ सिंह रावत फिर अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। यहां लगभग आधा घंटे चली मुलाकात के दौरान उन्हें जानकारी दी गई कि उपचुनाव पर निर्वाचन आयोग की रोक के कारण उन्हें पद छोड़ना होगा। इस पर तीरथ ने पार्टी अध्यक्ष को अपने इस्तीफे की पेशकश संबंधी पत्र सौंप दिया।

तीरथ ने पहले ही दे दिए थे पद छोड़ने के संकेत : दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए हालांकि तीरथ ने पद छोड़ने संबंधी सवालों के जवाब तो नहीं दिए, मगर एक बात ऐसी कह गए, जिससे संकेत मिल गए थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह संसद के आगामी सत्र में पूरे समय हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में रहेंगे। दरअसल, तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल सीट का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने लोकसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी। माना जा रहा था कि विधानसभा उप चुनाव का कार्यक्रम तय होते ही वह लोकसभा से इस्तीफा देंगे, लेकिन यह नौबत आई ही नहीं।


नई दिल्ली में शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। एएनआइ

विधायक दल की बैठक में तोमर व पुंडेश्वरी होंगे पर्यवेक्षक : तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद संभालने के छह महीने के अंदर विधानसभा सदस्य बनना था। यह अवधि नौ सितंबर को पूरी हो रही है। उत्तराखंड में वर्तमान में दो विधानसभा सीट रिक्त हैं। इनमें से एक गंगोत्री व दूसरी हल्द्वानी है। गंगोत्री सीट भाजपा विधायक गोपाल रावत के निधन से रिक्त हुई, लिहाजा उनके यहीं से उप चुनाव लड़ने की संभावना थी। अब जबकि तीरथ उप चुनाव न लड़ पाने के कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा चुके हैं, इस स्थिति में लगभग तय है कि भाजपा नया मुख्यमंत्री जिसे भी बनाएगी, वह विधायकों में से ही एक होगा। विधायक दल का नया नेता चुनने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा राष्ट्रीय महामंत्री डी पुंडेश्वरी केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे।

थके-थके से नजर आए तीरथ: तीरथ सिंह रावत लगभग साढ़े सात बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। आठ बजे देहरादून पहंचने पर वह बीजापुर राज्य अतिथि गृह चले गए। उनके कुछ नजदीकी लोग और मुख्य सलाहकार शत्रुघ्न सिंह उनके साथ थे। इस दौरान उनकी भाव-भंगिमा उन हालात को साफ तौर पर बयां कर रही थी, जिनसे उन्हें पिछले तीन दिन गुजरना पड़ा। हमेशा मुस्कराते रहने वाले तीरथ सिंह रावत काफी थके हुए और हताश से दिख रहे थे।

जॉर्ज की वापसी से दिल्ली जाने के दबाव से कमल नाथ को राहत

धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल

- कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्य के मामलों में होगी कमल नाथ की भूमिका
- मुश्किलों का हल निकालेंगे कमल नाथ तो क्रियान्वयन करेंगे विंसेंट जॉर्ज

कांग्रेस हाईकमान के दरबार में विंसेंट जॉर्ज की वापसी से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ को दिल्ली जाने के दबाव से राहत मिली है। वह मध्य प्रदेश में ही रहकर पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय के मसलों पर काम कर सकेंगे। मुश्किलों का हल कमल नाथ निकालेंगे, दिल्ली में इसके क्रियान्वयन का जिम्मा विंसेंट जॉर्ज पर होगा।

गौरतलब है कि विंसेंट जॉर्ज पूर्व में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निजी सचिव रह चुके हैं। एक घोटाले में नाम आने के बाद उनकी राजनीति में सक्रियता कम हो गई थी। वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए भी काम कर चुके हैं। हाल ही में पंजाब कांग्रेस पर आए संकट में उन्होंने ही समन्वय बनाकर मध्यस्थता की कोशिश की थी।

> विंसेंट जॉर्ज नेहरू-गांधी परिवार के न केवल अत्यंत वफादारी साथियों में शुमार रहे हैं, बल्कि समय-समय पर अपनी निष्ठा का अहसास भी कराया है। इसमें दो राय नहीं कि अब जब कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता अहमद पटेल हमारे बीच नहीं रह गए हैं, तो राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर कमल नाथ जी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कमल नाथ का मध्य प्रदेश में रहना जरूरी है, तो वे यहीं रहकर राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे।
>
> 
>
> -केके मिश्रा, महासचिव, मीडिया विभाग, मध्य प्रदेश कांग्रेस

दरअसल, मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद से ही पार्टी में एक खेमा कमल नाथ की दिल्ली वापसी के कयासों को हवा दे रहा था। इस बीच विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव में कमल नाथ ने मोर्चा संभाला, लेकिन महज नौ सीटें हाथ में आने से कांग्रेस की सत्ता वापसी की संभावनाएं भी खत्म हो गईं। इसके चलते नवंबर, 2020 में एक बार फिर कहा जाने लगा कि कमल नाथ की दिल्ली वापसी हो सकती है। इसी बीच 25 नवंबर, 2020 को सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल का निधन हो गया। वह पार्टी में राष्ट्रीय सियासत के साथ समन्वय के मामले भी देखते थे। इसके बाद से ही तय माना जाने लगा कि कमल नाथ को दिल्ली दरबार में ही बैठना होगा।

अचानक बदले समीकरण: पार्टी में केंद्र और राज्य के समीकरणों में उलझे कमल नाथ को अचानक जॉर्ज विंसेंट के आने से काफी राहत मिली है। जॉर्ज नेहरू-गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं। पनडुब्बी घोटाले में नाम आने के चलते उन्होंने सार्वजनिक रूप से गांधी परिवार और कांग्रेस से दूरी बना ली थी। अहमद पटेल के निधन के करीब छह माह बाद उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के दरबार में वापसी की है। हाल ही में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के विरोधी तेवर थामने में भूमिका निभाई। सूत्रों का कहना है कि अब जॉर्ज को राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रिश्ते ठीक करने का जिम्मा सौंपा गया है।

किसके सिर सजेगा ताज, फैसला होगा आज

राज्य ब्यूरो, देहरादून

अटकलों का दौर

- कौन बनेगा उत्तराखंड का 11 वां मुख्यमंत्री, इसे लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर टिकी नजरें
- भाजपा विधायक दल की शनिवार को होगी बैठक

उत्तराखंड की भाजपा सरकार में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की विदाई तय होने के साथ ही सियासी फिजां में अब यह सवाल तैरने लगा है कि अगले आठ माह के लिए यह कांटों भरा ताज किसके सिर सजेगा। मुख्यमंत्री भाजपा विधायकों में से ही होगा या फिर गैर विधायक को भाजपा नेतृत्व जिम्मेदारी सौंपेगा, इसे लेकर भाजपा विधायक दल की शनिवार को होने वाली बैठक पर सभी निगाहें टिकी हैं। हर कोई टकटकी लगाए है कि भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर किसका नाम लेकर आते हैं।

नए मुख्यमंत्री के सामने पिछले चार साल के दौरान की एंटी इनकंबेंसी को अपने सिर लेने के साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 2017 का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती भी होगी। फिलवक्त मुख्यमंत्री पद के लिए राजनीतिक गलियारों में विधायकों के बीच से छह संभावित नाम चर्चा में है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा त्रिवेंद्र और फिर तीरथ मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा.धन सिंह रावत के अलावा कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, विधायक पुष्कर सिंह धामी व ऋतु खंडूड़ी भूषण के नाम शामिल हैं। यह बात अलग है कि इनसे इतर भी कोई अन्य बाजी मार सकता है।

पिछले नेतृत्व परिवर्तन की भांति मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भाजपा हाईकमान अगर इस बार भी चौंकाने पर आया, तो गैर विधायकों पर भी भाजपा दांव खेल सकती है।

सांसदों में से किसी को जिम्मेदारी सौंपने पर यह सूरत बन सकती है कि वे बतौर मुख्यमंत्री छह माह का कार्यकाल पूरा करने से दो माह पहले विधानसभा को भंग कर चुनाव की सिफारिश कर दें। ऐसे में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी, सांसद अजय भट्ट व अजय टम्टा के नामों पर केंद्रीय नेतृत्व विचार कर सकता है।

77 दिन बाद खोला गया मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल राजस्थान के दौसा जिले में है। मंदिर खुलते ही स्थानीय सहित उप्र और दिल्ली से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे।

जासूसी करने घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने भगाया

नाकाम की कोशिश ▶ जम्मू के अरनिया सेक्टर में रेंजरों ने ड्रोन घुसपैठ की कोशिश की, बीएसएफ के जवानों ने डेढ़ दर्जन गोलियां दागीं

जागरण संवाददाता, जम्मू

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र की जासूसी करने के लिए घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों फायरिंग कर वापस भगा दिया। सीमा पार से ड्रोन की यह घुसपैठ ऐसे समय में हुई है जब जम्मू स्थित वायुसेना के टेक्निकल एयरपोर्ट पर ड्रोन धमाके के बाद पूरे जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट है। प्रदेश के भीतरी इलाकों में आम लोगों के पास मौजूद ड्रोन का आंकड़ा जुटाया और प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य मामलों के महानिदेशक (डीजीएमओ) स्तर की बातचीत के बाद संघर्ष विराम समझौते पर फिर अमल के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने एक दो बार गोलाबारी की है, लेकिन नियंत्रण रेखा पर चार माह से शांति बनी हुई है। संघर्ष विराम समझौते पर अमल की इस साल 25 फरवरी को सहमति बनी थी। इसके बाद से पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ पर पूरी तरह अंकुश लग गया है। इससे पाकिस्तान बेचैन है। उस पर आतंकियों की घुसपैठ का दबाव है। इसलिए भारतीय क्षेत्र की रेकी करने के लिए ड्रोन की घुसपैठ कराई है।

पाकिस्तानी रेंजरों ने ड्रोन की यह घुसपैठ जम्मू जिले में अरनिया सेक्टर की जब्बोवाल पोस्ट के पास कराई है। शुक्रवार तड़के करीब सवा चार बजे ड्रोन जैसे ही भारतीय क्षेत्र में घुसा तो बीएसएफ की 42 वाहनी के जवानों ने उसे निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। तकरीबन 20 गोलियां दागी गईं। इसके बाद ड्रोन पाकिस्तानी क्षेत्र में वापस भाग गया। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि यह छोटा क्वाडकापर था, जो अरनिया सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस रहा था।



केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को जम्मू में बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय का दौरा कर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उपकरणों को भी परखा। प्रेट्र

ड्रोन से बम गिराना बहुत गंभीर और खतरनाक : बीएसएफ महानिदेशक

जताई चिंता

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू स्थित वायुसेना के ठिकाने पर ड्रोन से बम गिराने की हालिया घटना 'बहुत गंभीर' और 'बहुत खतरनाक' है। इस चुनौती से निपटने के लिए तुरंत प्रौद्योगिकी विकसित करने की जरूरत है।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के प्रमुख अस्थाना ने कहा कि बल पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश से लगती भारत की करीब 6,300 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा की निगरानी करता है और सुरक्षा के मोर्चे पर उसके समक्ष चार चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ को पाक से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बारूदी सुरंगों का पता लगाने, सीमावर्ती इलाकों में राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रानिक उपकरणों की मौजूदगी का पता लगाने, ड्रोन की समस्या और दूरदराज के इलाके में मोबाइल नेटवर्क की समस्या से निपटना या जूझना पड़ता है।

अस्थाना ने कहा कि ये परिस्थितियां बीएसएफ के अभियान के प्रभाव और सीमा पर बढ़त बनाने की गतिविधियों पर सीधे तौर पर असर डालती हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए तत्काल ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकी विकसित करने की जरूरत है क्योंकि इन ड्रोन का इस्तेमाल मादक पदार्थ तस्करी करने और अहम प्रतिष्ठानों पर हमले में किया जा रहा है। बीएसएफ महानिदेशक ने यह बात बलों के लिए स्टार्टअप और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किफायती और नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी उपाय तलाशने को लेकर आयोजित हैक्थान की शुरुआत करने के दौरान की। इसका आयोजन बीएसएफ हाईटेक अंडरटेकिंग फार मैक्सिमाइजिंग इनोवेशन (भूमि) ने इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर किया है। अस्थाना ने कहा इतिहास में पहली बार ड्रोन के जरिये जम्मू में भारतीय वायुसेना के ठिकाने पर हमला किया गया। यह बहुत गंभीर और खतरनाक है।

जम्मू वायुसेना अड्डे पर ड्रोन हमला आतंकी कार्रवाई : वायुसेना

नई दिल्ली, प्रेट्र : वायु सेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू में वायु सेना के अड्डे पर हुआ ड्रोन हमला एक आतंकी कार्रवाई थी। इस आतंकी हमले का मकसद भारत की प्रमुख सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाना था। उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना सुरक्षा की ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं को और मजबूत बना रही है।

एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारतीय वायु सेना ने ड्रोन और अन्य समान क्षमताओं के राज्येतर तत्वों के हाथ में पड़ने के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया है और इनसे निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। एक थिंक टैंक के साथ बातचीत के सत्र में उन्होंने कहा, जम्मू में जो हुआ वह निश्चित तौर पर आतंकी कार्रवाई थी, जिसकी कोशिश हमारी संपत्तियों को निशाना बनाना था। जाहिर है कि वह प्रयास विफल रहा। संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उल्लेखनीय है रविवार को जम्मू में वायु सेना के अड्डे पर हमला करने के लिए विस्फोटकों से लैस ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया था। भारत में महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान पर हमले के लिए पाक के संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा मानवरहित हवाई यानों (यूएवी-ड्रोन) का इस्तेमाल करने का यह पहला मामला है।

वायु सेना प्रमुख ने कहा कि इस हमले की विस्तृत जांच जारी है। जांच के परिणाम के आने पर सभी तरह के कदम उठाए जाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना ने साफ्ट किल यानी बिना किसी विध्वंस के दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बनाने और ड्रोन रोधी प्रणाली के संबंध में जरूरी प्रणाली को लेकर काफी हद तक विश्लेषण किया है।

जम्मू में 100 से अधिक लोगों को मारने की थी बड़ी साजिश

जागरण संवाददाता, कठुआ

जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू शहर में बड़े पैमाने पर धमाकों की साजिश का पर्दाफाश होने से बड़ा आतंकी हमला टल गया। धमाकों में 100 से अधिक लोगों को मारने की बड़ी साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि अमन के रास्ते में आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में कश्मीर में आतंकरोधी अभियान तेज होंगे। जो राष्ट्र विरोधी तत्व कश्मीरी युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंकी गतिविधियों में धकेलना चाहते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रवार को कठुआ में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में हुए दीक्षांत समारोह के उपरांत डीजीपी पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरहद पर संघर्ष विराम उल्लंघन फिलहाल थम गया है, लेकिन पाक में बैठे लश्कर ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जम्मू कश्मीर में खूनखराबे की नापाक साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि 27 जून को नरवाल क्षेत्र में पकड़ा गया लश्कर के हिट स्क्वाड द रजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के आतंकी नदीम उल हक निवासी बनिहाल ने जम्मू को दहलाने की साजिश रची थी। पुलिस की सतर्कता से बड़ी आतंकी वारदात टल गई। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर धमाके करने

नापाक इरादे

- डीजीपी बोले, सरहद पार लश्कर और जैश खूनखराबे की साजिश रच रहा
- आने वाले दिनों में कश्मीर में आतंकरोधी अभियान तेज होंगे

की साजिश रची गई थी। डीजीपी ने बताया कि इससे पहले ड्रोन से हथियार, आइईडी और मादक पदार्थ गिराने की दर्जन भर से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। इसमें आतंकी गुट लश्कर ए तैयबा का हाथ रहा है। डीजीपी ने कहा कि कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में ड्रोन की घटनाओं में इजाफा हुआ है,जो नई चुनौती है। भविष्य में ड्रोन हमलों और घुसपैठ को रोकने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर रणनीति बनाई जा रही है। सीमा पार आतंकी संगठनों की किसी भी नापाक योजना को असफल बनाने में सुरक्षा बल पीछे नहीं हटेंगे।

ड्रोन हमले में पाकिस्तान की भूमिका अहम : डीजीपी ने दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू में वायु सेना स्टेशन पर ड्रोन से हुए हमले में पाकिस्तान की भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता। हमले में लश्कर ए तैयबा का हाथ हो सकता है। ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा व्यवस्था के लिए बेहद गंभीर खतरा है। महत्वपूर्ण लोगों एवं स्थानों की सुरक्षा की दोबारा समीक्षा करने की जरूरत है।

अकेले ही वाहन तक पहुंचाया पत्नी का शव, किसी ने नहीं की मदद

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

ओडिशा के फुलवाणी मुख्य अस्पताल में एक महिला के शव को उठाने के लिए पति ने लोगों से गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। अंततः वह अपनी पत्नी के शव को अकेले उठाकर शव वाहन तक ले गया। इस दौरान वहां मौजूद चिकित्सक, कर्मचारी एवं अन्य लोग मूकदर्शक बने रहे। घटना प्रकाश में आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। कंधमाल जिला के फिरिंगिया ब्लाक मोतीडिंगआ गांव के बालकृष्ण कहंर ने 29 जून को एनीमिया पीड़ित पत्नी को फुलवाणी मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया था। अगले दिन पत्नी की मौत हो गई। मृत पत्नी को शव वाहन तक ले जाने के लिए

> ड्यूटी पर मौजूद नर्स तथा हेल्पडेस्क कर्मचारी को मदद करनी चाहिए थी। उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन क्यों नहीं किया, इस पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण मिलने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
>
> **- डा. अजय पटनायक, एडीएमओ, फुलवाणी मुख्य अस्पताल, भुवनेश्वर।**

बालकृष्ण ने अस्पताल कर्मियों के अलावा वहां उपस्थित अन्य लोगों से गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। निराश बालकृष्ण वार्ड से सीढ़ी के रास्ते अकेले ही पत्नी के शव को उठाकर नीचे लेकर पहुंचे।

गर्म हवाओं और बारिश के कारकों के अभाव में झुलसा उत्तर भारत

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में शुक्रवार शाम हुई सीमित बारिश की बात छोड़ दी जाए तो उत्तर भारत के अधिकांश इलाके तेज गर्मी में तप रहे हैं। इस असामान्य गर्मी के पीछे पाकिस्तान की ओर चल रही गर्म पछुआ हवाएं और बारिश करने वाली मौसम प्रणाली के अभाव को मुख्य वजह बताया जा रहा है।

देश के सबसे ठंडे स्थानों में एक लद्दाख के द्रास में सर्दियों में कभी-कभी तापमान शून्य से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, वहां इस समय तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

उत्तर भारत के कई हिस्सों में लोगों को लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के गुरुवार को जारी बुलेटिन के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के ऊना में तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से सात डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं सोलन में तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से छह डिग्री अधिक है।



नई दिल्ली में शुक्रवार को दिनभर गर्मी के सितम के बाद शाम को मौसम का मिजाज बदला। प्रेट्र

इसी तरह लद्दाख में नूरबा के थोइस कस्बे का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुलेटिन के अनुसार यहां के स्टाकना में तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस, लेह में 25.7 डिग्री सेल्सियस, कारगिल में 28.5 डिग्री सेल्सियस और बेस कैंप में 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आमतौर पर मानसून से पूर्व के दिनों में लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात कभी-कभी पर्वतीय इलाकों में भी देखने को मिलते हैं। आमतौर पर ठंडे हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक तापमान के बारे में पूछे जाने पर, आइएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि इन क्षेत्रों में लू चलना असामान्य नहीं है। महापात्र ने कहा कि इस क्षेत्र में मानसून पहले से ही कमजोर है। इससे तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, असम और अरुणाचल प्रदेश जून-जुलाई में अपना अधिकतम तापमान दर्ज करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, जम्मू, कश्मीर और लेह क्षेत्रों के आधिकारिक मौसम विज्ञान प्रभारी सोनम लोटस का नजरिया अलग है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के दौरान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान सामान्य बात है। लोटस ने कहा कि इस साल जम्मू में 10 जून को 42.7 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर में 10-11 जून को 34.7 डिग्री सेल्सियस और 8 जून को लेह में 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।

'कृषि कानूनों के विरोध वाले हिस्सों में हों संशोधन'

राज्य ब्यूरो, मुंबई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कृषि कानून पूरी तरह खारिज नहीं किए जा सकते। इनके जिन हिस्सों को लेकर किसानों का विरोध है, सिर्फ उनमें संशोधन किया जा सकता है।

शरद पवार मुंबई स्थित डीवाई पाटिल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के वर्चुअल उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। यह पूछे जाने पर कि क्या महाविकास आघाड़ी सरकार आगामी मानसून सत्र में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव ला सकती है। पवार ने कहा, मुझे नहीं लगता कि सोमवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय मानसून सत्र में यह प्रस्ताव पास किया जा सकता है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे कानून को खारिज करने के बजाय हम उस भाग में संशोधन की मांग कर सकते हैं, जिसे लेकर किसानों को आपत्ति है। लेकिन सभी पार्टियों से बातचीत के बाद ही यह प्रस्ताव लाया जाएगा। पवार के अनुसार, महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रियों की एक उपसमिति केंद्रीय कृषि कानूनों का अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत बंद हो चुकी है। केंद्र को खुद पहल करके किसानों से बातचीत शुरू करनी चाहिए।

प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नेता के खेत से धान उखाड़ा

जासं, बरनाला : कृषि कानूनों का विरोध कर रहे अराजक प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल के खेत में रोपे गए धान को उखाड़ दिया और खेत में ट्रैक्टर चलवा दिया। जिला प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में करने के लिए घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल भेजा, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। धनौला में भाजपा नेता हरजीत ग्रेवाल के खेत को किसान नैब सिंह नब्बी निवासी धनौला ने ठेके पर लिया है और धान की रोपाई की थी। शुक्रवार को धान की रोपाई का पता चला तो कई गांव से संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्ती धान को उखाड़ दिया। भाजपा नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि कैप्टन सरकार की शह पर ही इस तरह की गुंडागर्दी करके आतंकवाद फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौके पर पहुंची पुलिस मूकदर्शक बनी रही व कुछ लोग उनका धान नष्ट करके चले गए। राज्यपाल व पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता से शिकायत की जाएगी।

मुनव्वर राना के बेटे ने खुद पर चलवाई थीं गोलियां

जागरण संवाददाता, रायबरेली

शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना ने ही खुद पर गोलियां चलवाई थीं। उसने संपत्ति विवाद में चाचा और चचेरे भाई को फंसाने और चर्चा में आने के लिए यह साजिश रची। रायबरेली पुलिस ने शूटर समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, तबरेज अभी फरार है। पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने शुक्रवार को पत्रकारवार्ता में बताया कि गत सोमवार शाम रायबरेली में त्रिपुला चौराहे के पास तबरेज राना पर कथित तौर पर हमला हुआ था। गोलियों के निशान कार पर पाए गए। उसने चार चाचा और एक चचेरे भाई के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। पेट्रोल पंप और होटल के सीसी कैमरे व तबरेज के मोबाइल फोन की काल डिटेल चेक से सच्चाई सामने आ गई।

पता चला कि तबरेज 26 जून को रायबरेली आया था और मोटल चौराहे के निकट एक होटल में रुका था। उसने नया पुरवा के अपने करीबी हलीम संग हमले की साजिश रची। ठेकेदार और प्रापर्टी डीलर हलीम को प्रलोभन दिया कि मैं तिलोई से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा तो होर्डिंग्स, बैनर का सारा ठेका दे दूंगा। हमला होने पर सुरक्षा मिल जाएगी। यह भी मंशा थी कि विवादित संपत्ति हासिल करने में अड़ंगेबाजी कर रहे चाचा और चचेरे भाई पर केस दर्ज होने से वे भी पीछे हट जाएंगे। हलीम ने अपने साथी नया पुरवा के सुल्तान अली, भदोखर के उतरपारा निवासी शुभम सरकार और पूरे हंसा के सत्येंद्र त्रिपाठी के साथ मिलकर घटना की।

चालाकी बनी फांस: 28 जून की शाम लगभग 5:45 बजे पूर्व नियोजित साजिश के तहत तबरेज ने अपनी कार पेट्रोल पंप के पास ले जाकर खड़ी कर दी। बाइक पर आए शुभम और सत्येंद्र कार का एक चक्कर घूमे और कार पर फायर करके वापस घर लौट गए।

यह है विवाद की वजह

मुनव्वर राना मूलत: रायबरेली के किला बाजार के रहने वाले हैं। राजघाट पर उनके परिवार की साढ़े आठ बीघा जमीन है। इसमें चार बीघा भाई राफे राना और इस्माइल की है, शेष में छह भाइयों का हिस्सा है, जिसमें मुनव्वर भी शामिल हैं। पिता की मृत्यु के बाद साढ़े चार नहीं, बल्कि साढ़े आठ बीघा जमीन छह भाइयों के नाम वरासत हो गई। इसका न्यायालय में वाद चला रहा है। राना ने पावर आफ अटार्नी तबरेज को दे रखी है। तबरेज ने 18 बिस्वा फरवरी में बेच दी थी, जिसके बाद चाचा लोग विरोध में आ गए थे। इस पर विवाद हुआ था।

न्यूज गैलरी

देशमुख ने सीबीआइ जांच को बताया अवैध

मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने खिलाफ चल रही सीबीआइ जांच को अवैध बताया है। सीबीआइ उनके विरुद्ध पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप की जांच कर रही है। अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज सीबीआइ की एफआइआर रद करने की मांग करते हुए उनके वकील अमित देसाई ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में कहा कि देशमुख के खिलाफ सीबीआइ जांच हाई कोर्ट के ही आदेश पर शुरू हुई थी। लेकिन यह जांच शुरू करने से पहले कानून का पालन नहीं किया गया। उस समय देशमुख सार्वजनिक सेवा में थे। उनके खिलाफ जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति ली जानी चाहिए थी, लेकिन यह अनुमति नहीं ली गई इसलिए यह जांच ही गैरकानूनी है। हम कानून को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देसाई ने जस्टिस एसएस शिंदे और एनएम जमादार की खंडपीठ के सामने भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा-17ए का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस या किसी और जांच एजेंसी को किसी जनसेवक के विरुद्ध जांच शुरू करने से पहले अनुमति लेनी आवश्यक होती है। (राब्यू)

गुरनाम सिंह चढ़ूनी व राकेश टिकैत के खिलाफ प्रदर्शन

गुरुग्राम : भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत एवं भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ शुक्रवार दोपहर गुरुग्राम में सोहना चौक के नजदीक प्रदर्शन किया। दरअसल, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश सचिव व अनुसूचित जाति वर्ग के नेता अमित वाल्मीकि के ऊपर गाजीपुर बार्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों द्वारा हमला किया गया था। इसके विरोध में वाल्मीकि समाज के लोगों ने शुक्रवार को दोनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने एक सुर से कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन रास्ते से भटक चुका है। अमित वाल्मीकि पर हमला इस बात का प्रमाण है। आंदोलन के दौरान कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जो यह प्रमाणित करती हैं कि आंदोलन के नाम पर राजनीति की जा रही है। (जासं)

पर्यावरण प्रेमी संत सीचेवाल को अफसरों ने कराया इंतजार

जालंधर : पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए कामों के कारण जिन संत बलबीर सिंह सीचेवाल के स्वागत के लिए दुनिया इंतजार करती है, उनको जालंधर नगर निगम ने भीषण गर्मी में लंबा इंतजार करवाया। निगम ने उन्हें पौधारोपण अभियान में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया था। जालंधर के काला संघिया ड्रेन में शुक्रवार सुबह 8 बजे मकसूदां में कार्यकम तय हुआ। निगम तैयारी नहीं करवा सका तो कार्यक्रम का समय 9.30 बजे कर दिया गया। संत सीचेवाल अपने डेरा स्थान से साढ़े नौ बजे जालंधर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए लेकिन निगम तैयारी नहीं कर सका। (जासं)

अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और खेल मंत्री की शिकायत

ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में बदलाव की कोशिश को लेकर राज्य के चार राजनीतिक दलों के नेताओं ने केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू तथा मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ यहां पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में इन पर राज्य की सीमा में बदलाव की कोशिश के अलावा कई कानूनों और संविधान का 'जानबूझकर उल्लंघन' करने का आरोप लगाया है। (प्रेट्र)

मंदिर निर्माण सभी रामभक्तों को सुख देने वाला : केशव

अयोध्या : उत्तर प्रदेश उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामनगरी में मंदिर निर्माण सभी रामभक्तों को सुख देने वाला है। उन्होंने कहा, राम वनगमन मार्ग के अलग-अलग स्थानों पर पौराणिक और आध्यात्मिक स्थल श्रद्धालुओं को देखने को मिलेंगे। रामनगरी में मार्ग के चौड़ीकरण से व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। अयोध्या सुंदर और स्वच्छ होगी तो श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होगा। (जासं)

फैसला

बांबे हाई कोर्ट के इस फैसले से बच्चे गोद लेने के इच्छुक परिवारों को मिलेगी राहत

सिर्फ अनाथ नहीं, संबंधियों के बच्चे भी लिए जा सकते हैं गोद

नई दिल्ली, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा है कि सिर्फ अनाथ, छोड़े गए और कानूनी विवाद में फंसे बच्चों को ही गोद नहीं लिया जा सकता बल्कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट संबंधियों के बच्चों को भी गोद लेने की इजाजत देता है।

जस्टिस मनीष पिटाले की एकल पीठ ने अपनी भतीजी को गोद लेने के इच्छुक एक दंपती की याचिका पर बुधवार को यह टिप्पणी की। दंपती बच्ची के मामा-मामी थे और उसके माता-पिता गोद देने के लिए तैयार थे। यवतमाल की जिला अदालत ने इस आधार पर उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि बच्ची अनाथ नहीं है, न ही कानूनी विवाद में फंसी है, न ही उसके माता-पिता ने उसे छोड़ दिया है और न ही उसे देखभाल व संरक्षण की जरूरत है। इस फैसले को दंपती ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

जस्टिस पिटाले ने अपने फैसले में कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता बच्ची के मामा-मामी हैं, लिहाजा वे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत संबंधियों की परिभाषा में आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने निचली अदालत के आदेश को रद करते हुए दंपती के आवेदन पर जल्द से जल्द नए सिरे से विचार करने को कहा।

जेल अपवाद, जमानत देना जज के विवेक पर निर्भर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक केस में जमानत नियम तो जेल अपवाद है। लेकिन जमानत देना अपराध के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए जज के विवेक पर निर्भर करता है। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करके वीडियो वायरल करने के इस मामले में दुराचार के साक्ष्य पर ट्रायल के समय विचार करने का निर्देश दिया और कहा कि यह देखा जाएगा कि पीड़िता के साथ उचित न्याय हो। कोर्ट ने इस मामले में आरोपित रिजवान को जमानत पर रिहा करने से इन्कार करते हुए अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है।

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की कोतवाली में नाबालिग बच्ची के गर्भवती होने पर पांच माह बाद 28 जनवरी,18 को एफआइआर दर्ज कराई गई। यूपी निवासी लड़की ने अपनी मां से उसके साथ हुए दुराचार की घटना बताई, इस पर मुकदमा दर्ज हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में कोई बाहरी चोट नहीं मिलने पर आरोपित रिजवान ने कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा लड़की का बयान और आरोपित की धमकी अपराध की गंभीरता बता रहे हैं। कोर्ट ने कहा इसके आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।

एएमएफ ने जुर्माना लगाने के फैसले को दी चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) स्क्रीनिंग टेस्ट को टालने से इन्कार करते हुए जुर्माना लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई 12 जुलाई को नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। एसोसिएशन आफ एमडी फिजीशियन (एएमएफ) ने 11 जून को एकल पीठ की तरफ से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कुछ टिप्पणी करने को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति अमित बंसल की एकल पीठ ने परीक्षा को एक महीने के लिए टालने से इन्कार करते हुए कहा था कि इस मामले में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पीठ ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद अब मामले कम हो रहे हैं और बेहतर होगा कि तीसरी लहर आने से पहले अगर कुछ और डाक्टर सहयोग करने के लिए आएंगे।

कानूनी शिकंजे के बाद बैकफुट पर देहरादून का वेल्हम ब्वायज स्कूल

जागरण संवाददाता, देहरादून

- हलाल मीट परोसने के लिए टेंडर आमंत्रित करने का मामला
- कैंटीन में मीट की आपूर्ति का पुराना टेंडर रद कर नई प्रक्रिया शुरू करेंगे

हलाल मीट परोसने के लिए टेंडर आमंत्रित करने के मामले में कानूनी शिकंजा कसने के बाद वेल्हम ब्वायज स्कूल प्रबंधन शुक्रवार को बैकफुट पर आ गया। स्कूल प्रबंधन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा.योगेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर बताया कि इसके लिए पूर्व में जारी टेंडर निरस्त कर नए सिरे से टेंडर मांगे जाएंगे। इसमें झटका मीट अथवा हलाल मीट जैसी शर्त नहीं होगी। इस बीच, पुलिस ने मुकदमे की विवेचना भी शुरू कर दी है। बजरंग दल की तहरीर पर बीती रात पुलिस ने स्कूल के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज किया था।

हालिया दिनों में वेल्हम ब्वायज स्कूल प्रबंधन ने कैंटीन में मीट की आपूर्ति के लिए टेंडर जारी किया था। इसमें हलाल मीट आपूर्ति करने की शर्त का उल्लेख था। बजरंग दल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए 29 जून को स्कूल परिसर में धरना-प्रदर्शन किया था। साथ ही, जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री को ज्ञापन भेज कर कार्रवाई की मांग की थी। बजरंग दल की महानगर इकाई का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने मतांतरण की लालसा से स्कूल की कैंटीन में हलाल मीट परोसने के लिए टेंडर जारी किया है। महानगर के विभाग संयोजक विकास वर्मा ने इस संबंध में डालनवाला कोतवाली में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ तहरीर भी दी थी। वीरवार रात मुकदमा दर्ज होने के बाद स्कूल प्रबंधन हरकत में आया। उन्होंने शुक्रवार सुबह एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा।

कोरोना के डेल्टा-बीटा वैरिएंट का मिश्रित रूप है डेल्टा प्लस वैरिएंट

इससे संक्रमितों के इलाज में मोनोकोनल एंटीबाडी काकटेल भी हो रहा फेल, देश में अभी सीमित केस, विशेषज्ञ बोले-वैक्सीन के प्रभाव पर कहना जल्दबाजी

ऋषि दीक्षित, कानपुर

कोरोना वायरस का नया रूप डेल्टा प्लस वैरिएंट अधिक घातक है। यह भारत में डबल म्यूटेंट डेल्टा वैरिएंट और दक्षिण अफ्रीका के बीटा वैरिएंट से मिलकर बना है। देश में इसके अभी सीमित केस ही रिपोर्ट हुए हैं। इनके इलाज में मोनोकोनल एंटी बाडी काकटेल भी फेल साबित हो रहा है। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल जीएसवीएम मेडिकल कालेज के माइक्रोबायोलाजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा.विकास मिश्रा बताते हैं कि चीन से निकलने के बाद कोरोना वायरस लगातार अपने रूप यानी वैरिएंट में बदलाव कर रहा है। वायरस में 1800 से अधिक म्यूटेशन हुए हैं, लेकिन अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा को लेकर देश-विदेश में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयूएचओ) ने अलर्ट जारी किया है। डेल्टा वैरिएंट ने दूसरी लहर में जमकर कहर बरपाया था। हालांकि, वैक्सीन की डोज लेने वालों पर उसका प्रभाव कम है। अब देश में डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दी है। इसको लेकर वैक्सीन के प्रभाव पर कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी।

फेफड़ों के लिए ज्यादा घातक है डेल्टा प्लस वेरिएंट

जासं, ऋषिकेश : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश ने नागरिकों को कोविड नियमों का पालन गंभीरता से सुनिश्चित करने की सलाह दी है। एम्स निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रवि कांत ने कहा कि कोरोना वायरस के अन्य सभी वेरिएंट की तुलना में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से फेफड़ों में कोविड निमोनिया का संक्रमण ज्यादा हो सकता है। यह भी आशंका है कि कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट में एंटीबाडी काकटेल जैसी दवा का भी शत-प्रतिशत असर न हो।

डेल्टा प्लस 60 फीसद तेजी से संक्रमण फैलाता : असिस्टेंट प्रोफेसर विकास बताते हैं, चीन के वुहान में कोरोना वायरस पाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने वायरस के अलग-अलग नाम रखे हैं, जिसमें ब्रिटेन का वैरिएंट अल्फा, दक्षिण अफ्रीका का वैरिएंट बीटा और ब्राजील का वैरिएंट गामा है। तीनों वायरस के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव आया था। विशेषज्ञों के अध्ययन में अल्फा के 18 प्रोटीन, बीटा के आठ प्रोटीन और गामा के 21 प्रोटीन में बदलाव पाया गया। इसलिए देश-विदेश के वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञों के सुझाव पर डब्ल्यूएचओ ने अल्फा, बीटा व गामा को वैरिएंट आफ कंसर्न बताते हुए अलर्ट जारी किया। दूसरी लहर में भारत में अल्फा वायरस डबल म्यूटेंट ने नए वैरिएंट डेल्टा और में अपने को बदल लिया। वायरस के बदले रूप डेल्टा ने ही दूसरी लहर में देश में सर्वाधिक तबाही मचाई थी। अब डेल्टा वायरस ने फिर से अपने को म्यूटेंट करके डेल्टा प्लस वैरिएंट बना लिया है। यह नया वैरिएंट अल्फा और बीटा से मिलकर बना है। डेल्टा में बीटा वैरिएंट का म्यूटेशन पाया गया है, जो इसे और घातक बनाता है।

डेल्टा प्लस इसलिए घातक

- शरीर के अंदर प्रवेश करके रिसेप्टर के माध्यम से फेफड़ों की कोशिकाओं (सेल) में मजबूती से चिपकता है।
- फेफड़ों की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करके खून की धमनियों व सिराओं में थक्के बनाता है।

यह हैं लक्षण

कफ, खांसी, बुखार, डायरिया, पेट से संबंधित समस्याएं, छाती में दर्द, सांस फूलना, त्वचा में लाल चकत्ते पड़ना, अंगुलियों और अंगूठे का रंग बदलना।

ईयू टीका लगवा चुके भारतीयों से बराबरी का व्यवहार करे : भारत

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि यात्रा के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) कोविन टीकाकरण प्रमाणपत्र को पारस्परिक आधार पर मान्यता देगा और इस मुद्दे पर वह समूह के सदस्य देशों के साथ संपर्क में है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं से वर्चुअल बातचीत में कहा कि यूरोपीय संघ ने ईयू डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र की व्यवस्था की है जो टीका लगवाने वाले लोगों की आवाजाही पर छूट के लिए है। उन्होंने कहा कि हमे उम्मीद है कि जिन भारतीयों को घरेलू टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीका लगा है, उन्हें यूरोपीय संघ में टीका लगाने वालों के समतुल्य माना जायेगा और कोविन टीकाकरण प्रमाणपत्र को यूरोपीय संघ पारस्परिक आधार पर मान्यता देगा। बागची ने कहा आपको मालूम है कि कोविन टीकाकरण प्रमाणपत्र की पुष्टि कोविन वेबसाइट पर की जा सकती है। उन्होंने कहा हम यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ पारस्परिक स्वीकार्यता को लेकर सम्पर्क में हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के देशों ने पहले ही इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाया है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सूत्रों ने बताया कि नौ यूरोपीय देशों ने उनके देश में यात्रा के उद्देश्य से कोविशिल्ड टीके को स्वीकार कर लिया है।सूत्रों ने बताया कि इन देशों में आस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवानिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन शामिल हैं जिन्होंने यात्रा के लिए कोविशिल्ड टीका लगाने वाले लोगों को अनुमति दी है।

न्यूज गैलरी

देहरादून से दिल्ली के लिए वाया करनाल बस सेवा शुरू

देहरादून : उत्तर प्रदेश सरकार की हठधर्मिता को दरकिनार कर उत्तराखंड ने देहरादून से दिल्ली रोडवेज बस सेवा शुक्रवार से शुरू कर दी। बस को देहरादून-मेरठ-दिल्ली मार्ग के बजाय वाया पांवटा साहिब-यमुनानगर-करनाल मार्ग से संचालित किया जा रहा। (जासं)

कोविड नियमों की अवहेलना पर बीआरओ को नोटिस

रियासी : रियासी-ज्योतिपुरम मार्ग पर बीआरओ की ओर से बनाए गए माड़ी पुल के उद्घाटन के दौरान कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर उपायुक्त चरणजीत सिंह ने शुक्रवार को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को नोटिस जारी किया है। इस पुल का उद्घाटन रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लेह से वर्चुअल तरीके से किया था। (संस)

गोरखपुर एम्स में शुरू हुआ कोवा-वैक्स का ट्रायल

गोरखपुर : कोवैक्सीन और जायको-डी के बाद अमेरिकी वैक्सीन कोवा-वैक्स का भारत में ट्रायल शुरू हो गया है। देश के जिन 23 संस्थानों में यह परीक्षण हो रहा है, इनमें गोरखपुर का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भी है। क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आरएमआरसी) के साथ मिलकर एम्स गोरखपुर में सौ स्वयंसेवकों पर वैक्सीन का परीक्षण करेगा। (जासं)

दूसरे राज्यों तक पहुंचेगी जांच फर्जीवाड़े की आंच

हरिद्वार : हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच फर्जीवाड़ा मामले में जांच की आंच दूसरे राज्यों पर भी पड़ रही है। जांच एजेंसियों ने जांच तो हरिद्वार में होना दिखाया पर आपसी मिलीभगत का फायदा उठाकर उनका डाटा अन्य राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों से सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया। यह भी पता चला है कि इन एजेंसियों ने स्वयं या फिर से साथी सर्विस प्रोवाइडर की आड़ में कोरोना जांच का काम किया है। जल्द विशेष जांच दल इन राज्यों में जाकर तथ्यों की पड़ताल कर जानकारी जुटाएगा। (जासं)

फर्जी टीकाकरण मामले के मास्टरमाइंड का गार्ड गिरफ्तार

कोलकाता : कोलकाता में फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर मामले में मुख्य आरोपित के एक निजी सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक पकड़े गए लोगों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि कोलकाता पुलिस के विशेष जांच दल ने गुरुवार की रात सुरक्षा गार्ड अरबिंद बैद्य को दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर स्थित उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। वह इस मामले का मास्टरमाइंड व फर्जी आइएएस अधिकारी देबांजन देब का निजी सुरक्षा गार्ड था। देब की कई अवैध गतिविधियों में अरबिंद शामिल था और उसने इसे स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि, उसके बयान में अनेक विसंगतियां पाई गई हैं। गौरतलब है कि शहर में फर्जी टीकाकरण के मामले में देब को गिरफ्तार किया गया था। (राब्यू)

टीकाकरण : गर्भवती महिलाएं भी पात्र

बड़ा कदम ▶ राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिशों पर सरकार ने लगाई मुहर

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में टीकाकरण के लिए पात्र लाभार्थियों की सूची में एक समूह और जुड़ गया है। गर्भवती महिलाएं भी अब टीकाकरण के लिए पात्र हो गई हैं। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएडीआइ) की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी दे ही।

मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के बारे में फैसला लेने का अधिकार मिल गया है। अब वह को-विन प्लेटफार्म पर पंजीकरण करा सकती हैं या सीधे टीकाकरण केंद्र जानकर भी टीके लगवा सकती हैं।

मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले के बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सूचना दे दी गई है ताकि वो इसे अपने मौजूदा राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में लागू कर सकें। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अभी तक गर्भवती महिलाओं को छोड़कर सभी समूहों को कोविड टीकाकरण के लिए पात्र माना गया था। अब दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के दायरे को विस्तार देते हुए इसमें गर्भवती महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया है।

गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित है वैक्सीन : दो दिन पहले ही मंत्रालय ने स्वास्थ्यकर्मियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के महत्व के बारे में बताया था। टीके के चलते ऐसी महिलाओं में कोरोना संक्रमण गंभीर रूप नहीं ले पाता और महिला के साथ ही उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी सुरक्षित रखता है। हाल के कुछ अध्ययनों में भी गर्भवतियों के लिए इसे सुरक्षित बताया गया है।



मां और गर्भसथ शिशु के लिए रक्षा कवच। फाइल फोटो

कोरोना वैक्सीन की 34 करोड़ से ज्यादा लगीं डोज

नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में कोरोना रोधी वैक्सीन की अब तक 34 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 42 लाख से ज्यादा डोज लगाई गईं। 21 जून से शुरू हुए महाभियान के बाद टीकाकरण की गति तेज हुई है। मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण अभियान के 167वें दिन एक जुलाई को 42,64,123 डोज दी गईं। इनमें से 32,80,998 लोगों को पहली और 9,83,125 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। लाभार्थियों में 18-44 वर्ष आयुवर्ग के 24,51,539 लोग पहली और 89,027 लोग दूसरी डोज लेने वालों में शामिल थे। आठ राज्यों-उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 18-44 वर्ष आयुवर्ग के 50 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है।

दो डोज के बाद 98 फीसद घटता है मौत का खतरा

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज महामारी से होने वाली मौत के खतरे को 98 फीसद कम कर देती हैं जबकि एक डोज करीब 92 फीसद बचाव करती है। सरकार ने पंजाब में पुलिसकर्मियों पर किए गए एक अध्ययन का हवाला देते हुए शुक्रवार को यह बात कही।

पुलिसकर्मियों पर यह अध्ययन चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने पंजाब सरकार के साथ मिलकर किया है।

प्रेस कांफ्रेंस में अध्ययन के आंकड़े साझा करते हुए नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डा. वीके पाल ने कहा कि 4,868 पुलिसकर्मियों को टीका नहीं लगा था और उनमें से 15 की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत हो गई, जो प्रति हजार 3.08 मामले हैं।

टीके की पहली डोज ले चुके 35,856 पुलिसकर्मियों में से नौ की मौत हो गई यह आंकड़ा प्रति हजार 0.25 का है। वहीं वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले कुल 42,720 पुलिसकर्मियों में से सिर्फ दो की मौत हुई जो प्रतिहजार 0.05 मामलों के बराबर है।

पाल ने कहा, 'पुलिसकर्मी उच्च जोखिम वाले समूह में आते हैं। इन आंकड़ों से हमनें पाया कि कोरोनारोधी टीके की एक डोज मृत्यु से 92 प्रतिशत सुरक्षा देती है जबकि दोनों डोज 98 प्रतिशत सुरक्षा देती हैं।' उन्होंने कहा, 'ऐसे अध्ययन और उनके नतीजे दर्शाते हैं कि टीकाकरण गंभीर बीमारी और मौत के मामलों को खत्म करता है। इसलिए टीकों पर भरोसा रखिए क्योंकि वे प्रभावी हैं और टीका लगवाया जाना चाहिए।'

जायडस कैडिला की वैक्सीन पर फैसला जल्द : समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक पाल ने कहा कि जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना रोधी वैक्सीन जायकोव-डी के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए भारत के दवा महानियंत्रक के यहां आवेदन किया है। विषय विशेषज्ञ समिति उसके आंकड़ों का मूल्यांकन कर रही है और जल्द ही इस पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है।

सिंगल डोज वैक्सीन के लिए जानसन से बात

एएनआइ के मुताबिक पाल ने कहा कि कोरोना रोधी सिंगल डोज वाली वैक्सीन जानसेन को लेकर अमेरिकी दवा कंपनी जानसन एंड जानसन से बातचीत चल रही है। योजना के मुताबिक इस वैक्सीन का भी हैदराबाद की बायो ई कंपनी उत्पादन करेगी। एक दिन पहले ही कंपनी ने कहा था कि उसकी वैक्सीन कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट समेत अन्य स्ट्रेन के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षा प्रदान करती है।

दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, लापरवाही न बरतें

▶ सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों को सख्ती से लागू रखने की अपील

▶ अभी भी देश भर में प्रतिदिन 40 हजार से ज्यादा मिल रहे हैं मामले

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि अभी कोरोना महामारी की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, इसलिए किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा सकती। सरकार ने टीकाकरण के साथ ही कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया है।

देश में कोरोना महामारी की हालात के बारे में जानकारी देते हुए प्रेस कान्फ्रेंस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि लोगों को वायरस के खिलाफ रोकथाम के उपायों में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। बीते 23-29 जून के हफ्ते में 71 जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 10 फीसद से ज्यादा थी। इसका मतलब है कि दूसरी लहर अभी गई नहीं है।

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वीके पाल ने कहा कि हम तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि पूरा देश सुरक्षित नहीं हो जाता है। इसलिए महामारी से बचाव के उपायों को कम नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस कहीं गया नहीं, बल्कि आसपास ही है और फैल रहा है।

वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 46,617 नए केस मिले हैं और कुल मृतकों की संख्या भी चार लाख को पार कर गई है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि रोजाना नए मामलों से ज्यादा मरीजों के ठीक होने का सिलसिला पिछले 50 दिनों से बना हुआ है। सक्रिय मामलों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है और मौजूदा समय में सक्रिय मामले पांच लाख के करीब आ गए हैं।



लव अग्रवाल। फाइल फोटो

शुक्रवार सुबह आठ बजे तक कोरोना की स्थिति

नए मामले	46,617
कुल मामले	3,04,58,251
मौतें	853
कुल मौतें	4,00,312
कुल सक्रिय मामले	5,09,637
ठीक होने की दर	97.01 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.48 फीसद
मृत्यु दर	1.31 फीसद
जांचें (गुरुवार)	18,80,026
कुल जांचें	41,42,51,520

पति का शव नहीं मिला तो पुतला बनाकर किया अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, हापुड़

15 हजार न देने पर अस्पताल से नहीं मिला कोरोना संक्रमित का शव

सिस्टम की लापरवाही और मर चुकी संवेदनाओं के चलते कोरोना संक्रमित की लाश को ढाई माह तक चिता नसीब नहीं हो सकी। मृतक की पत्नी ने गांव में पुतला बनाकर अंतिम संस्कार कर दिया था। उसे अस्पताल में 15 हजार रुपये जमा न करने पर पति का शव नहीं मिल पाया था। अब 75 दिन बाद उसे पता चला कि पति की लाश उप्र के हापुड़ के अस्पताल की मर्चरी में रखी हुई है। पुलिस-प्रशासन की सूचना पर बस्ती से हापुड़ लौटी पत्नी ने एक संस्था और चिकित्सकों की मदद से पति के शव का अंतिम संस्कार करवाया। अब प्रशासन अपनी कारगुजारियों पर पर्दा डालने के लिए पीड़ित विधवा और उसके बच्चों की मदद में जुट गया है। इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है।

मूलरूप से जनपद बस्ती के गांव नाथपुर निवासी नरेश हापुड़ में देहात थाना क्षेत्र के मोहल्ला पन्नापुरी में पत्नी गुड़िया, पुत्री काजल, काव्या व एक अनिकेत के साथ किराये के मकान में रहते थे। अप्रैल माह में नरेश को बीमार होने पर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 14 अप्रैल को उनमें कोरोना की पुष्टि हुई। हालत बिगड़ने पर 15 अप्रैल को उन्हें मेरठ मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया गया था। 16 अप्रैल, 2021 को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

नरेश के बड़े भाई विजय ने बताया कि अस्पताल ने नरेश का शव देने की एवज में उससे 15 हजार रुपये मांगे थे। मजबूर होकर गुड़िया जनपद बस्ती स्थित अपने गांव नाथपुर पहुंच गई, जहां नरेश का पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार कर रीति-रिवाज के कार्य किए।

रथयात्रा : पुरी में धर्मशाला व होटल होंगे सील

जागरण टीम, भुवनेश्वर

महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की 12 जुलाई को प्रस्तावित विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुरी जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधीश समर्थ वर्मा ने एहतियात के तौर पर होटल, लाज, धर्मशाला आदि को सील करने का निर्देश दिया है। पुरी शहर के अंदर मौजूद तमाम होटल, लाज एवं धर्मशाला में रथयात्रा के दौरान एक भी पर्यटक या भक्त नहीं रुक सकता है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस बीच, रथयात्रा के लिए तीनों रथ के निर्माण का कार्य लगभग खत्म हो गया है। आठ से 10 जुलाई तक रथयात्रा से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्री जगन्नाथ जी की सेवा में जुटे सेवकों की कोरोना जांच कराई जाएगी। सिंहद्वार एवं गुंडिचा मंदिर के बीच पांच जगहों पर अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया।

सरकार के खिलाफ याचिकाकर्ता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

चारधाम यात्रा

किशोर जोशी, नैनीताल

उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, वहीं, नैनीताल निवासी याचिकाकर्ता अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल 29 जून को ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुके हैं। उन्होंने सर्वोच्च अदालत से सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई की स्थिति में उनका पक्ष भी सुनने का अनुरोध किया है। इससे अब यह कानूनी लड़ाई रोमांचक हो गई है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चारधाम यात्रा शुरू करने के राज्य कैबिनेट के निर्णय पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है।

कोरोना की पहली लहर में जमकर हुआ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल

कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया के समक्ष अप्रत्याशित स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया है। यह ऐसा संकट है, जिसमें अभी तक इलाज और बचाव को लेकर कोई मानक व्यवस्था नहीं खोजी जा सकी है। बचाव के लिए टीका एकमात्र विकल्प है। वहीं इलाज के लिए मरीज और संक्रमण की स्थिति के हिसाब से दवाएं तय होती हैं। इन अनिश्चित परिस्थितियों में कई लोग अधूरी जानकारियों का भी शिकार हुए। अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोध में भी ऐसी ही एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसमें पाया गया है कि कोरोना की पहली लहर के दौरान भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का जमकर इस्तेमाल हुआ, जबकि ये दवाएं केवल बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण पर कारगर होती हैं, कोविड-19 जैसे वायरस वाले संक्रमण पर नहीं।



21 करोड़ ज्यादा डोज की खपत

भारत में जून से सितंबर, 2020 के बीच पहली लहर पीक पर थी। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि इस अवधि में एंटीबायोटिक्स की 21.6 करोड़ अतिरिक्त खुराक ली गई। एजिथ्रोमाइसिन की 3.8 करोड़ ज्यादा डोज लिए जाने का अनुमान है।



तीन साल की दवा बिक्री के आंकड़ों का किया गया विश्लेषण

अध्ययन के दौरान जनवरी, 2018 से दिसंबर, 2020 के दौरान भारत में निजी क्षेत्रों में बिकी सभी एंटीबायोटिक दवाओं के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। 2020 में भारत में एंटीबायोटिक्स की 16.29 अरब खुराक बिकी। यह 2018 और 2019 से थोड़ा सा कम है। हालांकि, आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले इसलिए हैं, क्योंकि 2020 में कोरोना के कारण लगे लाकडाउन के चलते लोग घरों में थे। कहीं आना-जाना नहीं हो रहा था। मलेरिया और चिकुनगुनिया जैसे संक्रमण के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। ऐसे में एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल में भी कमी आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं, अमेरिका और अन्य अमीर देशों में 2020 में एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई।

बड़ा हो सकता है खतरा

एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल केवल किसी दवा के उपयोग या दुरुपयोग का मामला नहीं है, बल्कि यह व्यापक स्तर पर बड़े खतरे की वजह बन सकता है। पूरी दुनिया में इन रजिस्टेंट संक्रमण विज्ञानियों के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। एंटीबायोटिक्स का बेतहाशा इस्तेमाल ऐसे संक्रमण का कारण बनता है। ज्यादा इस्तेमाल से सामान्य चोट और न्यूमोनिया जैसे सामान्य संक्रमण पर भी दवा का असर कम हो जाता है और ये संक्रमण जानलेवा बन जाते हैं।

इनपुट : प्रेट्र जागरण इन्फो

शोध

आइआइटी के विज्ञानियों ने पेप्टाइड के जरिए अमेरिकी दवा नटामाइसिन को बनाया प्रभावी, पहले के मुकाबले पांच गुना हुआ असरकारी, खरगोश और चूहे पर सफल प्रयोग

आंखों के फंगस के इलाज का कारगर तरीका ढूंढा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ कुसुम स्कूल आफ बायोलाजिकल साइंस की प्रोफेसर अर्चना चुग व इनकी पीएचडी छात्राएं डा आस्था जैन, हर्षा रोहिरा, सुजित्रा शंकर

▶ कार्निया स्पेशलिस्ट डा सुष्मिता जी शाह- डा सीएम शाह, मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली की महिला विज्ञानियों ने आंखों के फंगस संक्रमण के इलाज का कारगर तरीका ढूंढा है। विज्ञानियों ने अमेरिकी दवा नटामाइसिन को पेप्टाइड के साथ मिलाकर प्रयोग किया। जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। इससे अमेरिकी दवा की एंटी फंगल क्षमता और बढ़ जाएगी।

भारत में संक्रमण ज्यादा

आइआइटी दिल्ली के कुसुम स्कूल आफ बायोलाजिकल साइंस की प्रोफेसर अर्चना चुग ने बताया कि भारत की बड़ी आबादी कृषि संबंधी कार्यों पर निर्भर है। खेतों में काम करने के दौरान अक्सर पत्तों से आंखों पर हल्की चोट लग जाती है। कई बार आंखों में धूल चले जाने पर रगड़ होती है। चूंकि ये तत्काल हानि नहीं पहुंचाते इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन रगड़ या चोट से कई बार कार्निया की ऊपरी परत छिल जाती है। इससे फंगस संक्रमण कार्निया में पहुंच जाता है। संक्रमण के शुरुआती लक्षण तो नहीं दिखते लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है काली पुतली के अंदर सफेद एवं बाद में लाल धब्बे दिखने लगते हैं। इससे धुंधला दिखता है या फिर दिखाई देना बंद ही हो जाता है। इसे फंगल केराटाइसिस भी कहते हैं। फंगल केराटाइसिस गंभीर होने पर बाजार में उपलब्ध दवाएं बहुत कारगर साबित नहीं होती। अमेरिकी-फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) द्वारा प्रमाणित नटामाइसिन को फंगल केराटाइसिस के इलाज में प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह दवा पर्याप्त मात्रा में आंखों में प्रवेश नहीं कर पाती। जिसकी चलते इसकी बूंदें बेकार हो जाती हैं।

दवा बनी प्रभावी : प्रोफेसर अर्चना चुग ने बताया कि नैनोटेक्नोलाजी का प्रयोग कर लैब में एक पेप्टाइड तैयार किया गया। पेप्टाइड प्रोटीन का ही हिस्सा होता है। इसे नटामाइसिन के साथ मिलाया गया। इस पेप्टाइड की खासियत है कि यह कोशिकाओं के अंदर खुद तो जाता ही है साथ में मालिक्यूल्स को भी लेकर जाता है। इस तरह जब पेप्टाइड और नटामाइसिन को मिलाकर प्रयोग किया। विज्ञानियों ने इसे खरगोश और चूहे पर प्रयोग किया।



आंखें बचने की उम्मीद। फाइल फोटो

स्टेरायड के इस्तेमाल पर एकमत नहीं डाक्टर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

59.1 फीसद डाक्टरों ने मरीजों को दीं ज्यादा क्षमता की स्टेरायड दवाएं

7.29 फीसद डाक्टरों ने संक्रमण होने पर बहुत जल्दी शुरू कर दी थीं स्टेरायड दवाएं

मैक्स अस्पताल की तरफ से किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि कोरोना के इलाज में स्टोरायड का इस्तेमाल कब, कितनी डोज और अधिकतम कितने दिन तक करना चाहिए, ताकि मरीज पर गंभीर दुष्प्रभाव न हो इसको लेकर डाक्टरों की सोच में एकरूपता नहीं है। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 7.29 फीसद डाक्टरों ने कोरोना के इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को शुरुआती दौर में ही स्टेरायड दवा देना शुरू कर दिया था। यह सर्वे मेडिकल जर्नल जेएपीआइ (जर्नल आफ दी एसोसिएशन आफ फिजिशियन आफ इंडिया) में प्रकाशित हुआ है।

सर्वे में कहा गया है कि स्टेरायड के इस्तेमाल से शुगर बढ़ने व दूसरे तरह के घातक संक्रमण होने का दुष्प्रभाव अधिक देखा गया। मैक्स अस्पताल के डाक्टरों ने 23 राज्यों के 384 डाक्टरों पर यह सर्वे किया है, जिसमें दिल्ली से सबसे अधिक 80 डाक्टरों ने सर्वे में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश से 38 व हरियाणा के 31 डाक्टरों ने हिस्सा लिया था। इनमें से ज्यादातर वरिष्ठ डाक्टर थे। सर्वे में पाया गया कि ज्यादातर डाक्टर मानते हैं कि स्टेरायड मध्यम व गंभीर संक्रमण से पीड़ित मरीजों को देने पर अधिक फायदा होता है। वहीं, आठ फीसद डाक्टर मानते हैं कि हल्के संक्रमण वाले मरीजों को भी यह दवा दी जा सकती है। 9.89 फीसद डाक्टरों ने हर तरह के मरीजों को यह दवा दी। 7.29 फीसद डाक्टरों ने बहुत जल्दी दवा शुरू कर दी थी। 36.2 फीसद डाक्टरों की तरफ से अधिक क्षमता की दवा देने का कारण आक्सीजन का स्तर कम होना व 22.9 फीसद डाक्टरों की अधिक पावर की दवा देने का कारण मरीज के खून में इंफ्लेमेटरी मार्कर सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन) का स्तर बढ़ना था। 74.48 फीसद डाक्टरों ने मध्यम श्रेणी के मरीजों में ही स्टेरायड का इस्तेमाल किया। वहीं, 60.94 फीसद डाक्टरों ने गंभीर मरीजों में भी यह दवा दी। करीब 66 फीसद डाक्टर मरीज के ठीक होने तक स्टेरायड की डोज चालू रखना चाहते हैं। 34 फीसद डाक्टरों ने मरीजों को 14 दिन से अधिक समय तक स्टेरायड की डोज दी। मैक्स अस्पताल के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के एसोसिएट निदेशक डा. देवेन जुनेजा के नेतृत्व में यह सर्वे हुआ। उन्होंने कहा कि स्टेरायड कोरोना के इलाज में फायदेमंद पाई गई है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर सोच अलग-अलग है।

एनपीपीए ने तीन दवाओं के दाम 50 फीसद बढ़ाए

नई दिल्ली : देशभर में दवाओं के दाम निर्धारित करने वाली नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने कार्बामाजेपाइन, रेनिटिडाइन और आइबुप्रोफेन के नौ फॉर्मुलेशंस के दाम में एक बार 50 फीसद बढ़ोतरी को अनुमोदन दे दिया है। एनपीपीए के आदेश में कहा गया है कि देशभर में सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत सबसे शुरुआत में इन्हीं दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इनके दाम में बढ़ोतरी को अनुमोदन दिया गया है। (प्रेट्र)

देश-विदेश में रसायनों की मांग धीरे-धीरे सुधर रही है। चालू वित्त वर्ष में इसके कोरोना-पूर्व के स्तर पर पहुंच जाने की उम्मीद है।
– एन. चंद्रशेखरन, चेयरमैन, टाटा केमिकल्स



सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
52,484.67	15,722.20	₹ 46,615	₹68,458	₹74.74	$ 75.79
▲ 166.07	▲ 42.20	▲ ₹251	▼ ₹256	▲ ₹0.19	

'काउंसिल ही पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएगी'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की पहल जीएसटी काउंसिल को ही करनी होगी। पेट्रोलियम ईंधन को दायरे में लाने के लिए जीएसटी के नियमों में संशोधन की जरूरत नहीं है। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दाम को देखते हुए इन्हें जीएसटी दायरे में शामिल करने की मांग उठा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय पहले ही इसकी सिफारिश कर चुका है।

कर्नाटक के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में फिलहाल कटौती नहीं होने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल पर केंद्र और राज्य दोनों ही शुल्क लेते हैं। केंद्र का शुल्क निर्धारित होता है जबकि राज्य का शुल्क पेट्रोल और डीजल के दाम से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है।

पहली तिमाही में रिकॉर्ड निर्यात

अप्रैल-जून, 2021 में 92 अरब डॉलर के साथ आंकड़ा अब तक के शीर्ष पर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2021) में रिकॉर्ड तिमाही निर्यात किया गया। इस वर्ष अप्रैल-जून में वस्तुओं का निर्यात 95.36 अरब डॉलर का रहा जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 85.36 फीसद और वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि से 17.85 फीसद अधिक है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में 82 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। इससे पहले पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की आखिरी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2021) में 90 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था जो उस वक्त तक का तिमाही रिकॉर्ड था।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वस्तुओं का आयात 126.14 अरब डॉलर का रहा जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 107.99 फीसद अधिक है। लेकिन वर्ष 2019 के अप्रैल-जून के मुकाबले यह आयात 3.05 फीसद कम है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इस वर्ष जून में 32.46 अरब डॉलर का निर्यात किया गया जो पिछले वर्ष जून के मुकाबले 47.34 फीसद तो वर्ष 2019 के जून की तुलना में 29.7 फीसद अधिक है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में मंत्रालय ने वस्तुओं के निर्यात को रिकॉर्ड 400 अरब डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब तक किसी वित्त वर्ष में अधिकतम 330 अरब डॉलर का निर्यात किया गया है। इस वर्ष जून में 41.86 अरब डॉलर का आयात किया गया जो पिछले वर्ष जून के मुकाबले 96.33 फीसद अधिक है। वर्ष 2019 जून के मुकाबले इस वर्ष जून में 2.03 फीसद अधिक का आयात किया गया।

गोयल ने बताया कि निर्यातकों के लिए जल्द ही रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स (रोडटेप) स्कीम की विस्तृत घोषणा की जाएगी। रोडटेप को मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम(एमईआइएस) की जगह लागू किया जा रहा है। रोडटेप में पूरी तरह से टैक्स का रिफंड होगा और इसके तहत निर्यातकों को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा अक्टूबर तक हो सकती है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इसमें थोड़ा विलंब हुआ है। गोयल ने बताया कि सिंगल प्रोडक्ट वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अब मल्टी प्रोडक्ट्स सेज के रूप में काम कर सकते हैं। इन केंद्रों से तैयार उत्पाद को घरेलू स्तर पर बिक्री की इजाजत के लिए टैक्स संबंधित मामलों पर राजस्व विभाग से बात चल रही है जिस पर जल्द ही फैसला होने की उम्मीद है।

अप्रैल-जून, 2019 की तुलना में इस वर्ष इसी तिमाही की स्थिति

वस्तु	वृद्धि (फीसद)
लौह अयस्क	168
चावल	37
इंजीनियरिंग उत्पाद	25
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद	17
समुद्री उत्पाद	16
ड्रग एवं फार्मा	14
पेट्रोलियम उत्पाद	16
केमिकल्स	20

स्रोत : वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय



- कोरोना पूर्व काल से 18 फीसद, पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 85 फीसद बढ़ा
- निर्यात को चालू वित्त वर्ष में 400 अरब डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य

ई-कॉमर्स में एफडीआइ पर जल्द स्थिति स्पष्ट करेगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) नियमों को लेकर स्थिति जल्द स्पष्ट करेगी। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दो-टूक कहा कि ई-कॉमर्स में एफडीआइ पर सरकार नीतियों में कोई बदलाव नहीं करने वाली है, क्योंकि ये नियम शीशे की तरह साफ हैं।

घरेलू कारोबारियों का एक बड़ा वर्ग ई-कॉमर्स कंपनियों पर एफडीआइ नियमों के लगातार उल्लंघन का आरोप लगाता रहा है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि हम ई-कॉमर्स नीति और उससे जुड़े स्पष्टीकरण जल्द लाएंगे। हमारे संज्ञान में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें नीतियों का अक्षरशः और मनोयोग से पालन नहीं हुआ है। सरकार निश्चित रूप से ऐसे मामलों से संबंधित स्पष्टीकरण जल्द लाएगी।

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को देश के कानूनों का पालन करना ही होगा। उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनियों को स्पष्ट चेताया था कि वे भारतीय ग्राहकों के हितों से खिलवाड़ करने के लिए धनबल या रुतबे के इस्तेमाल से बाज आएं।

उन्होंने शुक्रवार को कहा कि यह उपभोक्ता मामलों, एफडीआइ नीति और ई-कॉमर्स नीति का मिलाजुला मामला है और इस पर स्थिति जल्द स्पष्ट की जाएगी।



पीयूष गोयल की दो टूक- एफडीआइ के नियम शीशे की तरह साफ ● फाइल फोटो

वाणिज्य व उद्योग मंत्री ने कहा- ई-कॉमर्स में एफडीआइ पर सरकार नीतियों में कोई बदलाव नहीं करने वाली है

इन्फ्रा परियोजनाओं की हुई समीक्षा: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने करीब 2.7 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश वाली 20 महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़े 59 मुद्दों की समीक्षा की। इस बारे में शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए लंबित मुद्दों के जल्द समाधान के निर्देश दिए और उनकी समय सीमा निर्धारित की।

बयान के मुताबिक जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई, उनमें पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (एकेआइसी) शामिल हैं। गोयल ने इन्फ्रा परियोजनाओं की नियमित बहुस्तरीय निगरानी पर भी जोर दिया, जो देश में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सरकार ने दालों के भंडारण पर लगाई स्टॉक लिमिट

नई दिल्ली, प्रेट्र : दालों की बढ़ती महंगाई और जमाखोरी को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से इनकी भंडारण सीमा निर्धारित कर दी है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि थोक व्यापारी 200 टन और खुदरा व्यापारी पांच टन से अधिक किसी भी एक दाल का भंडारण नहीं करेंगे। मिलों के लिए यह सीमा पिछले तीन महीनों के उत्पादन या उनकी कुल स्थापित क्षमता के 25 फीसद (जो भी अधिक हो) से ज्यादा नहीं होगी। मूंग दाल को इन सभी सीमाओं से बाहर रखा गया है। यह सीमा इस वर्ष 31 अक्टूबर तक के लिए है।

आयातकों के लिए मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष 15 मई से पहले आयात किए गए स्टॉक पर उनकी भंडारण सीमा थोक कारोबारियों जितनी ही होगी। अगर आयात 15 मई के बाद किया है तो स्टॉक लिमिट की बाध्यता कस्टम क्लीयरेंस मिलने की तिथि के 45 दिनों बाद से लागू होगी।

मंत्रालय ने इन सभी पक्षों से कहा है कि अगर उनके पास सीमा से अधिक स्टॉक है तो वे उपभोक्ता मामलों के विभाग पर इसकी लिखित जानकारी दें। साथ ही वे अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर स्टॉक को सीमा के अंदर लाएं। इस वर्ष मार्च और अप्रैल के दौरान दालों की कीमत में तेज उछाल दर्ज किया गया है। इसे रोकने के लिए तत्कालीन नीति की जरूरत थी।

200 टन से अधिक कोई एक दाल नहीं रख सकेंगे थोक व्यापारी

05 टन सीमा रखी गई है खुदरा व्यापारियों के लिए

'एक जिला-एक उत्पाद' योजना के लिए 707 जिलों के प्रस्ताव मंजूर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों को 'एक जिला-एक उत्पाद' के लिए अनुमोदित किया है। इसके लिए 17 राज्यों में 50 से अधिक इंक्यूबेशन केंद्रों की मंजूरी भी दी गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में एक वर्ष के भीतर छोटी इकाइयों की स्थापना की दिशा में कई उल्लेखनीय पहल की गई है। योजना के तहत शुरू की जाने वाली सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय व तकनीकी मदद भी मुहैया कराई जा रही है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना को बढ़ावा देने को ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से प्रयास किया है। इसके लिए साझा कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राज्य आजीविका मिशन और ग्रामीण आजीविका मिशन के नेटवर्क का सहयोग लिया जा रहा है।

इस योजना में कार्यशील पूंजी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य द्वारा छोटे उपकरणों की खरीद को वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है। इस दौरान 9,000 से अधिक छोटे उद्यमियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से 2,500 ने सरकारी मदद से कार्य भी शुरू कर दिया। योजना के तहत कर्नाटक, उप्र, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, मप्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड समेत 17 राज्यों में 54 कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। नए उद्यमियों की मदद को 491 जिलों में विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। डेढ़ दर्जन राज्यों में 470 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों को भी रखा गया है। योजना में प्रत्येक उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग को सहकारी संस्था नैफेड और ट्राइफेड सहयोग करेंगी। कृषि व बागवानी उत्पादों में अनानास, बाजरा आधारित उत्पाद, धनिया, मखाना, शहद, रागी, बेकरी, इसबगोल, हल्दी और चेरी की ब्रांडिंग व मार्केटिंग नैफेड करेगी। ट्राइफेड ने इमली, मसाले, आंवला, दालें, अनाज, कस्टर्ड सेब, जंगली मशरूम, काला चावल व जंगली सेब के उत्पादों का चयन किया है।

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को दी जाएगी मदद, ग्रामीण व शहरी विकास मंत्रालयों संग खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय करेगा काम

विदेशी मुद्रा भंडार 609 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंचा

मुंबई, प्रेट्र : देश का विदेशी मुद्रा भंडार 25 जून को खत्म सप्ताह में 5.066 अरब डॉलर बढ़कर रिकॉर्ड 608.999 अरब डॉलर पर जा पहुंचा। उससे पहले 18 जून को खत्म सप्ताह के दौरान यह 4.148 अरब डॉलर घटकर 603.933 अरब डॉलर रह गया था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) में बड़े उछाल का फायदा विदेशी मुद्रा के सकल भंडार पर दिखा।

आरबीआइ द्वारा दी जानकारी के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) में 4.7 अरब डॉलर का उछाल दर्ज किया गया। इससे एफसीए का मूल्य 566.24 अरब डॉलर पर पहुंच गया। एफसीए में डॉलर समेत यूरो, पाउंड और येन जैसी मुद्राओं को भी शामिल किया जाता है। इनके मूल्य की गणना भी डॉलर के भाव में ही की जाती है।

डिजिटल मार्केटप्लेस बना एमएसएमई का सहारा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन में डिजिटल मार्केटप्लेस छोटे और मझोले कारोबारियों यानी एमएसएमई की आमदनी बरकरार रखने का मंच बनकर उभरे हैं। सप्लाई चेन की चुनौतियों और नकदी की कमी से उपजे संकट का सामना करने में छोटे कारोबारियों को डिजिटल मार्केटप्लेस ने नई राह दिखाई है। लॉकडाउन के बाद फ्लिपकार्ट होलसेल ने छोटे कारोबारियों को विक्रेता के तौर पर अपने साथ जोड़ने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई हैं। इनमें आसान कर्ज, उत्पादों की विस्तृत रेंज, ऑर्डर वापस करने तथा सरल ऑर्डर ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं प्रमुख हैं।

फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक लॉकडाउन में लगी पाबंदियों की वजह से छोटे खुदरा कारोबारियों की आमदनी में 40% तक की कमी आई है। ई-कॉमर्स कंपनियों की इस मुहिम ने उनके विक्रेताओं की संख्या को तेज रफ्तार से बढ़ाया है। गाजियाबाद (उप्र) निवासी कई सरकारी विभागों में काम कर चुकीं सपना को डिजिटल मार्केटप्लेस से जुड़ने के बाद सहूलियत मिल रही है। उन्होंने फैशन कारोबार शुरू कर आसपास की कई महिलाओं को रोजगार दिया।

एसेंचर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटलीकरण समग्र रिटेल इकोसिस्टम के लिए फायदे का सौदा है और इससे कारोबार कठिन समय में भी टिके रह सकेंगे। इसी तरह केपीएमजी की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन ने ग्राहकों के व्यवहार को भी तेजी से बदला है। अब 50-75 वर्ष आयुवर्ग के ग्राहक भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। यह वर्ग पहले डिजिटल मार्केटप्लेस से दूर रहता था।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

ट्विटर एमडी के खिलाफ पटना में मुकदमा दायर

पटना : भारत का गलत नक्शा साइट पर दिखाने के मामले में ट्विटर के खिलाफ अब पटना की अदालत में मुकदमा दायर किया गया है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी सुरेश रूंगटा ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी के खिलाफ चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। रूंगटा का कहना है कि पिछले साल 12 नवंबर को ट्विटर ने देश के नक्शे से छेड़छाड़ करते हुए लद्दाख को भारत के हिस्से से हटाकर चीन में दिखा दिया था। भारत सरकार की आपत्ति पर इसे ठीक किया गया। ट्विटर ने भारत सरकार से लिखित में माफी मांगी थी। इसके बावजूद बीते दिनों फिर जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को भारत के नक्शे से हटाकर एक अलग देश के रूप में दिखाया। (राब्यू)

इसरो विज्ञानी के बेटे का जला हुआ शव बरामद

चेन्नई : आइआइटी मद्रास के एक अस्थायी कर्मचारी उन्नीकृष्णन नायर का जला हुआ शव पिछली रात संस्थान के हाकी ग्राउंड से बरामद हुआ। नायर के पिता रेघु इसरो के वरिष्ठ विज्ञानी हैं। उनका घर केरल के एर्नाकुलम में है। नायर के आवास से एक सूसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने खुद के अवसाद में होने की बात कही है। (आइएएनएस)

जमानत के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में जमानत नहीं

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में मिली जमानत के आधार पर गैंगस्टर एक्ट केस में जमानत नहीं दी जा सकती। कहा वाहन चोरी गैंग के सदस्य को जमानत दी तो आगे भी अपराध दोहरा सकता है। याची का लंबा आपराधिक इतिहास है। (जासं)

रोज वैली कंपनी, गौतम कुंडू के खिलाफ पूरक आरोपपत्र

नई दिल्ली : त्रिपुरा में पोंजी घोटाला मामले में सीबीआइ ने रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इसके अध्यक्ष गौतम कुंडू व अन्य के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। कंपनी ने जमीन की बुकिंग पर लाभ का लालच देकर 31 करोड़ रुपये से ज्यादा धन इकट्ठा किया है। (प्रेट्र)

अजीत पवार व उनकी पत्नी ईडी के निशाने पर

दाल में काला

राज्य ब्यूरो, मुंबई

गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त की गई जरंडेश्वर चीनी मिल के मामले में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार एवं उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी अब ईडी के निशाने पर हैं। लेकिन अजीत पवार ने अपने परिवार पर लग रहे आरोपों का खंडन किया है। उधर शिवसेना नेता संजय राउत अजीत पवार के बचाव में उतर आए हैं।

ईडी इन दिनों महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में हुए घोटाले की जांच कर रही है। इसी के तहत गुरुवार को जब्त की गई जरंडेश्वर चीनी मिल से अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के संबंध जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ईडी को पता चला है कि जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रा.लि.में ज्यादा बड़ी अंशधारिता मेसर्स स्पार्कलिंग स्वायल प्रा.लि. की है, जिससे अजीत पवार एवं उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का सीधा संबंध जुड़ता दिखाई दे रहा है।

जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रा.लि. ने ही 2010 में जरंडेश्वर सहकारी शुगर कारखाना खरीदा था। जबकि उस समय अजीत पवार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के निदेशकों में से एक थे। आरोप है कि इसी बैंक से बड़ा लोन लेकर राज्य की कई सहकारी चीनी मिलें जानबूझकर नेताओं द्वारा डुबाई गईं। बाद में उन्हें कुछ नेताओं या उनके करीबियों द्वारा ही खरीद लिया गया। सहकारी बैंकों से लोन लेकर सहकारी चीनी मिल डुबाने और फिर उसे किसी नेता के करीबी द्वारा खरीदी गई चीनी मिलों में से एक जरंडेश्वर चीनी मिल भी रही है। जरंडेश्वर सहकारी शुगर कारखाना के नाम पर केंद्रीय कोआपरेटिव बैंक से 700 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था।

ईडी ने फेमा मामले में पूछताछ के लिए यामी गौतम को तलब किया

नई दिल्ली,प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सात जुलाई को तलब किया है। सूत्रों ने बताया कि उन्हें पहले भी तलब किया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुई थीं। यह मामला एक बैंक खाते में जमा 1.5 करोड़ रुपये के लेन-देन से जुड़ा है। यामी गौतम ने कुछ तमिल और तेलुगु फिल्मों के अलावा कई हिंदी फिल्मों में काम किया है।

बंगाल में ईडी ने जब्त किया केआइडीसीएल का होटल

राब्यू, रांची : अलकतरा (कोलतार) घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रांची की टीम ने कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (केआइडीसीएल) के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट में कार्रवाई की है। शुक्रवार को ईडी ने बंगाल के झाड़ग्राम में कौशल्या हेरिटेज होटल को जब्त किया। होटल की कीमत 1.08 करोड़ रुपये बताई गई है। मामले की जांच में पता चला कि केआइडीसीएल नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), टाटानगर की 59 रसीद जमा कीं जिसमें केवल 33 रसीद ही सही पाई गईं।

वसूली की महाभारत नहीं, भर्तियों में शुचिता नए उप्र की पहचान : योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि एक बड़ी फौज की ओर से की गई अदालती अड़ंगेबाजी और रुकावटों के बावजूद राज्य सरकार अपने सवा चार वर्षों के कार्यकाल में युवाओं को पारदर्शिता व शुचिता के साथ सवा चार लाख सरकारी नौकरियां देने में सफल रही है। इनमें से डेढ़ लाख नौकरियां तो पुलिस विभाग में दी गई हैं। उप्र सरकार के प्रयासों से प्रदेश में हुए निवेश की बदौलत एक करोड़ से ज्यादा नौजवान निजी क्षेत्र में रोजगार पाने में कामयाब हुए हैं। 2017 के पहले जिस उप्र में भर्तियां भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और वसूली की 'पारिवारिक महाभारत' की भेंट चढ़ जाती थीं, वहां सवा चार लाख पदों पर हुई नियुक्तियों में से एक पर भी सवाल नहीं किया जा सकता है। यह नई कार्यसंस्कृति, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की है। यहां भ्रष्टाचार की जगह नहीं, प्रतिभा का सम्मान है। योगी उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उप्र में एक लाख और भर्तियों की ओर बढ़ी सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को पांच साल में पांच लाख सरकारी नौकरियां देने के अपने वादे को अमली जामा पहनाने में शिद्दत से जुटे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार नौजवानों को एक लाख और सरकारी नौकरियां देने के लिए कमर कस रही है। राज्य सरकार की सेवाओं में भविष्य में विज्ञापित होने वाले समूह 'ग' के लगभग 30 हजार पदों पर भर्तियों का रास्ता तेजी से खोलने के लिए उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 20 अगस्त को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) कराने की तैयारी है। शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर भर्ती से जुड़े आयोगों व बोर्ड के अध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारी भर्ती प्रक्रियाओं को दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है।

योगी सरकार अपने सवा चार साल के कार्यकाल में सवा चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दे चुकी है। कोरोना महामारी के कारण सरकारी सेवाओं में भर्तियों में बाधा आई थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पाने के बाद सरकार फिर मिशन रोजगार को रफ्तार देने में जुट गई है। सरकार की मंशा है कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले वह ज्यादा से ज्यादा भर्तियां कराकर युवाओं का दिल जीत सके। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में भर्ती से जुड़े आयोगों और बोर्ड के अध्यक्षों ने उन्हें अपनी संस्थाओं के भर्ती कार्यक्रमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों की ओर से प्राप्त हुए भर्ती प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।

मिशन रोजगार

- मुख्यमंत्री योगी का सभी भर्ती प्रक्रियाओं को दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश
- समूह 'ग' के पदों पर भर्तियों के लिए 20 अगस्त को अर्हता परीक्षा की तैयारी

सांवले रंग के चलते बांग्ला अभिनेत्री से गाली-गलौज, पुलिस में शिकायत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बांग्ला टीवी सीरियल की अभिनेत्री श्रुति दास को इंटरनेट मीडिया पर सिर्फ इसलिए भला-बुरा कहा जा रहा है, क्योंकि वह सांवली हैं। इससे परेशान होकर उन्होंने अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

श्रुति दास को बांग्ला टीवी सीरियलों में ब्रेक मिलने के बाद से ही उनके सांवले रंग के लिए अभद्र टिप्पणियां की जा रहीं थीं। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने वाली टॉलिवुड की संभवतः वह पहली महिला अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने रंग को लेकर हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ आधिकारिक रूप से कार्रवाई की मांग की है। बांग्ला सीरियल 'देशेर माटी' में मुख्य भूमिका 'नूह' का किरदार निभाने वाली दास का कहना है कि साल 2019 में उन्हें ब्रेक मिला था, जिसके बाद से ही उनके साथ इंटरनेट मीडिया पर गाली-गलौज शुरू हो गई थी और जैसे-जैसे सीरियल लोकप्रिय होता गया तो यह सब और बढ़ने लगा। दास का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर ट्रोल करने वाले मुझपर लगातार निशाना साधते हुए यह आरोप लगा रहे हैं कि मैंने इस रोल के लिए अपने पार्टनर से धूर्तता की है, जोकि एक निर्देशक भी है। ट्रोल करने वालों का कहना है कि मेरे जैसी सांवली लड़की के लिए ये रोल मिलना बेहद मुश्किल होता। गुरुवार को उन्होंने अपने पोस्ट में कोलकाता पुलिस को टैग किया। इसके बाद उन्होंने लिखा कि मुझसे कहा गया कि मैं साइबर पुलिस स्टेशन में मेल करके अपनी शिकायत दर्ज करूं। मैंने ऐसा ही किया।

- श्रुति दास को बांग्ला टीवी सीरियल में ब्रेक मिलने के बाद से ही इंटरनेट मीडिया पर कहा जा रहा था भला-बुरा



रंगभेद की शिकार श्रुति दास। फाइल फोटो

खनन से गहरे खेत में फंसा मासूम, चिलचिलाती धूप में दम तोड़ा

जागरण संवाददाता, जसवंतनगर (इटावा) : दो साल का कन्हैया घर पर माता-पिता को न देखकर करीब ढाई सौ मीटर दूर खेत की तरफ जाने को निकला। रास्ते में मिट्टी खनन की वजह से गहरे हुए खेत में गिरकर फंस गया। चार घंटे तक वह कड़ी धूप के बीच निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन न तो उसकी चीखें बाहर तक आ सकीं और न ही वह खुद। मासूम की मौत से स्वजन में चीख-पुकार मच गई।

मासूम कन्हैया की मौत का यह वाकया इटावा जिले के ग्राम अजनौरा का है। यहां के धर्मेंद्र कठेरिया पल्लेदारी करने के अलावा कुछ खेत बटाई पर लेते हैं। उन्होंने इस बार करीब तीन बीघा खेत बटाई पर लिया था। शुक्रवार को वह फसल की देखभाल के लिए पत्नी के साथ खेत पर गए थे। घर पर उनका दो साल का बेटा कन्हैया अपने भाई-बहन के साथ खेल रहा था। जब उसको माता-पिता की याद आई तो वह उन्हें ढूंढ़ते हुए खेतों की ओर निकल गया।

एनआइए ने उप्र के शामली से दो लोगों को गिरफ्तार किया

दरभंगा विस्फोट प्रकरण

जागरण संवाददाता, शामली

17 जून को बिहार के दरभंगा रेलवे जंक्शन पर हुए पार्सल विस्फोट प्रकरण में शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने उप्र के शामली जिले के कैराना कस्बे से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय से पांच दिन का ट्रांजिट रिमांड मिलने पर एनआइए दोनों को अपने साथ पटना ले गई।

दरभंगा रेलवे जंक्शन पर जिस पार्सल में विस्फोट हुआ था। उस पर शामली जिले के एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिखा था। 24 जून को एनआइए ने दिल्ली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान एनआइए ने हैदराबाद से कैराना कस्बा निवासी दो सगे भाई नासिर व इमरान पुत्र मूसा खान को 30 जून को गिरफ्तार कर लिया। जांच में दोनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य पाए गए। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्होंने अपने संगठन के लोगों की मदद से विस्फोट को अंजाम दिया था। दोनों भाइयों ने कैराना के मोहल्ला आलखुर्द निवासी सलीम अहमद उर्फ हाजी सलीम उर्फ टुइयां पुत्र यासीन व कफील अहमद पुत्र शकील के नाम बताए थे। शुक्रवार दोपहर एनआइए के डिप्टी एसपी आरके पांडेय के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम ने कैराना कोतवाली में सलीम व कफील को बुलाकर पूछताछ की। इसके बाद एनआइए ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और ट्रांजिट रिमांड लेकर कोर्ट में पेश किया।

एनआइए ने मदद मांगी थी। शुक्रवार को शामली पुलिस ने दरभंगा विस्फोट की घटना से जुड़े हाजी सलीम व कफील निवासी कैराना को एनआइए को सौंप दिया। इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई एनआइए द्वारा की जाएगी। – सुकीर्ति माधव, एसपी, शामली

चंद्रशेखर आजाद पार्क में निर्माण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क से कब्र और मजार के कृत्रिम निर्माण के मामले में कोर्ट के आदेश के पालन के संदर्भ में दो सप्ताह में नगर निगम से जवाब मांगा है। यह आदेश पार्क में मजार और कब्र के कृत्रिम निर्माण को लेकर जितेंद्र सिंह बिसेन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद की खंडपीठ ने दिया है। न्यायालय ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता को इस अवधि में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम समुदाय चंद्रशेखर आजाद पार्क में कृत्रिम कब्र और मजार बना रहा है, जबकि 1987 में हाई कोर्ट ने आजाद पार्क में किसी तरह का निर्माण नहीं करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने आदेश के संदर्भ में जानकारी मांगी तो नगर निगम के अधिवक्ता ने अरुण कुमार ने दो सप्ताह का समय मांगा।

दैनिक जागरण

मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है

बेनकाब बंगाल सरकार

कलकत्ता उच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को चुनाव बाद हिंसा की सभी शिकायतों को प्राथमिकी के रूप में दर्ज करने का आदेश देकर ममता सरकार के इस झूठ की पोल खोल दी कि उनके राज्य में कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला यह भी बताता है कि बंगाल पुलिस ने पीड़ितों की शिकायतों को सुनने से इन्कार किया। देश के राजनीतिक इतिहास में यह शायद पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने अपने ही लोगों के दमन, उत्पीड़न और पलायन का संज्ञान लेने से इन्कार करने के साथ यह झूठ भी फैलाया हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह अच्छा है कि कुछ देर से सही, ममता सरकार हिंसा की इन भयानक घटनाओं पर पर्दा डालने की जो बेशर्म कोशिश कर रही थी, उसमें नाकाम भी हुई और बेनकाब भी। सबसे शर्मनाक यह रहा कि बंगाल पुलिस भी ममता सरकार के झूठ का साथ देती हुई नजर आई। बंगाल पुलिस के अधिकारियों को इससे लज्जित होना चाहिए कि उन्होंने हिंसा पीड़ित लोगों की मदद करने के बजाय उनकी उपेक्षा की। वास्तव में उन्होंने बिलकुल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार किया। जिस राज्य की पुलिस सत्तारूढ़ दल के दास की तरह व्यवहार करे, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।

इसमें संदेह है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बंगाल पुलिस अपने दायित्वों को लेकर सजग होगी। आखिर जिस पुलिस ने अपने सामने हो रही हिंसा से मुंह मोड़ा हो, उससे यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह उच्च न्यायालय के आदेश पर अपना कर्तव्य पालन सही तरह करेगी? उचित होगा कि उच्च न्यायालय चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं की पुलिस जांच की निगरानी खुद करे। और भी उचित यह होगा कि वह इन घटनाओं की जांच के लिए किसी विशेष जांच दल का गठन करे। यदि वह यह काम नहीं करता तो फिर सर्वोच्च न्यायालय को इस दिशा में पहल करनी चाहिए, क्योंकि बंगाल में चुनाव बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने राजनीतिक विरोधियों के उत्पीड़न और दमन का जो घिनौना अभियान छेड़ा, वह राज्य के माथे पर कलंक से कम नहीं। इस दौरान लोगों को मौत के घाट उतारा गया और घरों-दुकानों में आगजनी के साथ दुष्कर्म भी किए गए। यदि चुनाव बाद हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों और उन्हें संरक्षण देने वालों को जवाबदेह नहीं बनाया गया तो फिर बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दुष्चक्र थमने वाला नहीं है। इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक विरोधियों को डराने-धमकाने और उन्हें कुचलने के मामले में वही तौर-तरीके अपना लिए हैं, जो वाम दलों ने अपना रखे थे।

विज का सही जवाब

हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी को करार जवाब देकर ठीक किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहना चढ़ूनी की ओछी मानसिकता का परिचायक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हों या कोई भी, जिनके परिवार भारत विभाजन के समय यहां आकर बसे वे भी उतने ही भारतीय हैं, जितने अन्य लोग। विज की बात तर्कसंगत है कि बंटवारे के समय जो लोग भारत में आए उन्हें भारत से प्रेम था, इसीलिए उन्होंने भारत को चुना। यदि उन्हें भारत से प्रेम न होता तो वे पाकिस्तान में रह जाते। विचारणीय है कि भारत विभाजन के समय उधर से इधर आने वाले परिवारों के लोग राजनीति में ही नहीं हर क्षेत्र में हैं और देश के विकास में उनका योगदान अप्रतिम है। हरियाणा में उनकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि हरियाणा में वहां से लोग बड़ी संख्या में आकर यहां बसे। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो या जननायक जनता पार्टी, सभी दलों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके परिवार विभाजन का दंश झेलते हुए भारत पहुंचे थे। अब ऐसे लोगों को कोई पाकिस्तानी कहे तो उनको दुख होगा ही। इस तरह के अपकथनों का तो सभी दलों के लोगों को विरोध करना चाहिए और ऐसा विरोध करना चाहिए कि फिर किसी दूसरे को ऐसा कहने का साहस न हो। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि चढ़ूनी ने ऐसा क्यों कहा? चढ़ूनी तीनों कृषि सुधार कानूनों को रद करने को लेकर चलाए जा रहे जिस आंदोलन का हिस्सा हैं, वह हिंसक होने के कारण मृतप्राय हो चुका है। आंदोलन में अराजक तत्व से शुरू से ही प्रभावी थे। लेकिन चढ़ूनी जैसे नेताओं को लगता था कि आंदोलन जितना आक्रामक होगा, जितना हिंसक होगा, प्रदेश सरकार उतना ही दबाव में आएगी। ऐसा नहीं हुआ, दूसरी तरफ आंदोलन में शामिल खालिस्तान समर्थक और अन्य अराजक तत्वों के अपकृत्यों से जन सामान्य भी आंदोलन और आंदोलनकारियों से क्षुब्ध हो गया। इन सब कारणों से चढ़ूनी अब इस तरह का अनर्गल प्रलाप करने लगे हैं।

चढ़ूनी का मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी कहना अति आपत्तिजनक है, इसका विरोध सभी दलों को करना चाहिए

सऊदी अरब में वैश्विक महत्व वाला बदलाव



शंकर शरण

एक ओर अफ्रीका से एशिया तक कई देशों में उग्रवादी इस्लाम बढ़ रहा है तो दूसरी ओर अरब देशों में विपरीत प्रक्रिया चल रही है

हाल में सऊदी शासक प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान का एक इंटरव्यू अल-अरबिया चैनल पर आया। इंटरव्यू लेने वाले प्रसिद्ध पत्रकार अब्दुल्ला अल-मुदैफर थे। कुछ अवलोकनकर्ता इसकी अनेक बातों को धरती हिलने जैसी घटना बता रहे हैं। विदित हो कि इधर तीन दशकों से भी अधिक समय से सऊदी अरब पूरे विश्व में बहावी इस्लाम का प्रेरक रहा है। कई मुस्लिम भी मानते हैं कि सऊदी धन से ही भारत के उदारवादी मदरसों में उग्रवादी पाठ भरे गए। यह पूरी प्रक्रिया विश्व में आतंकवाद के फलने-फूलने का बड़ा कारण रही। इस पृष्ठभूमि में नए सऊदी शासक की नीतियां एक बड़ा बदलाव हैं। उक्त इंटरव्यू में एक बार भी इस्लाम शब्द नहीं आया। हालांकि सात बार अल्लाह का नाम और 17 बार प्रोफेट का। कुल दो बार इस्लामी विरासत का उल्लेख हुआ, किंतु अन्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासतों के साथ। इसी में शरीयत का प्रश्न भी उठा। मुदैफर ने सऊदी प्रशासन, संविधान, सार्वजनिक जीवन में शरीयत और वैयक्तिक स्वतंत्रता पर सवाल पूछे। पूरे विश्व में आधुनिक मुसलमान महसूस करते हैं कि जो स्वतंत्रता दुनिया भर में गैर-मुसलमानों को सहज उपलब्ध है, उससे मुसलमान शरीयत के दबाव से वंचित रहते हैं। प्रिंस सलमान ने कहा कि सऊदी अरब का संविधान कुरान है। उसका पालन होता रहेगा, किंतु कुरान में स्पष्ट निर्देशों के अलावा बाकी कायदों पर बाध्यता अनुचित है। प्रोफेट मुहम्मद के उदाहरण (सुन्ना) की भी वही बातें स्वीकार्य होंगी, जो असंदिग्ध हैं। यहां प्रिंस सलमान ने एक नई बात कही। उनके अनुसार, हदीसों में केवल उन्हीं हदीसों को सही माना जाएगा, जिसे कई स्रोतों ने दोहराया हो। इसकी तुलना में अदद व्यक्तियों से मिली हदीसें, जिन्हें अहद हदीस कहते हैं, उसे कुरान से स्पष्ट मेल खाने, साथ ही दुनिया की भलाई से भी जुड़े होने पर ही माना जाएगा। यह बात शरीयत के साथ मानवीय विवेक को भी महत्व देती है।

प्रिंस सलमान के अनुसार अधिकांश हदीसें ऐसी हैं, जिन्हें कदापि बाध्यकारी नहीं रखा जा सकता। प्रोफेट मुहम्मद की जीवनी उद्धृत करते हुए वह कहते हैं कि प्रोफेट ने ही कई हदीसों के रिकार्ड जला देने का हुक्म दिया था और उन्हें लिखने से मना किया था। इस प्रकार शरीयत के अधिकांश निर्देश निष्प्रभावी हो जाएंगे, क्योंकि वे इक्के-दुक्के व्यक्तियों के कहे होने के बल पर बने थे और जिनसे कोई भला नहीं होता। इस प्रकार शरीयत को विवेक-विचार से भी तौलने की बात दूरगामी महत्व रखती है।

अब तक दुनिया भर के उलमा केवल मुस्लिम-हितों की बात करते रहे हैं, पर प्रिंस सलमान मानवता के हित का उल्लेख करते हुए यह भी कह रहे हैं कि मजहबी मामलों में कुरान के स्पष्ट निर्देशों के सिवाय किसी बिंदु पर दंड नहीं दिया जाएगा और वह भी उसी तरह जैसे प्रोफेट ने उसे लागू किया था। उदाहरण के लिए व्यभिचार पर प्रोफेट मुहम्मद द्वारा दी गई व्यवस्था। इस्लामी कायदे के मुताबिक कुंवारे व्यभिचारी को कोड़े मारने की सजा है, जबकि शादी-शुदा व्यभिचारी को मृत्युदंड, किंतु जब प्रोफेट मुहम्मद के सामने एक स्त्री ने अपना अपराध कबूल किया तो उसे सजा देने के बजाय वे लंबे समय तक टालते रहे। यानी प्रोफेट दंड नहीं देना चाहते थे। यह प्रसंग बताकर प्रिंस सलमान कहते हैं कि प्रोफेट द्वारा किए गए व्यवहार के अलावा कोई व्यवस्था देना गलत है। उनके विचार से, कई कामों का दंड देना अल्लाह ने केवल अपने हाथ में रखा, जो अपराधी को मरने के बाद मिलेगा। अल्लाह ने नहीं कहा कि लोग खुद दंड देने लगें। इसी को प्रिंस सलमान सही नजरिया बताते हैं। यह निःसंदेह क्रांतिकारी है, क्योंकि यह चालू शरीयत कायदों की तीन चौथाई बातें खारिज करता है।



बदलाव की राह पर सऊदी अरब। फाइल

प्रिंस सलमान कुरान और सुन्ना की व्याख्या करते हुए सऊदी नागरिकों के हित, सुरक्षा, देश की उन्नति और अंतरराष्ट्रीय नियमों का ध्यान रखना जरूरी मानते हैं। पर्यटन उद्योग का उदाहरण देकर कहते हैं कि यदि किसी देश में अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों से अलग विचित्र कानून होंगे तो बाहरी पर्यटक नहीं आएंगे। इससे उस देश की ही हानि होगी। इसी तरह आर्थिक-व्यापारिक नियम भी अंतरराष्ट्रीय चलन के अनुरूप होने चाहिए, वरना बाहरी निवेश का अभाव होगा। शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में बाहरी प्रतिभाओं, विशेषज्ञों के आने के बारे में भी यही सच है। इस प्रकार प्रिंस सलमान आम मानवीय लोकतांत्रिक देशों के कानूनों के साथ तालमेल रखते हुए सऊदी कानून बनाना चाहते हैं। यह निःसंदेह असंख्य इस्लामी कायदों को छोड़ने की ही हिमायत है। वह सऊदी पहचान को भी नया अर्थ देते हैं, जिसमें इस्लाम के साथ-साथ अपनी अरबी, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत को भी जोड़ते हैं। चाहे वह इस्लाम से पहले की या भिन्न ही क्यों न हो। वह प्रोफेट मुहम्मद की सीखों के साथ-साथ जीवन और इतिहास के अनुभवों को भी महत्व देने की अपील करते हैं।

निःसंदेह प्रिंस सलमान सऊदी अरब की आतंक या इस्लाम-प्रसारक छवि बदलना चाहते हैं। विदेश नीति में भी वह सऊदी नागरिकों के आर्थिक विकास, रोजगार के नए अवसर और अंतरराष्ट्रीय मैत्री संबंध के हामी हैं। इसके लिए हर प्रकार के उग्रवाद और उसे मदद देने को अपराध मानकर यह सब खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोप के साथ-साथ रूस, भारत और चीन का नाम लेकर सबके साथ सहभागिता की जरूरत बताई। इन बातों का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि वे इस्लाम के केंद्र सऊदी अरब में हो रही है, जो सारी दुनिया के मुसलमानों का श्रद्धास्थल है। यहां किसी अच्छे परिवर्तन का असर स्वभाविक रूप से पूरी दुनिया के मुसलमानों पर होगा।

एक ओर अफ्रीका से एशिया तक कई देशों में उग्रवादी इस्लाम बढ़ रहा है तो दूसरी ओर अरब देशों में विपरीत प्रक्रिया चल रही है। अब स्वयं सऊदी लोग इस्लाम से पहले और इस्लाम से भिन्न अपने इतिहास और संस्कृति को महत्व दे रहे हैं। यह बुनियादी परिवर्तन का संकेत है, जिसे भारतीय मुसलमानों को भी नोट करना चाहिए। वैश्विक इस्लाम स्पष्टतः एक गंभीर मोड़ पर है। चूंकि भारत ऐतिहासिक रूप से इस्लाम का एक महत्वपूर्ण केंद्र एवं क्षेत्र रहा है, इसलिए सारी स्थिति से पूरी तरह अवगत होकर अपना कर्तव्य करना चाहिए-हिंदू और मुसलमान, दोनों को।

(लेखक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

अतिक्रमण पर अलग-अलग मानदंड



पंकज चतुर्वेदी

इस पर विचार हो कि यदि सरकारी जमीन से सभी अवैध कब्जे हटा दिए जाएं तो भारत का स्वरूप कैसा होगा?

दिल्ली की सीमा से सटे फरीदाबाद के खोरी गांव के दस हजार घरों में रहने वाले कोई एक लाख लोगों को उजाड़ने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून के हिसाब से सटीक है, लेकिन यह एक सवाल भी खड़ा कर रहा है कि जिस तंत्र की लापरवाही से यह अवैध कब्जे का साम्राज्य खड़ा हुआ, वह ऐसी मानवीय त्रासदी में निरापद कैसे रह जाता है? शायद भारत के इतिहास में इतना बड़ा अतिक्रमणरोधी अभियान कभी नहीं चला होगा, जिसमें 35 धार्मिक स्थल, पांच स्कूल, दो अस्पताल, एक बड़ा बाजार सहित समूची बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। यदि बारीकी से देखें तो समूची कार्रवाई उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है, जिसके कई ऐसे आदेशों पर राज्य सरकारें कुंडली मार कर बैठी रही हैं। यह विचार करने का समय है कि यदि समस्त सरकारी जमीनों से सभी अवैध कब्जे हटा दिए जाएं तो देश का स्वरूप कैसा होगा? दिल्ली में ही अवैध कालोनियों को नियमित करने, झुग्गी बस्ती बसाने और विस्थापन पर नए स्थान पर जमीन देने, मुआवजा बांटने के तमाशे सालों से हर सरकारें करती रही हैं।

खोरी गांव अरावली पहाड़ की तली पर 1980 के आसपास तब बसना शुरू हुआ था, जब यहां खनन शुरू हुआ। पहले खदानों में काम करने वाले मजदूरों की कुछ झुग्गियां बसीं, फिर इसका विस्तार लकड़पुर गांव से दिल्ली की सीमा तक होता रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली में खनन पूरी तरह बंद कर दिया गया और यह बस्ती मेहनत-मजदूरी करने वालों से आबाद होती चली गई। पावर ऑफ अटार्नी पर गरीब-श्रमिक जमीन खरीदते रहे और अपनी सारी कमाई लगाकर अधपक्के ढांचे खड़े करते रहे। इधर दिल्ली सुरसा मुख सी फैल रही थी तो उधर फरीदाबाद-गुरुग्राम सड़क आने के बाद सारा इलाका नगर निगम क्षेत्र में अधिसूचित हो गया। इस एक लाख आबादी की रिहाइश भले ही हरियाणा में हो, लेकिन दिल्ली से तार खींच कर यहां घर-घर बिजली दी जाती थी। बाकायदा साढ़े 13 रुपये यूनिट की वसूली ठेकेदार करते थे। पानी के लिए टैंकर का सहारा। एक हजार रुपये प्रति टैंकर की दर से माफिया पानी भरता था। पीने के लिए 20 रुपये की 20 लीटर वाली बोतल की घर-घर सप्लाई की व्यवस्था यहां थी। जाहिर है कि यहां हर महीने अकेले बिजली-पानी का कारोबार 20 करोड़ रुपये से कम का न था और इतने बड़े व्यापार तंत्र का संचालन बगैर सरकारी मिलीभगत से हो नहीं सकता। यहां हर एक बाशिंदे के पास मतदाता पहचान पत्र है और इस बस्ती के लिए बाकायदा चार मतदाता केंद्र स्थापित किए जाते थे।



फरीदाबाद के खोरी गांव में हटता अतिक्रमण। फाइल

असल में खोरी की कोई सौ एकड़ जमीन नगर निगम की है। पंजाब भू संरक्षण अधिनियम-1900 के तहत यह जमीन वन विकसित करने के लिए अधिसूचित है और यहां कोई भी गैरवानिकी कार्य वर्जित है। अरावली क्षेत्र से अवैध कब्जे हटाने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर फरवरी और अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को खोरी का अवैध कब्जा हटाने के आदेश दे चुका था, लेकिन सरकार जनाक्रोश के डर से अतिक्रमण हटाने से बचती रही। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के उपायुक्त और पुलिस प्रमुख को अतिक्रमण न हटा पाने की दशा में व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार निरूपित करते हुए छह हफ्ते में आदेश के पालन के आदेश दिए। इसके बाद से खोरी खंडहर हो रहा है। यहां की बिजली काट दी गई। चप्पे-चप्पे पर पुलिस है। प्रदर्शन, धरने, हिंसा भी हुई, लेकिन यह सवाल अनुत्तरित है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए तत्काल घर तलाशना-वह भी अपने कार्यस्थल के पास कैसे संभव है? हालांकि अदालत और प्रशासन से यह उम्मीद जरूर थी कि यहां जमीन, पानी और बिजली बेचने वालों पर न केवल आपराधिक मुकदमे हों, बल्कि उनकी संपत्ति से विस्थापित लोगों को आवास मुहैया कराया जाए। खोरी के इतने बड़े विस्थापन पर राजनीतिक रूप से कोई बड़ी हलचल न होना जताता है कि इतनी बड़ी बस्ती को बसाकर अपने महल खड़े करने वालों में हर दल के लोग होते हैं।

यह जानना जरूरी है कि देश में कुल वन भूमि के दो प्रतिशत अर्थात 13 हजार वर्ग किमी पर अवैध कब्जे होने की बात केंद्र सरकार ने एक सूचना अधिकार अर्जी में स्वीकार की है। इससे पहले जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने देश में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर बने धार्मिक स्थलों की सूची मांगी थी और 2016 में आदेश दिया था कि ऐसे 20 लाख से ज्यादा कब्जे हटाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकारों ने ही बताया था कि तमिलनाडु में 77,450, राजस्थान में 58,253, मध्य प्रदेश में 52,923, उप्र में 45,152 ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए हैं। आदेश को पांच साल से अधिक हो गया। इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ।

आजादी के समय देश के हर गांव में एक परती या चरागाह की जमीन होती थी। हर गांव में मवेशियों के चरने के लिए बड़े हरियाली चक को छोड़ा जाता था। आज शायद ही किसी गांव में चरागाह की जमीन बची हो। देश का कोई भी शहर, कस्बा ऐसा नहीं है, जहां बाजार या दुकान के नाम पर कुछ फुट सरकारी जमीन पर कारोबार आगे न बढ़ाया गया हो। पैदल चलने वालों के लिए बने फुटपाथ पर दुकान सजाना तो अधिकार में शामिल है। हर कालोनी में घर के आगे की कुछ जमीन पर क्यारी लगाने, गाड़ी खड़े करने का चबूतरा या शेड बनाने में किसी को कोई लज्जा नहीं आती। दिल्ली की सीमाओं पर सार्वजनिक सड़क पर कब्जे कर पक्की संरचनाएं खड़ी कर सात महीने से धरना दे रहे किसानों पर कोई कानून लागू नहीं होता। जाहिर है ऐसे अतिक्रमण प्रधान देश में खोरी को बगैर विकल्प के उजाड़ देना भले ही वैधानिक हो, लेकिन नैतिक या मानवीय कतई नहीं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्म-नियंत्रण

जहां गतिशीलता है वहां नियंत्रण भी जरूरी है। वह चाहे भौतिक स्तर की गतिशीलता हो या मानसिक स्तर की। यदि गति पर नियंत्रण का विधान नहीं होगा तो दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। भौतिक स्तर पर किसी भी तरह के वाहन होते हैं उनमें ब्रेक भी होता है। वाहन चालक स्थिति-परिस्थिति के अनुसार ब्रेक का प्रयोग करते हुए गंतव्य तक पहुंचता है। इसी तरह का नियंत्रण मन के स्तर पर भी जरूरी है। सबसे तेज मन ही चलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने 'पीपर पात सरिस मन डोला' चौपाई में यह स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार हल्की सी भी हवा चलने से पीपल के पत्ते हिलने-डुलने लगते हैं, उसी प्रकार किसी भी तरह की परिस्थितियां आती हैं तो सबसे पहले मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। जहां सबकुछ अनुकूल होने पर मन के निरंकुश होने का खतरा पैदा हो जाता है, वहीं विपरीत स्थिति में नकारात्मक कार्य करने लगता है।

किसी भी युग का उदाहरण लें तो यह स्पष्ट होता है कि जिसने भी आत्म-नियंत्रण नहीं किया, उसको संकटों का सामना करना पड़ा। सतयुग में हिरण्यकश्यप रहा हो, त्रेता में रावण या द्वापर में दुर्योधन। सबने आत्म नियंत्रण खो दिया था। इसलिए ये सब प्रतापी और बलिष्ठ होते हुए भी मारे गए और उनका उदाहरण निंदनीय कार्य के लिए दिया जाता है। मुहावरा भी है कि 'बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय।' हर व्यक्ति का मन गलत-सही के बारे में बताता रहता है, लेकिन आत्म-नियंत्रण न होने से व्यक्ति गैरविधिक कार्य कर बैठता है और संकट में पड़ जाता है। इसलिए हर किसी को खुद अपने जीवन का संविधान बनाना चाहिए। जिस कार्य से खुद को कष्ट मिले, वह कार्य दूसरों के साथ न करे। कथनी-करनी में अंतर न करे। अवांछित सुख की चाहत न रखे और शक्ति का उपयोग लोगों के हित के लिए करे, न कि पीड़ा पहुंचाने के लिए। छोटी-छोटी सावधानियों पर अमल कर व्यक्ति सुखी जीवन जी सकता है।

सलिल पांडेय

लैंगिक समानता की चुनौती

कीर्तिदेव

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किए बिना देश में लैंगिक समानता नहीं लाई जा सकती है

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2021 में भारत को 156 देशों की सूची में 140वां स्थान मिलना यह दर्शाता है कि देश में लैंगिक समानता के लिए किए गए प्रयासों को अभी वांछित सफलता नहीं मिली है। दक्षिण एशिया में भारत का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। हमें यह मानना होगा कि मात्र कानून बना देने या अधिकार दे देने से लैंगिक असमानता नहीं मिटेगी, क्योंकि कानून केवल महिलाओं को दिए गए हथियार हैं। केवल हथियार दे देने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि महिलाएं उनका इस्तेमाल करने लायक न हो जाएं।

लैंगिक समानता स्थापित करने की दिशा में हमें कई क्षेत्रों में गंभीर प्रयास करने होंगे। एक तो यह कि हमें ग्रामीण समाज को शिक्षित करना होगा। दरअसल लैंगिक समानता स्थापित करने में स्कूल एवं अन्य शिक्षा केंद्रों की सबसे अधिक भूमिका होती है। प्राथमिक शिक्षा से ही लैंगिक समानता पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी बच्चे की जिंदगी के शुरुआती वर्षों में ही उसकी समझ विकसित होती है। जैसे वातावरण में वह रहता है, वैसी छवियां उसके मन में बैठ जाती हैं। स्कूलों में खासकर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लड़कों एवं लड़कियों को कभी अहसास न हो कि लड़कियों या फिर लड़कों की समाज में खास भूमिकाएं तय हैं। स्कूलों में लड़कों-लड़कियों को अलग-अलग कतारों में बिठाने, आपसी मेलजोल को गलत ठहराने से धीरे-धीरे उनके बीच एक खाई बना जाती है। और यहीं से फिर लैंगिक असमानता की शुरुआत होने लगती है। दूसरा, हमें फिल्मों और धारावाहिकों में ऐसे दृश्य दिखाने होंगे, जो महिला-पुरुष में समानता दर्शाएं। इंग्लैंड में इस दिशा में कानून बनाया गया है। खासकर बच्चों को दिखाए जाने वाले कंटेंट में ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि बच्चों की समझ बनाने में आज इन चीजों की बहुत अधिक भूमिका है।

एक पहलू यह भी है कि भारत में महिलाओं की आर्थिक एवं वित्तीय हालत अच्छी नहीं है। संपत्तियों पर महिलाओं का मालिकाना हक न होना उन्हें पुरुषों पर आश्रित बनाता है। महिलाओं को कानून के जरिये संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार मिल गया है, परंतु अधिकांश महिलाएं सामाजिक दबाव के चलते संपत्ति में हिस्सेदार बनने से परहेज कर रही हैं। साफ है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किए बिना लैंगिक समानता नहीं लाई जा सकती है और महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत तभी होंगी, जब वे जागरूक एवं शिक्षित होंगी। आंकड़ों के अनुसार भारत में मात्र 9.8 प्रतिशत महिलाएं ही स्नातक तक शिक्षित हैं तो सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का योगदान मात्र 20 प्रतिशत के आसपास है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हमें अभी लैंगिक समानता की दिशा में बहुत कुछ करना है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

देश को व्यवस्थित बनाने के उपाय

'बंगाल को बचाने के उपाय' लेख में कैप्टन आर विक्रम सिंह द्वारा सुझाए गए विचारों पर केंद्र सरकार को अविलंब निर्णय लेना चाहिए। केंद्र सरकार को सीमावर्ती राज्यों के लिए केंद्रीय प्रशासन की प्राचीन इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पुनर्जीवित करना चाहिए। इसका विस्तार सीमावर्ती सभी राज्यों में होना चाहिए जिससे सीमा पार से अवैध प्रवेश, मादक पदार्थों, पशुओं की तस्करी, हथियारों, आतंकवादियों के प्रवेश आदि को रोकने में मदद मिले। इससे कई समस्याओं से निजात मिलने में सहायता मिलेगी। इस प्रशासनिक परिवर्तन से राज्यों में शांति और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। बंगाल में तृणमूल सरकार बनने के बाद भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं पर हमले और उनकी हत्या की गई। कुछ पीड़ितों ने दूसरे राज्यों में भागकर अपनी जान बचाई। देश की जनता बंगाल में हिंसा और अराजकता की स्थिति देखकर आहत है। राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखना राज्यों का विषय है। केंद्र को संविधान में संशोधन कर अराजकता की स्थिति में राज्यों की कानून-व्यवस्था में हस्तक्षेप का अधिकार हासिल करना चाहिए। लेखक के अनुसार बंगाल की स्थिति सुधारने के लिए राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर देना चाहिए। राष्ट्रहित में इस संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा के लिए निर्णय लेने का समय आ गया है। किसी भी दल की सरकार बनने का यह अर्थ नहीं है कि उसका हर कार्यकर्ता कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करे। किसी भी राज्य के सत्ताधीश को सर्वजन हिताय की भावना से ही सत्ता का संचालन करना चाहिए। जिससे राज्य में अराजकता और गुंडागर्दी की स्थिति उत्पन्न न हो।

कुलदीप मोहन त्रिवेदी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश

मेलबाक्स

दिशाविहीन कांग्रेस

संपादकीय पेज पर प्रकाशित लेख कांग्रेस की कार्यशैली में कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे के कथन पर विवेचन किया गया है। शिंदे का यह कहना कि अब कांग्रेस में बहस और संवाद की परंपरा खत्म हो गई है कटु सत्य है। दरअसल कांग्रेस में अब नेहरू-गांधी परिवार के अलावा और किसी की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। बेशक पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अपने मंत्रिमंडल में नवजोत सिंह सिद्धू को शामिल नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन गांधी परिवार के ओदश का उल्लंघन करना उनके लिए संभव नहीं था। सिद्धू पहले भी विवादों में रहे हैं, किंतु यह कांग्रेस का मामला है और अंतिम फैसला गांधी परिवार ही करता है। कांग्रेस को तो अपना अध्यक्ष नियुक्त करने का समय नहीं मिल पा रहा है। सोनिया गांधी बरसों से बिना किसी चुनाव के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। बीच में राहुल गांधी भी अध्यक्ष रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद उन्होंने वापस सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष पद सौंप दिया। अब गांधी परिवार के तीनों सदस्य बारी बारी से मिलजुल कर कांग्रेस की गाड़ी को खींच रहे हैं। परिवार से बाहर का कोई नेता पार्टी की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

पौधारोपण को बनाना होगा जनअभियान

दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है। तापमान ने पिछले 90 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया है। कुछ वर्ष पूर्व तक इस समय मानसून का आगमन हो जाता था और लोग झमाझम बारिश का आनंद लेते थे। कई-कई दिनों तक धूप के दर्शन नहीं होते थे। परंतु अब तस्वीर बदल चुकी है। आखिर दिल्ली से बादलों के रूठने का क्या कारण हो सकता है हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। शहरीकरण को बढ़ावा और लगातार घटते वन क्षेत्र ने प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचाया है और अब उसी का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। कहने को तो सरकार प्रत्येक वर्ष अभियान चलाकर पौधारोपण को बढ़ावा देती है, परंतु सही मायनों में यह कागजों तक ही सीमित है। जब तक पौधारोपण कार्यक्रम को जनजागरण अभियान बनाकर धरातल पर नहीं उतारा जाएगा तब तक मेघों से उम्मीद करना बेमानी है। हमें बड़े पैमाने पर पौधे लगाकर वन क्षेत्र विस्तार की दिशा में कार्य करने की जरूरत है।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

22,184 करोड़ रुपये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में दिए गए हैं केंद्र सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्यों को। इस फंड का एक बड़ा हिस्सा कोरोना महामारी से लड़ने में खर्च हो रहा है।

आजकल

आश्रितों के लिए तार्किक रूप से तय हो मुआवजा



लालजी जायसवाल
शोधार्थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

कोरोना महामारी से मरने वालों के आश्रितों को समुचित मुआवजा देने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लाखों लोगों को राहत देने वाला साबित होगा। इस महामारी के कारण देशभर में अब तक करीब चार लाख लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में इस संबंध में की गई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मुआवजे की रकम तय करने से इन्कार करते हुए यह कहा कि सरकार स्वयं ही यथोचित मुआवजा राशि निर्धारित करे। ऐसे में सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह बेहद तार्किक तरीके से इसकी रकम तय करे



कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को समुचित मुआवजा देने की व्यवस्था करे सरकार। फाइल

कोरोना महामारी से प्राण त्यागने वालों को सरकार की ओर से मुआवजा दिए जाने के प्रविधान पर बहस जारी है। न्यायालय में दायर संबंधित याचिका में आश्रितों को चार लाख रुपये देने की मांग की गई, तो अदालत ने सरकार से इस पर उसका रुख जानना चाहा। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि इस तरह का भुगतान राज्यों के पास उपलब्ध 'स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड' से होता है। लेकिन अगर राज्यों को हर मौत के लिए चार लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया, तो उनका पूरा फंड खत्म हो जाएगा। इससे अन्य आपदाओं से लड़ पाना कठिन हो जाएगा।

सरकार का इस बारे में कहना है कि मुआवजा देने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई और स्वास्थ्य पर किए जा रहे खर्च पर असर पड़ सकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्यों को 22,184 करोड़ रुपये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में दिए गए। इसका एक बड़ा हिस्सा कोरोना से लड़ने में खर्च हो रहा है। केंद्र ने 1.75 लाख करोड़ रुपये का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया है। इसमें गरीबों को राशन के अलावा वृद्ध, दिव्यांग, असमर्थ महिलाओं को सीधे पैसे देने जैसी कई बातें शामिल हैं।

बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी बातों का संज्ञान लेते हुए इसे सरकार का उत्तरदायित्व मानते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया है। लेकिन न्यायालय ने इतनी छूट अवश्य दी है कि सरकार मुआवजा राशि अपने हिसाब से तय कर सकती है। इसके लिए छह हफ्ते के भीतर दिशानिर्देश जारी करने होंगे। अब सरकार के समक्ष यह चुनौती है कि सामंजस्य के साथ सही मानक तैयार किया जाए, जिससे कोई पीड़ित परिवार मुआवजे से वंचित न हो और सरकार को ज्यादा वित्तीय दबाव का सामना भी न करना पड़े।

यह कहना सही है कि सरकारी मुआवजे मात्र से उन लोगों की जिंदगी आसान नहीं हो जाती है, जिन्होंने अपना भरण-पोषण करने वाला सदस्य खो दिया है। सरकार द्वारा मुआवजे का प्रविधान इसलिए किया जाता है, ताकि परिवार के बचे हुए लोगों को संभलने और नए ढंग से जीवन शुरू करने में आसानी हो। यह तय है कि कोरोना की वजह से अपने सदस्य खो चुके परिवार के लोगों को कुछ दिन तक संभालने की जिम्मेदारी से सरकार कभी मुंह नहीं मोड़ेगी। सरकार अपने पिछले कई निर्णयों से यह साबित कर चुकी है कि वह लोककल्याण के लिए कितनी संवेदनशील है और वास्तव में सरकार की यह छवि दिखाती है कि किसी सरकार का जनहितकारी और लोककल्याणकारी रूप क्या होता है। पिछले दिनों कोरोना से अपने माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के तहत सहायता देने की घोषणा की गई। इन सभी निर्णयों से सरकार की लोक हितकारी भावनाएं साफ झलकती है।

वैसे समग्रता में देखा जाए तो मृतकों के मुआवजे को लेकर न केवल केंद्र, बल्कि राज्य सरकारों की अन्यमनस्कता कायम है। अगर उत्तर प्रदेश और बंगाल की बात की जाए, तो पिछले पंचायत और विधानसभा चुनावों में सैकड़ों कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए और अपनी जान गंवा बैठे। किंतु सरकार की ओर से उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल सका है। इस बीच मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों के परिवार को प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपये मुआवजा राशि देने की घोषणा की थी। कर्नाटक सरकार ने बीपीएल परिवार में कोरोना से मौत पर एक लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी। वहीं बिहार सरकार पहले से ही कोरोना मृतकों के आश्रित स्वजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा राशि दे रही है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि अपेक्षाकृत कम बजट वाली बिहार सरकार बतौर मुआवजा चार लाख रुपये दे सकती है, तो दूसरे राज्य और कम से कम केंद्र सरकार को इससे ज्यादा ही मुआवजा तय करना चाहिए।

वैसे बिहार सरकार की मुआवजा नीति में एक बड़ी कमी चिंता पैदा करने वाली है। बिहार सरकार का निर्णय है कि अगर किसी बिहारवासी यानी बिहार के नागरिक की राज्य से बाहर मौत होती है, तो ऐसी दशा में बिहार सरकार उसे किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देगी। सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से मौत पर मिलने वाली चार लाख रुपये की मुआवजा राशि केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिनकी मौत बिहार के अस्पतालों या बिहार की सीमा के अंदर हुई हो। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिहार का कोई व्यक्ति अपने राज्य से बाहर इलाज कराने के लिए क्यों जाता है? अगर वह बिहार में रहता और कोरोना से मौत होती तो उसके परिवार को मुआवजा जरूर मिलता। अगर कोई व्यक्ति इलाज के लिए राज्य से बाहर गया तो कहीं न कहीं यह बात साबित होती है कि राज्य की चिकित्सा व्यवस्था जर्जर थी। अब सवाल है कि इस जर्जर व्यवस्था के लिए सरकार जिम्मेदार है या वहां के नागरिक? अगर सरकार को जिम्मेदार माना जाए तो वह प्रत्येक व्यक्ति मुआवजे का हकदार है, जिसकी मौत बिहार राज्य से बाहर हुई है।

खैर, अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इतना तो तय हो गया है कि भविष्य में पीड़ित स्वजनों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। वैसे न्यायालय के आदेश के बाद उन्हीं लोगों को मुआवजा मिल सकेगा, जिनके मृत्यु प्रमाण-पत्र पर मौत का कारण 'कोरोना' दर्ज होगा।

हालांकि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे वैसे लोगों के स्वजन इस मुआवजे को हासिल करने के लिए अपना दावा नहीं पेश कर पाएंगे, जिनके परिवार में किसी ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया था। मृत्यु प्रमाणपत्र की इसमें अहम भूमिका होगी, जिसमें संबंधित कारण दर्ज होना आसान नहीं। इसलिए, इस मामले में सरकार से बहुत सुसंगत तरीके से दिशानिर्देश तय करने की अपेक्षा की जाती है। मुआवजा तय करते और देते समय ध्यान रखना होगा कि किसी के साथ अन्याय न होने पाए।

संक्रमण की तीसरी लहर पर असमंजस



संजय श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार

कोरोना की दूसरी लहर इस माह विदा हो सकती है, मगर तीसरी लहर आशंकित है। तीसरी लहर के आने न आने पर असमंजस है तो इस बात को लेकर भी कि यह कब दस्तक देगी। विशेषज्ञों और विज्ञानियों में से किसी का आकलन अगले दो महीने में है तो कोई इसकी आमद अगले साल बता रहा है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आएगी ही चाहे जब आए तो फिर इस सवाल पर भी ऊहापोह है, क्या दूसरी लहर के मुकाबले यह कमजोर होगी या ज्यादा मारक? इस पर भी विशेषज्ञ एकमत नहीं हैं। ढाई महीने पहले इस बात की आशंका व्यक्त की गई थी कि तीसरी लहर का असर गांवों और सुदूर क्षेत्रों में घातक होगा। स्वास्थ्य संजाल का सघन न होना, कम टीकाकरण और जागरूकता का अभाव इसके कारण हैं, लेकिन अब इस मामले में भी विचार बदल गया है।

लेकिन इसके उलट भी तमाम बयान हैं कि हमने दूसरी लहर से सबक भले ही लिए हों, मगर तीसरी लहर की तैयारी बहुत नगण्य है। सबब यह कि जितने मुंह, उतनी बातें। ये बातें इंटरनेट मीडिया की गपशप नहीं हैं, बल्कि विभिन्न आधिकारिक और प्रतिष्ठित विश्वस्त माने जाने वाले स्रोतों द्वारा निकली हैं। अपने क्षेत्र के मान्य व्यक्तियों, विशेषज्ञों ने कही हैं। पर कुल मिलाकर भ्रम ही पैदा करती हैं। सरकार विरोधी कहते हैं, तीसरी लहर सरकारी भ्रम है। कहीं नहीं आने वाली। जब यह नहीं आएगी तो सरकार अपनी तैयारियों और कार्यकुशलता का ढिंढोरा पीटेगी, अपनी पीठ खुद ठोकेगी।

इस बीच एक तथ्य यह भी है कि सबके लिए तीसरी लहर आशंका है तो फार्मा क्षेत्र के लिए संभावना। इसे भी अनेक संदर्भों में समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. राघवन, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया समेत कई दिग्गजों का कहना है कि तीसरी लहर का आना तय है। दुनियाभर के 40 स्वास्थ्य विशेषज्ञ, चिकित्सक, विज्ञानी, विषाणुविज्ञानी और महामारी विशेषज्ञों के बीच एक न्यूज एजेंसी के सर्वे का नतीजा यह निकला कि अलग अलग समय पर ही सही, पर सभी ने माना कि कोरोना की तीसरी लहर जरूर आएगी। पर यह स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए कि कब आएगी।

कुछ विज्ञानियों का विचार है कि तीसरी लहर इस बात पर निर्भर करती है कि लोग कितने बेपरवाह हुए और वायरस ने स्वयं में किस तरह का बदलाव किया। इन आकलनों में बहुत सी गणनाएं सरकारी आंकड़ों पर आधारित हैं। आंकड़े जितने शुद्ध होंगे, आकलन उतने ही सटीक। तीसरी लहर कितनी मारक होगी मतभेद इसको लेकर भी है। कई विशेषज्ञों के अनुसार यह संक्रमण दर में थोड़ी बढ़ोतरी भर हो सकती है तो कुछ का विचार है कि लहर उतनी घातक कतई नहीं होगी जितनी पहली या दूसरी। तर्क यह कि लहर आने तक व्यापक वैक्सीनेशन हो चुका होगा और लोग हर्ड इम्युनिटी के अलावा नेचुरल इम्युनिटी से भी लैस होंगे। अधिकांश विशेषज्ञों ने कहा कि तीसरी लहर पर सरकार का बेहतर नियंत्रण होगा, वह दूसरी लहर के मुकाबले बेहतर तरीके से निपटेगी। पर यह भी है कि तब तक वायरस अपनी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए म्यूटेट होकर किसी और अधिक संक्रामक व मारक वैरिएंट में न बदल जाए। लहर का असर कितना होगा यह संदेह के घेरे में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के प्रमुख कहते हैं, तीसरी लहर में बच्चों के लिए हालात गंभीर हो सकते हैं।

ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कोरोना की दो लहरों के दौरान देश की जो हालत हुई, उसके बाद तीसरी लहर को लेकर ऐसे मतभेद, असमंजस और ऊहापोह कोरोना के खिलाफ हमारी जंग को कमजोर कर सकते हैं। (ईआरसी)

खरी-खरी

होना था पठनीय... हो गए दयनीय

आशीष दशोत्तर

तमाम तिकड़मों, तैयारियों, तरकीबों के बावजूद वे 'लघु एवं सीमांत' ही रहे। अनसुने, अनजाने, अनचाहे, अपरिपक्व, अलोकप्रिय, अमान्य होने के दंश से मुक्त नहीं हो पाए। लघु से दीर्घ एवं सीमांत से दुर्दांत बनने का सपना अधूरा ही रहा।

कोई उनके दिल से पूछे कि उस पर क्या-क्या गुजरी। किसी ने उनके दिल का हाल नहीं जाना। जब-जब उन्होंने अपनी हदों को बढ़ाने का प्रयास किया तब-तब उन्हें रोक दिया गया। उड़ने से पहले ही पर कतर दिए गए। किसी ने कहा, कविताएं कच्ची हैं। किसी ने कहानियों को अधूरा बताया। किसी ने स्पष्ट भाव से टरकाया तो किसी ने तटस्थ भाव से टाला। वे दिनकर जी की पंक्तियां दोहराते रहे, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।

उन्हें यकीन है कि आज उनकी रचनाओं पर जो तटस्थ भाव दिखा रहे हैं, उन्हें एक दिन अपनी भूल का अहसास होगा। मगर मुद्दा तो अभी उनके महत्व को पहचानने का है न!

उनकी इच्छा भी आखिर क्या रही? फकत इतनी ही कि वे बड़े और नामी लेखकों में शुमार किए जाएं। नामी-गिरामी अखबार और पत्रिकाएं उन्हें सम्मानित स्थान दें। इतनी छोटी सी इच्छा को कोई पूरी नहीं कर रहा। हर तरह से लिख कर देख लिया। महान रचनाकारों की रचनाओं को देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार बदल कर भी इस्तेमाल किया। हर तरह से लिखा हुआ भेज कर देख लिया।

किसी ने कहा कि रचना के महत्व से कोई रचना प्रकाशन योग्य नहीं हो जाती। रचना को रचना होने के लिए लेखक की सक्रियता आवश्यक होती है। रचना अच्छी होने से नहीं लेखक के प्रयत्न और संबंधों से प्रकाशित होती है। उन्होंने यह भी किया। पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ।

लघु एवं सीमांत कृषकों को कम से कम कुछ राहत, मुआवजा और सहानुभूति तो मिल जाती है। इन्हें लघु एवं सीमांत लेखक होकर भी रचना प्रकाशन का लाभ नहीं मिल पाया। व्यथित हृदय से अब कहते फिरते हैं- पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है। जिसका सिक्का चल रहा है, वही छप रहा है। वे पठनीय होना चाहते थे, लेकिन दयनीय हो गए हैं। कोई 'पत्थर दिल' संपादक पिघले तो कोई बात बने।

ट्वीट-ट्वीट

पंजाब में बिजली संकट पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने वाले नवजोत सिंह सिद्धू का सामने आया सच। वह पिछले नौ महीनों से नहीं भर रहे अपना बिजली बिल। उनपर आठ लाख, 67 हजार, 540 रुपये बकाया है।
अभिषेक उपाध्याय@upadhyayabhii

शायर मुनव्वर राणा ने पहले मां वाली शायरी चोरी की। अब अपने भाई की 18 बिस्वा जमीन हड़प ली। यह शर्मनाक है।
जितेंद्र शर्मा@capt_ivane



भारत में तीन मजाक बहुत प्रसिद्ध हैं। 1-कानून सबके लिए बराबर है। 2-आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। 3-मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
संजय दीक्षित@Sanjay_Dixit

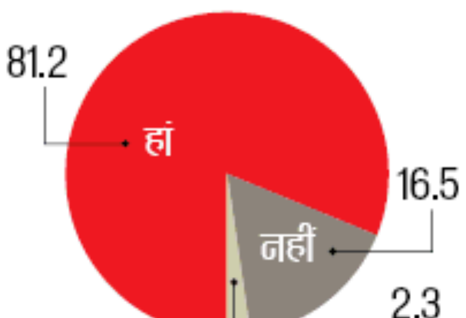
विश्वनाथ धाम जबसे बन रहा है तबसे एक वर्ग के लिए आंख की किरकिरी बना हुआ है। जो दो चार किताबें पढ़कर बनारस को जानते हैं वे लोग दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से आते हैं और झट से लिख देते हैं कि बनारस की अस्मिता से खिलवाड़ हो रहा है। इस तरह वे लोग अपनी जगहंसाई ही करवा रहे हैं।
अतुल कुमार राय@AuthorAtul

अगर आपसे किसी को मदद की उम्मीद नहीं तो फिर यह समझ लीजिए कि जिंदगी में आपको बदलाव लाने का समय आ गया है।
सोनू सूद@SonuSood

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या महंगाई बेलगाम होती दिख रही है?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या कांग्रेसी नेतृत्व पंजाब और राजस्थान कांग्रेस के झगड़े को सुलझाने में नाकाम साबित हो रहा है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

चर्चा में हैं आजकल ममता जी के आम,
जितनी कड़वी जीभ है उतने मीठे आम।
उतने मीठे आम मित्र हो या हो बैरी,
भिजवाने में आम लगातीं ना वो देरी।
भाषण में तो आप उगलती रहतीं मिर्चा,
पर भिजवाकर आम खूब पा लेतीं चर्चा।
– ओमप्रकाश तिवारी



आलोक मिश्रा
स्थानीय संपादक, बिहार

बिहार डायरी

तबादले के मौसम में मंत्री जी का हाल

बिहार में जून का खासा महत्व है। मानसून ही नहीं यह तबादलों का भी मौसम होता है। इस मौसम का सभी को इंतजार रहता है। लेकिन इस बार यह मौसम समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी को नहीं सुहाया। रिएक्शन ऐसा हुआ कि वे इस्तीफा-इस्तीफा भजने लगे हैं। हालांकि अभी इस पर अमल तो नहीं किया है, लेकिन भजना भी नहीं रुका है। मंत्री जी का दर्द भी कम नहीं है। उनकी पैरवी को उनके ही अधिकारियों ने तवज्जो नहीं दी तो बेचारे क्या करते? क्षेत्र में मुंह भी दिखाना है और आगे की राजनीति का जुगाड़ भी करना है। अगर इतना भी न करवा पाए तो मंत्री किस बात के?

मदन सहनी जदयू के टिकट पर दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। वे तीसरी बार विधायक बने हैं और दूसरी बार मंत्री। उनकी कसक इस बात की है कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं। इधर तबादलों का मौसम जब आया तो उनकी सूची भी तैयार हो गई। 134 सीडीपीओ के स्थानांतरण की सूची उन्होंने भेज दी। लेकिन उनके अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने उसे तवज्जो नहीं दी। 30 जून आखिरी तारीख थी। समय गुजरता देख बेचारे हर दर पर संपर्क करने लगे, लेकिन किसी ने भाव नहीं दिया। कसक गुबार में बदली और वे फट पड़े कि अधिकारी छोड़ो, चपरासी तक उनकी बात नहीं सुनते। अब मंत्री जी इस्तीफा देने पर उतारू हैं। मजा लेने वाले इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह लगाए हैं। कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभाल लेंगे और इस्तीफा नहीं होगा तो कोई कह रहा है कि मामला तूल पकड़ेगा और सिर्फ उनका इस्तीफा ही नहीं तैयार है, बल्कि उनकी जाति से आने वाले तमाम लोग संगठन से भी इस्तीफा दे देंगे। मंत्री जी शुक्रवार को अपने साथी विधायक के अंतिम संस्कार के लिए कुशेश्वर स्थान



इस्तीफा देने की घोषणा के बाद शुक्रवार को दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के विधायक शशिभूषण हजारी के अंतिम संस्कार में मौजूद समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी (काला मास्क लगाए बायें से चौथे)। जागरण

गए हैं। शनिवार को उनके पटना आने पर आगे का दृश्य सामने आएगा। सिस्टम में उनका प्रलाप नक्कारे की तूती ही अभी तक साबित हुआ है। उनके दर्द पर अभी तक कोई भी जिम्मेदार नहीं बोला है।

जून का इंतजार सभी मंत्रियों और बड़े अधिकारियों को रहता है। इसमें थोक में तबादले होते हैं। जिसमें लंबे रेट होते हैं। मनचाही पोस्टिंग हो या तबादला रुकवाना हो, सभी के लिए रकम तय होती है। अब तक लगभग 2300 तबादले हो चुके हैं। जिसकी चल गई उसकी चांदी और जिसकी नहीं चली उसको आया माल लौटाने की दिक्कत। इस बार कुछ की खूब चली, जबकि जो हल्के पड़े, वे निपट गए। अमूमन काम न करवा पाने वाले दिल मसोस कर रह जाते हैं, लेकिन इस बार मंत्री मदन सहनी ऐसे उदाहरण हैं जो पूरी व्यवस्था पर फट पड़े। उनकी बात का समर्थन करने के लिए बाढ़ से भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल भी उतर पड़े हैं। दोनों ने ही तबादलों में मोटी रकम उगाहने के खेल पर मोहर लगाई है। ज्ञानू तो यहां तक कह बैठे कि अगर मंत्रियों के यहां इस समय छापे पड़ें तो करोड़ों मिलेंगे। सरकार के सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी ने भी मदन सहनी के आरोपों को सही ठहराया है। हालांकि लेन-देन के इस कारोबार में कुछ विभाग ऐसे भी रहे जिनमें पैसा-पैरवी नहीं चली। घपला देख शिक्षा विभाग में पटना के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के तबादले की सूची निरस्त कर दी गई।

इधर भाजपा कोटे के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के साथ भी खेल हो गया। उद्योग विहीन बिहार में जब महत्वहीन उद्योग विभाग उन्हें मिला तो वे उसे खड़ा करने की ठान बैठे। देशभर में अपने संबंधों के आधार पर तमाम उद्योगपतियों से संपर्क कर बिहार में लाने की कवायद करने लगे। इथेनाल उत्पादन का उनका पासा सही पड़ा और तमाम लोगों ने रुचि दिखाई। जब कवायद पूरी हो गई तो उन्हें लगा कि इसकी घोषणा की जाए। मंत्री जी ने शुक्रवार का दिन तय किया। लेकिन जब वो गुरुवार को मुंबई से पटना चलने को तैयार हुए, उसी समय बिहार में राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक हो गई और उसमें 12,744 करोड़ रुपये के 99 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जिसमें अकेले 59 प्रस्ताव इथेनाल के हैं। इसके अतिरिक्त, तीन दिनों में नए मिले 87 प्रस्तावों की जानकारी भी सार्वजनिक कर दी गई। अब शाहनवाज हुसैन के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसको लेकर भी तरह-तरह की चर्चा है। कुछ इसे शाहनवाज की तेजी पर ब्रेक के रूप में देख रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि ये तो होना ही था।

मंथन

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं में होड़



शंभु सुमन
तकनीकी मामलों के जानकार

भारत में इंटरनेट की बढ़ती मांग के बीच देश–दुनिया की तमाम तकनीकी कंपनियां इस क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही हैं जो आकाश के जरिए इसे दूरदराज इलाकों तक पहुंचाएंगी



देश के दूरदराज क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचाने की प्रक्रिया में तेजी आने की जगी उम्मीद। प्रतीकात्मक

भारत में 'डिजिटल इंडिया' अभियान के छह वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जुलाई को इसके फायदे गिनाते हुए कहा कि आनलाइन शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक के लिए विकसित किए गए प्लेटफॉर्म से करोड़ों भारतीय लाभान्वित हो रहे हैं। कोरोना काल में इसकी बदौलत ही दूरदूराज तक स्वास्थ्य सुविधाओं को संभव बनाया जा सका। साथ ही इसके सहयोग से कोरोना महामारी से निपटने में भी मदद मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संदर्भ में नया नारा देते हुए कहा- डिजिटल इंडिया मतलब सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी।

इसके बढ़ते उपयोग के बीच अब हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत महसूस की जा रही है। इसकी पूर्ति में देसी-विदेशी कंपनियां से लगी हुई हैं। इसी संदर्भ में जियो ने गूगल से समझौता किया है, तो बीएसएनएल ऑप्टिकल फाइबर बिछाने पर जोर दे रही है। टेलीकॉम आपरेटरों में पुरानी कंपनी एयरटेल 28.2 मेगाहर्ट्ज एयरवेव और एडवांस नेटवर्क साफ्टवेयर टूल का इस्तेमाल कर हाई स्पीड डाटा सर्विस एवं गांवों में व्यापक सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहती है। इनसे हटकर हजारों सेटेलाइटों के जरिए आकाश से इंटरनेट सेवा लाने की होड़ मची हुई है। इसमें अमेजन भी शामिल हो गया है। उसने करीब तीन हजार सेटेलाइट लांच करने का एक प्रोजेक्ट बनाया है। उसकी निगाह भारत के सबसे बड़े इंटरनेट बाजार पर है। उनके सेटेलाइट पृथ्वी के सबसे निकटतम भू-स्थिर कक्षा यानी लो-अर्थ आर्बिट (एलईओ) में स्थापित किए जाएंगे, जिससे पृथ्वी के चारों ओर सेटेलाइटों के समूह का जाल बन जाएगा।

इस सिलसिले में पिछले एक दशक से प्रयास जारी है। इंटरनेट स्पीड बढ़ाने से लेकर सभी जगहों पर उसकी सहज उपलब्धता को लेकर तरह-तरह के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इंटरनेट के लिए समुद्र में केबल फैलाए गए हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनियां इस मैदान में हैं। गूगल और फेसबुक से लेकर स्पेसएक्स तक इसमें शामिल हैं। हालांकि फेसबुक और गूगल को इस मामले में अब तक अप्रत्याशित सफलता नहीं मिली है। फेसबुक ने 2013 में अपना प्रोजेक्ट 'इंटरनेट डॉट ओआरजी' शुरू किया था। आकाशीय इंटरनेट के लिए सेटेलाइट भी छोड़े। असफल हुए। इसी तरह गूगल ने बैलून के जरिए इंटरनेट उपलब्धता का प्रयोग किया। उन्हें भी आशानुरूप सफलता नहीं मिली। इस क्षेत्र से दोनों ने अपने हाथ खींच लिए। उसके बाद स्पेसएक्स को सैकड़ों सेटेलाइट के जरिए आकाश से इंटरनेट सेवा देने में सफलता मिली। उसकी योजना 2,824 सेटेलाइट छोड़ने की है।

स्पेसएक्स दुनिया को अपने 'स्टार लिंक' प्रोजेक्ट से जोड़ना चाहती है, जो छोटी सेटेलाइटों का एक सिस्टम है। प्रोजेक्ट की पहली किस्त के तौर पर अमेरिकी क्षेत्र को कवर करने के लिए 60 सेटेलाइट को मई 2019 में छोड़ा जा चुका है। एशियाई देशों को ध्यान में रखकर भी पिछले दिनों सेटेलाइट छोड़े गए। अमेजन द्वारा भारत में हाई स्पीड सेटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को लाने की दौड़ में शामिल होने को वन-वेब और स्पेसएक्स के खिलाफ प्रतिस्पर्धा के नजरिए से देखा जा रहा है। अमेजन भारत में पहले से ही हाई स्पीड सेटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की योजना पर काम रहा है। इसके तहत अप्रैल 2019 में 'प्रोजेक्ट कुइपर' की नींव रखी गई थी। इसकी स्थापना तब ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक बड़े ब्रॉडबैंड उपग्रह इंटरनेट समूह को तैनात करने के लिए की गई थी। उन्हीं दिनों अमेजन ने घोषणा की थी कि वह इस परियोजना में उपग्रह इंटरनेट समूह को तैनात करने के लिए 10 अरब डॉलर का निवेश करते हुए कुल 3,236 सेटेलाइट लांच किए जाएंगे।

सेटेलाइट लांचिंग की तैयारी के बाद कानूनी वैधता हासिल करने के लिए अमेजन भारत सरकार के संपर्क में है। अमेजन को भारत में विदेशी उपग्रहों के संकेतों को डाउनलिंक करने के लिए लैंडिंग अधिकारों की भी आवश्यकता होगी, जो अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। साथ ही भारत में उसे अंतरिक्ष विभाग और दूरसंचार विभाग के साथ सहमति बनने एवं उनसे अनुमति मिलने पर ही वह भारत के लिए सेटेलाइट सर्विस का इस्तेमाल कर पाएगा। इसके लिए आवश्यक नियामक के अनुमोदन की जरूरत होगी और भारत के कानूनी दायरे में रहकर सेवाएं बहाल करने की इजाजत मिलेगी।

तकनीकी तौर पर समझें तो पाएंगे कि अमेजन एलईओ उपग्रहों का एक तारामंडल बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस पर खर्च की जाने वाली राशि में भारत में कितना निवेश होगा, इस बारे में अभी उसने कुछ नहीं कहा है।

आखिर आकाश से बेतार इंटरनेट देने के लिए इतनी होड़ क्यों मची हुई है? इसका जवाब स्पेसएक्स, अमेजन और गूगल के पास है। उसके अनुसार इसमें सफलता मिलने पर इंटरनेट कनेक्टिविटी संबंधी दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उनकी मंशा धरती के चप्पे-चप्पे को इंटरनेट से जोड़ना है। साथ ही, उसमें एकाधिकार वाले कारोबारी हित के छिपे होने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

बहरहाल, ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस की जब बात होती है तो विभिन्न देशों में इसकी उपलब्धता में काफी अंतर की भी चर्चा होती है। इस अंतर को खत्म करने के लिए आकाश से आने वाले वायरलेस इंटरनेट का दायरा बढ़ाया जा रहा है।

12 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र से उत्तराखंड में हटाई जाएंगी कुर्री (लैंटाना कमारा) की झाड़ियां। इनकी जगह होगा घास समेत बांस व अन्य प्रजातियों का रोपण।

बंगाल

शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में गड़बड़ी

बंगाल में पिछले करीब सात वर्षों में जब भी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसमें धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मामला कभी कलकत्ता हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। अभी पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में आगामी वर्ष मार्च से पहले 32 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की थी और साफ तौर पर कहा था कि यह नियुक्ति पूरी पारदर्शी और बिना किसी पैरवी और गड़बड़ी की होगी। परंतु, देखा जा रहा है कि उससे पहले ही उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतिरम रोक लगा दी है। साथ ही सात दिनों के भीतर प्राप्तांक सहित पूरी सूचना के साथ साक्षात्कारों की सूची प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है। वहीं जिनका आवेदन खारिज किया गया है, उन अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी कर अस्वीकृति का कारण बताना होगा।

न्यायाधीश ने कहा कि यह एसएससी बेकार है। इसे कौन से अधिकारी चला रहे हैं? आयोग को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इस मामले की जांच होनी चाहिए

मालूम हो कि हाई कोर्ट में शुक्रवार को उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मामले में गड़बड़ी को लेकर सुनवाई थी। इसी दौरान हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) बेकार बताते हुए कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ ने सुनवाई करते हुए आयोग की भूमिका पर सख्त नाराजगी जताई। साथ ही यह अनियमितताएं क्यों हुई है यह बताने के लिए एसएससी के अध्यक्ष को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो पीठ के समक्ष एसएससी का कोई अधिवक्ता मौजूद नहीं थे। इससे न्यायाधीश काफी क्षुब्ध हो गए। उन्होंने निर्देश दिया कि जब कोई अधिवक्ता नहीं है, तो एसएससी के अध्यक्ष को सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि यह एसएसी बेकार है। इसे कौन से अधिकारी चला रहे हैं? इस आयोग को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इससे पहले एक अक्टूबर 2019 को हुए साक्षात्कारों की सूची प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया गया था। हालांकि, उस निर्देश का पालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने आयोग से यह भी जानना चाहा है कि पहले दिए गए निर्देश का पालन क्यों नहीं हुआ?

यहां सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है। यदि सबकुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है तो फिर ऐसी अनियमितताएं क्यों हो रही हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसका पता लगाया जाना चाहिए और उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो यह सुनिश्चित होना चाहिए। इससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में भी मदद मिलेगी।

उत्तर प्रदेश

भारी पड़ती लापरवाही

कोरोना की दूसरी लहर के खात्मे पर पहुंचने के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में केस बढ़ना खतरनाक है। कोरोना मुक्त माने गए महोबा में 21 जून को एक भी केस नहीं था, मंगलवार को वहां भी आ गया। कासगंज में दो बचे थे, अब नौ हैं। कौशांबी में भी सक्रिय केस एक था, चार नए मरीज आ चुके हैं। बदायूं और हमीरपुर में छह से बढ़कर क्रमशः 16 और 12 केस हो चुके हैं। कानपुर देहात, चित्रकूट में भी संक्रमित बढ़े हैं। यह गंभीर लापरवाही का द्योतक है। दरअसल, आठ जून को पूरे प्रदेश से दिन का कर्फ्यू हटाते हुए सतर्कता बढ़ाने के निर्देशों का पालन जिला स्तरीय पुलिस-प्रशासनिक अफसरों को कराना था। उन्होंने कुछ कराया ही नहीं। हद यह भी कि लखनऊ में ही भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में जुटे समर्थकों ने मास्क और शारीरिक दूरी के मानकों की धज्जियां उड़ाईं।

संभवतः लापरवाही की ऐसी ही आशंका के कारण शासन ने शुक्रवार रात नौ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक का कर्फ्यू अब भी बरकरार रखा है। सप्ताहांत में बाजार और अन्य प्रतिष्ठान इसीलिए नहीं खुलने दिए जा रहे कि लोग कहीं छुट्टी मानकर भीड़ न जुटाने लग जाएं। वैसे, साप्ताहिक बंदी में भी बंदी जैसा कुछ नहीं दिख रहा। कर्फ्यू-मुक्त शेष पांच दिनों में भी बाजारों में इतनी भीड़ हो जा रही है कि पैदल चलना भी मुहाल है।


महामारी संबंधी दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से जारी रहना चाहिए। फाइल

राज्य सरकार प्रोटोकाल के अनुपालन की निगरानी के लिए मुख्यालय से टीम गठित करे, ताकि कोरोना महामारी को फिर से रौद्र रूप लेने से रोका जा सके

दुर्योग से कोई संक्रमित भी भीड़ में फंसा तो कितने लोगों तक वायरस पहुंच जाएगा, इसकी कल्पना ही कठिन है। यह भी संभव है कि लोगों को संक्रमण का पता ही न चले और वे अनजाने में ही कोरोना फैलाते रहें। वैक्सीन लगवाने या एक बार संक्रमण के बाद ऐसा होना आम बात है। यह स्थिति ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कोरोना प्रोटोकाल और गाइड लाइंस के पालन का निर्देश भर देकर चुप न बैठा जाए। राज्य सरकार प्रोटोकाल के अनुपालन की निगरानी के लिए मुख्यालय से टीम गठित करे, ताकि महामारी को फिर रौद्र रूप लेने से रोका जा सके। लापरवाही कोई भी करे, उसे कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए।

पंजाब

दूरदर्शिता की कमी

पंजाब में बिजली संकट चिंताजनक हालात में पहुंच गया है। इसका परिणाम यह है कि लगभग पूरे प्रदेश में लंबे बिजली कट लग रहे हैं। इससे लोगों के साथ ही किसान और उद्यमी भी परेशान हैं। संकट किस स्तर पर पहुंच गया है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार को आनन-फानन में बैठक बुलानी पड़ी और पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड को लोगों से अपील करनी पड़ी कि अगले तीन दिनों तक एसी सहित ज्यादा बिजली खपत वाले उपकरण न चलाएं। साथ ही प्रदेश में लार्ज इंडस्ट्री, फर्नेस इंडस्ट्री, इंडक्शन फर्नेस इंडस्ट्री और रोलिंग मिलों में दो दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में भी एसी न चलाने की अपील करनी पड़ी। हालत यह है कि पंजाब में बिजली की मांग रिकार्ड 14,500 मेगावाट के पार पहुंच गई है, जबकि पावरकाम के पास बिजली की उपलब्धता इससे करीब एक हजार मेगावाट कम की है। इससे मांग और वितरण में भारी अंतर आ गया है। हालांकि इसके पीछे कहीं न कहीं प्रदेश सरकार और पावरकाम की अदूरदर्शिता ही बड़ा कारण है। यह तो सर्वविदित है कि इस मौसम में एक तरफ जहां प्रचंड गर्मी पड़ती है, वहीं धान की रोपाई के कारण भी बिजली की खपत बढ़ जाती है। सरकार को इसके लिए पहले से ही प्रबंध करना चाहिए था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार और पावरकाम मानसून के भरोसे रहे। जब तक मानसून ने साथ दिया, तब तक सब ठीक रहा, जैसे ही मानसून ने मुंह फेरा, सरकारी प्रबंधों की कलई खुल गई। हैरत की बात यह भी है कि आखिर प्रदेश सरकार इस संकट को समय रहते क्यों नहीं समझ पाई? कहां तो प्रदेश में बिजली सरप्लस होने की बातें की जा रही थीं और अब हालत यह है कि खपत रोकने के लिए प्रतिबंध और अपील का सहारा लेना पड़ रहा है। सरकार और पावरकाम ने यदि समय रहते संकट को समझ लिया होता, तो संभवतः इसका कुछ न कुछ हल भी निकल आता। सरकार और पावरकाम को इस पर गहन मंथन की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में बिजली की मांग और बढ़ेगी। इसके अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव उपाय तत्काल किए जाने चाहिए। सरकार को बंद पड़े थर्मल प्लांटों को फिर से शुरू करने के साथ ही बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के अन्य उपायों पर भी गंभीरता से काम करना चाहिए।

सरकार और पावरकाम ने समय रहते बिजली संकट को समझ लिया होता, तो इसका कुछ न कुछ हल भी निकल आता


बिजली संकट का शीघ्र हल तलाशे सरकार। फाइल

उत्तराखंड

तीसरी लहर से निपटने की तैयारी

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश सरकार ने संक्रमण की रोकथाम को तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसका सबसे अधिक असर 18 वर्ष तक के आयु वर्ग में होने का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और पुख्ता स्वरूप दिया जा रहा है। इसके लिए शासन की तरफ से लगातार संबंधित दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर ये तैयारियां समय पर धरातल पर उतरती हैं तो निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने में राज्य को बड़ी मदद मिलेगी।

मालूम हो कि प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयुवर्ग की जनसंख्या तकरीबन 39.50 लाख है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य सुविधा जुटाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। विशेष रूप से 10 साल से कम आयु के बच्चों के लिए। दरअसल, स्वास्थ्य केंद्रों में जो उपकरण हैं, उनमें से अधिकांश उपकरण वयस्कों के लिए होते हैं। छोटे बच्चों के लिए उपकरण अलग आते हैं, चाहे आक्सीजन के लिए अथवा इंजेक्शन देने के लिए। यही कारण है कि अब इनकी खरीद पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों को स्वास्थ्य विभाग से बजट जारी किया गया है। बच्चों के साथ दूसरी सबसे बड़ी चुनौती उनकी देखभाल को लेकर है। इसका ध्यान रखते हुए अस्पतालों में बच्चों के साथ ही उनके अभिभावकों को रखने की व्यवस्था की जा रही है। इससे एक मरीज पर दोगुना जगह का इस्तेमाल होगा। यह एक ऐसा विषय है जिस पर स्वास्थ्य विभाग लगातार मंथन कर इसका समाधान करने का प्रयास कर रहा है। 18 वर्ष तक आयुवर्ग के लिए पेड्रियाटिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीकू) और नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (निकू) वार्ड बनाए जा रहे हैं। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं की खरीद की जा रही है। दूसरी लहर में पर्वतीय क्षेत्र में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस बार ब्लाक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक में आक्सीजन बेड बनाए जा रहे है। जिला अस्पतालों में आक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाए गए हैं। निश्चित तौर पर ये तैयारियां कुछ राहत देती नजर आ रही हैं। सरकार को चाहिए कि वह इन तैयारियों को जल्द धरातल पर उतारने की व्यवस्था सुनिश्चित करे, ताकि दूसरी लहर की तरह मरीजों को बेड के लिए न भटकना पड़े।

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार द्वारा की जा रही तैयारी यदि समय से धरातल पर उतरती है तो संक्रमण के असर को कम करने में खासी मदद मिलेगी

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि सरकार की तैयारी अपनी जगह, मगर अभिभावकों को भी संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए पूरी तरह जागरूक होना पड़ेगा।

दो से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ा और कठोर कदम उठाने की तैयारी में है। पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरियों के चुनाव में दो से अधिक बच्चे वालों को अयोग्य घोषित करने का मसौदा तैयार कर रहा है। सरकार यह प्रविधान इस बार के पंचायत चुनाव में लागू नहीं करेगी, लेकिन किसी कारणवश अगर चुनाव टलता है तो फिर दो से अधिक बच्चे वालों पर नए कानून की गाज गिरनी तय है। अगर इस बार चुनाव में उम्मीदवारों को इस प्रविधान से मोहलत मिल जाती है, तो भी पांच साल बाद यानी 2026 के पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले लोग दावेदारी नहीं कर पाएंगे।

सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गंभीर: पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गंभीर है। जनता को जागरूक करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से उम्दा माध्यम कोई और नहीं हो सकता है। पंचायती राज कानून-2006 में संशोधन किया जाएगा। वर्तमान में पंचायती राज नियमावली में इस तरह का कोई प्रविधान नहीं है। कानून में संशोधन के बाद सरकार इसे लागू करने में नियमानुसार एक वर्ष का समय लेगी।

बिहार में सख्ती

- पंचायती राज कानून में सरकार करने जा रही संशोधन, 2026 के चुनाव से प्रभावी होगी व्यवस्था
- पंचायतों में नया नियम लागू कर जनता को संदेश देना है उद्देश्य

12 करोड़ लोगों को मिलेगा संदेश

सरकार का मानना है कि 2016 के पंचायत और ग्राम कचहरियों के चुनाव में 2.60 लाख पदों के लिए 10 लाख से अधिक प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया था। ऐसे में देखा जाए तो कानून में संशोधन से बिहार के 12 करोड़ लोगों में बड़ा संदेश जाएगा।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों और ग्राम कचहरियों में दो से अधिक बच्चे वालों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने पर सरकार विचार कर रही है। हालांकि 2021 के पंचायत चुनाव को इससे मुक्त रखा जाएगा।
– सम्राट चौधरी, पंचायती राज मंत्री, बिहार

स्वदेशी को सलाम : भारतीय तोड़ से बनारस में टूट रही चीनी रेशम की डोर

मुहम्मद रईस, वाराणसी

गलवन घाटी में तनाव और फिर कोरोना महामारी के घाव के चलते चीन को लेकर उपजा आक्रोश बनारस और चीन के बीच रेशमी रिश्ते की डोर तोड़ रहा है। इस पर सरकार द्वारा दस फीसद इंपोर्ट ड्यूटी लगाने और भारतीय रेशम बाजार में छूट के साथ भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो जाने से बुनकरों व कारोबारियों का चीनी रेशम से मोह भंग हो चुका है। इससे बनारस में चीन के रेशम का आयात लगभग बंद हो चला है। उसके स्थान पर अब करघे पर बेंगलुरु का स्वदेशी रेशम बनारसी साड़ियों का रंग चटख कर रहा है। स्थानीय बुनकर मोहम्मद स्वालेह अंसारी कहते हैं, चीनी रेशम की तानी जरूर बेहतर होती है, जबकि बाने में इसका प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता।

वहीं बेंगलुरु के रेशम से तैयार वस्त्र छह महीना या साल भर रख कर भी बेचना पड़े तो गुणवत्ता बनी रहती है और पूरा दाम भी मिल जाता है। यह सबक कोरोना काल ने सिखा दिया है, जिसमें बड़ा स्टाक बुनकरों के कारखाने में या गद्दीदारों के गोदाम में रखा रह गया था। ऐसे में समझा जा सकता है कि बेंगलुरु के रेशम से बना उत्पाद ग्राहक के पास जाने के बाद भी लंबे समय तक बना रहेगा।

दरअसल, बेंगलुरु से आने वाले रेशम पर उप्र सरकार की ओर से बुनकरों को 10 फीसद की छूट भी दी जा रही है। इस तरह यह चीनी रेशम के मुकाबले प्रति किलोग्राम करीब 1200 रुपये तक सस्ता भी पड़ रहा है। हालांकि एक बुनकर को एक माह में चार किलोग्राम तक ही रेशम देने का प्रविधान है। इससे अधिक की जरूरत की स्थिति में वियतनाम का ड्यूटी फ्री रेशम भी विकल्प बनता जा रहा है यही नहीं, सस्ते के चक्कर से निकलने के बाद स्थानीय बुनकरों को एक बात और समझ में आई जो भारत की पहचान से जुड़े हस्तशिल्प की साख पर बट्टा लगा रही थी।

बदलाव

- स्वदेशी रेशम पर 10 फीसद छूट से वस्त्र कारोबार को मिल रही गति
- एक साल तक गुणवत्ता खराब नहीं होती बेंगलुरु के रेशम की
- कोरोना काल ने भी बुनकरों का चीनी धागा से मोह भंग कराया

दूसरे पहलू पर भी करें विचार

हालांकि स्टेट अवार्डी बुनकर विजय कुमार मौर्या का मानना है कि वैश्विक बाजार में चीन भारतीय वस्त्र कारोबार को चुनौती दे रहा है। चीनी रेशम, वियतनाम व बेंगलुरु के मुकाबले बेहतर है। महंगा होने के चलते इसका उपयोग बनारसी वस्त्र में लगभग शून्य हो गया है। इसका असर बनारसी वस्त्र की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। इंपोर्ट ड्यूटी हटा लेने से बुनकरों के सामने तीनों का विकल्प होगा। इससे बुनकर जहां वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहेंगे, निर्यात की मांग भी बनी रहेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी।

कारखानों से गायब हो गया चीनी रेशम

रेशमी तागा संघ के सरंक्षक व उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष मोहन लाल सरावगी आंकड़ों से स्पष्ट करते हैं कि चीन के रेशम की कीमत 4500 है जो ड्यूटी व अन्य खर्च मिलाकर 5100 रुपये प्रति किलोग्राम पड़ रहा है। वहीं वियतनाम के रेशम का भाव 4100 से 4400 रुपये प्रति किलोग्राम तक में मिल जा रहा है। इसलिए कोरोना काल में वियतनाम से 20 और बेंगलुरु से करीब 15 टन रेशम की आवक होती रही। अब हालात सामान्य हो रहे तो खपत 60 टन तक जाने की संभावना है। कोरोना काल से पहले तक बनारस में 250 टन रेशम की खपत थी, जिसमें 150 टन से अधिक चीनी रेशम ही होता था। अब सिल्क साड़ियों में मिलावट के कारण खपत करीब 75 फीसद तक घट गई है, लेकिन चीन का रेशम कारखानों से लगभग गायब है।

डाकिया घर पहुंच कर बच्चों का बनाएंगे आधार कार्ड

जागरण संवाददाता, बरेली

पांच वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ सूचना देनी होगी। इसके बाद डाकिया आपके घर आकर बच्चों का आधार कार्ड बना देगा। देश भर में यह सुविधा जल्द लागू करने की तैयारी है। इसके लिए डाकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पांच वर्ष आयु तक के बच्चों के आधार कार्ड बनाने की शुरुआत कब से होगी, इसकी तारीख तय नहीं हुई है। मगर, विभागीय अधिकारी मानते हैं कि सात जुलाई से इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय स्तर से मिले संकेत के बाद उसी अनुसार डाकियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह व्यवस्था दो चरण की होगी। सभी डाकघरों में बच्चों के लिए विशेष काउंटर बना दिए जाएंगे। जो अभिभावक वहां आना चाहते हैं तो बच्चों के आधार कार्ड बना दिए जाएंगे। दूसरी व्यवस्था के तहत डाकिया घरों तक जाकर भी आधार कार्ड बनाएंगे।

इस तरह बनेगा कार्ड : डाकियों को स्मार्ट फोन व अंगुली का निशान लेने वाली मशीन दी जा रही है। फोन में डाक विभाग की विशेष एप्लीकेशन होगी। अभिभावक की सूचना पर डाकिया उनके घर पहुंचेंगे। मोबाइल एप संचालन के लिए उनकी लागिन आइडी बनाई गई है, जिससे वे एप्लीकेशन खोलेंगे। उसमें बच्चे का नाम, पता जन्मतिथि आदि ब्योरा दर्ज करेंगे। मोबाइल फोन से अंगुली का निशान लेने वाली मशीन को कनेक्ट कर बच्चे के निशान लेंगे। बच्चों का रेटीना निशान नहीं लिया जाता, इसलिए रेटीना मशीन की जरूरत नहीं होगी। पांच से आठ मिनट में आधार कार्ड आवेदन की प्रक्रिया एप्लीकेशन में दर्ज हो जाएगी। इसके बाद छह से आठ दिन में आधार कार्ड मिल जाएगा। इसके लिए अभिभावक को कोई शुल्क नहीं देना होगा। जो लोग अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हैं, उन्हें भी यह सुविधा मिलेगी। इसके लिए 50 रुपये शुल्क देना होगा। बरेली मंडल के 430 डाकियों को इसके लिए लागिन आइडी दे दी गई है। तारीख तय होते ही इस योजना के तहत डाकिया काम शुरू कर देंगे। इससे लोगों को बहुत सुविधा होगी।

तैयारी

- नि:शुल्क मिलेगी सुविधा, डाकिया तक पहुंचानी होगी सूचना
- डाक विभाग की एप के जरिये होगी प्रक्रिया, दिया जा रहा प्रशिक्षण

बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष योजना शुरू की जानी है, जिसकी तैयारियां हो रही हैं। तारीख तय होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
–पीके सिंह, प्रवर डाक अधीक्षक, बरेली

गीर वन में सात सौ से ज्यादा हुए एशियाई शेर

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

- सरकार ने शेरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संरक्षित वन का क्षेत्रफल बढ़ाया

गुजरात के गीर वन में एशियाई शेरों की संख्या सात सौ के पार हो गई है। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल शेरों की गणना नहीं की जा सकी थी, लेकिन इस साल मई-जून में पूर्णिमा अवलोकन (ब्लाक काउंट मेथड) से वनकर्मियों ने शेरों की गणना की।

सौराष्ट्र स्थित गीर जंगल एशियाई शेरों की शरणस्थली है। वर्ष 2015 में यहां शेरों की संख्या 523 थी, जो अब बढ़कर 710 से 730 के बीच जा पहुंची है। वन मंत्री गणपतसिंह वसावा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गीर जंगल में शेरों की संख्या सात सौ के पार हो गई है। सरकार ने शेरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इनके लिए संरक्षित वन के क्षेत्रफल को 22 हजार वर्ग किमी से बढ़ाकर 30 हजार वर्ग किमी कर दिया है। गीर जंगल में हर पांच साल में शेरों की गणना होती है तथा हर साल पूनम अवलोकन (ब्लाक काउंट मेथड) के जरिये शेरों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। इसमें पूर्णिमा को दोपहर दो बजे से अगले दिन दोपहर दो बजे तक वन विभाग के अधिकारी और क्षेत्रीय कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र में शेरों की संख्या और उनकी अवस्थिति के आंकड़े दर्ज करते हैं। ब्लाक काउंट मेथड के कारण इसमें नर एवं मादा की गणना अलग-अलग नहीं की जाती है। बीते साल यह गणना नहीं हो सकी थी। लेकिन इस साल वनकर्मी तथा गीर जंगल के बीट स्टाफ ने मिलकर इस गणना को पूरा किया। गीर जंगल के बाहर 2015 में 167 शेर निवास करते थे, जबकि 2021 में माना जा रहा है कि इनकी संख्या 329 तक पहुंच गई है। जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2020 के बीच गीर जंगल में 313 शेर व उनके शावकों की विभिन्न कारणों से मौत हुई। इसके बावजूद उनकी संख्या सात सौ के पार पहुंच गई है।

गीर नेशनल पार्क एवं अभयारण्य में इनकी संख्या सबसे अधिक 334 आंकी गई है, जबकि पानिया अभयारण्य में 10, मितियाला में 16, गीमर अभयारण्य में 56, दक्षिण-पश्चिम किनारे पर 20, दक्षिण-पूर्वी किनारे पर 67, सावरकुंडला लिलिया जंगल में 98, भावनगर मुख्य जंगल में 56 तथा भावनगर सीमावर्ती क्षेत्र में शेरों की संख्या 17 आंकी गई है।

सलई का गोंद बदलेगा आदिवासियों की किस्मत

मप्र में एक कंपनी लगवा रही पेड़ जिनपर आदिवासियों का होगा हक, एक पेड़ से एक माह में निकलता है करीब 50 किलो गोंद

जागरण विशेष

मनोज श्रीवास्तव • ग्वालियर

मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के जंगल में पाए जाने वाले सलई के पेड़ से निकलने वाला गोंद आदिवासियों की किस्मत बदलेगा। इस सुगंधित गोंद का उपयोग दवा व परफ्यूम आदि में किया जाता है। इसे देखते हुए गोंद का उत्पादन बढ़ाने के लिए गुजरात की फार्माजा हर्बल कंपनी इन आदिवासियों के साथ आई है।

कंपनी ने वन समितियों के माध्यम से ओछापुरा क्षेत्र में 25 हेक्टेयर में सलई के पौधों का रोपण शुरू किया है। यह पौधे आदिवासी जंगल से लाकर रोप रहे हैं। कंपनी पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा पर प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तीन साल तक खर्च करेगी। पहले साल के लिए रुपये दिए जा चुके हैं। पेड़ बड़े होने के बाद इन्हें आदिवासियों को सौंप दिया जाएगा। आदिवासी इनसे निकलने वाला गोंद बेच सकेंगे।

गुजरात की कंपनी ने सलई के पेड़ लगाने का काम अपने सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम (सीएसआर प्रोग्राम) के तहत शुरू किया है। उसने पेड़ तैयार होने के बाद उनको वन समितियों के माध्यम से जंगल में रहने वाले आदिवासी परिवारों के सुपुर्द करने की बात कही है। आदिवासी परिवार ही पेड़ों से गोंद निकालेंगे और बाजार या कंपनी को बेच सकेंगे। इससे आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

गिरवी रखते हैं पेड़

पारंपरिक रूप से सलई के पेड़ों पर आदिवासियों का एकाधिकार माना जाता है। किसी पेड़ पर मालिकाना हक आदिवासियों का मुखिया सबकी सहमति से तय करता है। एक पूर्ण विकसित पेड़ से एक माह में आसानी से 50 किलो तक गोंद निकल आता है। बाजार में एक किलो गेंद की कीमत करीब 400 रुपये तक होती है। ऐसे में जिस आदिवासी के पास कोई पेड़ होता है तो वह जरूरत पड़ने पर उसे गिरवी भी रख सकता है। जब तक कर्ज नहीं पट जाता तब तक गोंद को निकालकर बेचने का काम कर्जदाता ही करता है।



गुजरात की कंपनी ओछापुरा में 25 हेक्टेयर में सलई के पेड़ वन समितियों के माध्यम से लगवा रही है। सलई का गोंद सुगंधित होता है। इसका उपयोग दवा के साथ-साथ परफ्यूम आदि बनाने में किया जाता है। ऐसे में औषधियों का व्यापार करने वाली कंपनी के आदिवासियों से जुड़ने से आदिवासियों को फायदा होगा। – **सुधांशु यादव**, डीएफओ, सामान्य वन मंडल, श्योपुर

सलई के पेड़ हमारे लिए बेहद अहम हैं। इससे निकलने वाले गोंद से हमारी आजीविका चलती है। बेटी की शादी में भी हम वर पक्ष को उपहार में पेड़ देते हैं, जिससे बेटी आर्थिक रूप से परेशान नहीं हो। संकट के समय हम इन पेड़ों को गिरवी रखकर कर्जा भी ले लेते हैं। अब कंपनी हमें सहयोग कर रही है तो इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर और गोंद को बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।
श्रीनिवास आदिवासी,
ओछापुरा, श्योपुर


सलई के पेड़ के पास खड़ा श्रीनिवास आदिवासी • नईदुनिया

ऐसे निकालते हैं इन पेड़ों से गोंद: छह से आठ माह में सलई का पेड़ बड़ा हो जाता है। गोंद निकालने के लिए पेड़ के तने को चारों ओर छील दिया जाता है। ऐसा निचले हिस्से में दो से तीन फीट ऊंचाई तक किया जाता है। आठ से 10 दिन के बाद इससे गोंद निकलना शुरू हो जाता है। हालांकि, पूर्णरूप से पेड़ को विकसित होने में करीब दो साल लग जाते हैं।

शादी में उपहार में भी देते हैं पेड़: जंगल में खड़े सलई के पेड़ों को आदिवासी अपनी संपत्ति मानते हैं। चूंकि, इन पेड़ों से गोंद निकलने से उन्हें रोजगार मिलता है, इसलिए वे इन्हें तस्करों से बचाते भी हैं। बेटी की शादी में वर पक्ष को उपहार के रूप में भी पेड़ देते हैं, जिससे उनकी बेटी आर्थिक रूप से परेशान न रहे।

इसलिए वन विभाग को नहीं है कोई आपत्ति: पेड़ को शादी में उपहार में देने और जरूरत पड़ने पर गिरवी रखने को लेकर वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि यह आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था है। चूंकि, पेड़ काटे नहीं जाते और न ही जंगल को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए उपहार में देने और गिरवी रखने पर उसे आपत्ति नहीं होती।

3 बच्चों की मौत हो गई है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवां प्रांत में एक हैंड ग्रेनेड से गेंद की तरह खेलने के दौरान हुए धमाके में। बताया जाता है कि एक ही महीने के अंदर पाकिस्तान में यह ऐसी दूसरी घटना है।

अमेरिका ने 20 साल बाद छोड़ा अफगानिस्तान का प्रमुख बेस

युद्धविराम ▸ सैनिकों की वापसी के बीच बगराम एयरबेस अफगान सेना को सौंपा

बलों की रक्षा का अधिकार अभी भी जनरल ऑस्टिन एस. मिलर के पास हैं

काबुल, एपी : अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना और नाटो ने कूच कर दिया है। इसी कड़ी में अमेरिकी सेना ने करीब 20 साल के बाद अफगानिस्तान के सबसे प्रमुख बगराम एयरबेस को छोड़ दिया है। यह एयरबेस तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए हुए युद्ध और अमेरिका पर 9/11 में हुए आतंकवादी हमले के जिम्मेदार अलकायदा के साजिशकर्ताओं की धर-पकड़ के लिए अमेरिकी सेना का केंद्र रहा था।

अमेरिका के दो अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एयरफील्ड 'अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा बल' को पूरी तरह से सौंप दिया गया है। रायटर एजेंसी के मुताबिक इसका औपचारिक एलान शनिवार को होगा। एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों की रक्षा का अधिकार और क्षमताएं अभी भी अफगानिस्तान में अमेरिका के शीर्ष कमांडर जनरल ऑस्टिन एस. मिलर के पास हैं। उनके पास हवाई हमले करने के भी विकल्प मौजूद रहेंगे। अधिकारी ने अपनी पहचान ना बताने की शर्त पर कहा, 'गठबंधन की पूरी सेना ने बगराम को छोड़ दिया है।' हिंदूकुश की पहाड़ियों से घिरा यह एयरबेस काबुल के 50 किमी उत्तर में स्थित है जो पूरे अफगान मिशन का मुख्य केंद्र रहा है। बीस साल बाद अमेरिकी सेना की वापसी की घोषणा से यह साफ है कि अफगानिस्तान में 2500-3500 अमेरिकी सैनिकों की आखिरी टुकड़ी भी अफगानिस्तान छोड़ चुकी है या फिर कूच करने वाली है। हालांकि सभी सैनिकों के चार जुलाई तक अफगानिस्तान छोड़ देने की उम्मीद है। ध्यान रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने चुनाव जीतने के बाद वादा किया था कि अमेरिकी सैनिक 11 सितंबर से पहले अफगानिस्तान से जा चुके होंगे।

इस बीच, रूस ने कहा कि आतंकी संगठन आइएस ने उत्तर अफगानिस्तान में अपने पैर पसारने की कोशिश की है।


अफगानिस्तान के परवान प्रांत में स्थित अमेरिकी सेना के सबसे अहम बगराम एयरबेस पर सुरक्षा में तैनात अफगानी सैनिक। रायटर

तालिबान बढ़ा रहा ताकत

वहीं अफगानिस्तान में तालिबान अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। इसने सैनिकों की वापसी वाली अमेरिकी घोषणा के बाद से ही अफगानिस्तान में बम से हमले तेज कर दिए। इसमें सैनिकों, आम नागरिकों और मुख्य तौर पर महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे ही दो नए हमलों में कुल 14 लोग मारे गए हैं। इसके साथ ही देश के कई बड़े हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया गया। हालांकि बगराम एयरफील्ड पर अगर अफगानी सैनिक तैनात रहते हैं, तो वह पास में स्थित राजधानी काबुल की रक्षा कर पाएंगे और उन्हें तालिबान पर भी दबाव बनाए रखने में मदद मिलेगी।

अमेरिका में भारत के राजदूत संधू व्हाइट हाउस के फेलो से मिले

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों से गहन विचार-विमर्श किया है। उन्होंने कूटनीतिक जटिलताओं के साथ ही दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच संबंधों पर भी चर्चा की।


तरणजीत सिंह संधू

इसके बाद संधू ने ट्वीट करके बताया कि व्हाइट हाउस परिसर के एसिनहावर एक्जिक्यूटिव आफिस बिल्डिंग में व्हाइट हाउस के अधिकारियों से बातचीत काफी फलदायी रही है। उन्होंने कहा कि कूटनीति से लेकर भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय विकास, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, पर्यावरण, आइटी और शिक्षा से बात हुई। यह सभी युवा अमेरिकी अधिकारी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना दखल रखते हैं। उल्लेखनीय है कि व्हाइट हाउस फेलोशिप की स्थापना 1964 में हुई थी।

न्यूज गैलरी

यूएई ने अपने नागरिकों को भारत जाने से रोका

दुबई : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार ने शुक्रवार से अपने नागरिकों पर भारत और पाकिस्तान समेत कुल 14 देशों में यात्रा करने से रोक लगा दी है। ताकि वैश्विक महामारी कोविड-19 को यूएई में पांव पसारने से रोका जा सके। यह रोक कब तक रहेगी यह भी अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। इससे अंतरराष्ट्रीय उड़ाने भी नहीं जा सकेंगी। यूएई के विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा संकट व आपदा प्रबंधन के मुताबिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया समेत 14 देशों में यूएई के नागरिकों को जाने से रोका गया है। (प्रेट्र)

नेपाल को भारत से चाहिए और 10 लाख वैक्सीन

नई दिल्ली : नेपाल को अभी भी भारत से कोविड-19 की 10 लाख वैक्सीन मिलनी बाकी हैं, जोकि उसने पहले से ही खरीदी हुई हैं। भारत में नेपाल के राजदूत निलांबर आचार्य ने नेपाल में वैक्सीन की किल्लत पर चिंता जताते हुए कहा कि हम इस संबंध में लगातार भारत सरकार और वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि नेपाल सरकार ने वैक्सीन के लिए भारत को कुल बीस लाख वैक्सीनों के लिए रकम अदा की है। लेकिन उसे अभी तक दस लाख वैक्सीन ही मिल पाई हैं। भारत ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते अप्रैल के महीने में अन्य देशों को वैक्सीन की आपूर्ति बंद कर दी थी। (एएनआइ)

चीन के परमाणु हथियारों से अमेरिका चिंतित

वाशिंगटन, एएनआइ : चीन के परमाणु हथियारों के निर्माण पर अमेरिका ने चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि चीन परमाणु शक्ति के मामले में पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ा है। इसका गलत इस्तेमाल शांति के लिए खतरा पैदा कर सकता है। चीन ने हाल ही में सौ से अधिक नई मिसाइलों को तैयार कर बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।

चीन सरकार के 100 से अधिक परमाणु मिसाइल साइलो बनाए जाने पर विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि चीन की परमाणु शक्ति पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ी है। चीन के परमाणु निर्माण हथियारों पर नियंत्रण करने के लिए प्राइस ने दुनिया के सभी देशों को आगे आने का आग्रह किया।

दुनिया के लिए खतरा

- अमेरिकी सरकार चीन के मिसाइल प्रतिष्ठानों के निर्माण से परेशान
- विदेश प्रवक्ता बोले- इसे नियंत्रित करने के लिए सभी को आना होगा आगे


नेड प्राइस। फाइल/इंटरनेट मीडिया

100 से अधिक नए साइलों को कर रहा है तैयार

चीनी नौसेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। चीन इतना ताकतवर हो चुका है कि वह अमेरिका को भी चुनौती दे सकता है। इस बात का अमेरिका को भी भान है। अमेरिका लगातार चीन की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। ड्रैगन इन दिनों तेजी से अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ाने में जुटा हुआ है। हाल की सेटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन उत्तर-पश्चिम शहर युमेन के पास एक रेगिस्तान में इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 100 से अधिक नए साइलों को तैयार कर रहा है। साइलो एक तरह का स्टोरेज कंटेनर होता है, जिसमें लंबी दूरी की मिसाइलों को रखा जाता है।

टैक्स चोरी में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ीं, सीएफओ आरोपित

▸ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप को राजनीति से प्रेरित बताया

न्यूयॉर्क, एपी : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी टैक्स चोरी में फंस गई है। इसके चलते ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही वर्ष 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की उनकी संभावनाओं पर भी पानी फिर सकता है। ट्रंप ने टैक्स चोरी के आरोप को राजनीति से प्रेरित बताया है।

टैक्स चोरी के मामले में ट्रंप आर्गनाइजेशन के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) एलन वीसेलबर्ग को आरोपित किया है। हालांकि इस मामले में ट्रंप पर अभी कोई आरोप नहीं लगाया गया है। लेकिन अभियोजकों का कहना है कि टैक्स गड़बड़ी से जुड़े इस मामले में जारी कई चेक पर ट्रंप के हस्ताक्षर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मामले में ट्रंप के वफादार रहे कंपनी के सीएफओ एलन फंसे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की कारोबारी गतिविधियों की दो साल तक चली जांच के बाद न्यूयॉर्क के अभियोजन अधिकारी ने यह आपराधिक मामला दर्ज किया है। यह मामला मैनहटन की अदालत में चल रहा है। अभियोग के अनुसार, 2005 से लेकर इस वर्ष तक ट्रंप आर्गनाइजेशन और सीएफओ ने कर अधिकारियों को धोखा दिया। 73 वर्षीय एलन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सरकार के साथ टैक्स के तौर पर नौ लाख डॉलर (करीब छह करोड़ 70 लाख रुपये) की धोखाधड़ी की। इस आरोप में एलन को 15 साल तक की सजा हो सकती है। एलन करीब पांच दशक से कंपनी के वित्तीय मामलों को देखते रहे हैं।


डोनाल्ड ट्रंप। फाइल/ इंटरनेट मीडिया

विद्या, एकता व शोभा कपूर बनीं ऑस्कर कमेटी की सदस्य

लास एंजिलिस, प्रेट्र : वर्ष 2021 के ऑस्कर अवार्ड की कमेटी में कुल 395 सदस्यों में बालीवुड की अभिनेत्री विद्या बालन और मां-बेटी की फिल्म निर्माता जोड़ी शोभा कपूर और एकता कपूर को भी शामिल हैं।

सिनेमा जगत के सबसे बड़े अवॉर्ड माने जाने वाले ऑस्कर की गवर्निंग बाडी द एकेडमी आफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने इस साल 395 फिल्म उद्योग की हस्तियों को शामिल किया है। इसमें दुनिया भर से फिल्म अभिनेता व अभिनेत्रियों, निर्माताओं, निर्देशकों और फिल्मों से जुड़े विभिन्न तरह के तकनीशियनों को शामिल किया गया है। इन 395 नामों में बालीवुड से विद्या बालन, एकता कपूर और शोभा कपूर शामिल हैं।

एकेडमी ने साल 2016 में दुनिया भर से रिकार्ड 928 लोगों को कमेटी में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा था। इनमें भारत से शाहरुख खान, दिवंगत सौमित्र चटर्जी, तब्बू, आदित्य चोपड़ा नसीरुद्दीन शाह, डॉली अहलूवालिया, बल्लू सलूजा, अनिल मेहता, मेहदाबी मुखर्जी जैसे नाम शुमार थे। इसके बाद साल 2020 में भी ऑस्कर कमेटी की तरफ से कई भारतीय फिल्मकारों और तकनीशियनों को कमेटी में शामिल होने का निमंत्रण मिला था।

इस सूची की अन्य मशहूर हस्तियों की बात करें तो इसमें रॉबर्ट पैटिसन, लावेरने कॉक्स, वैनिसा किर्बी, स्टीवेन यून जैसे नाम शामिल हैं। ऑस्कर के लिए फिल्मों की वोटिंग करने के लिए तैयार की गई 2021 की इस क्लास में 46 फीसद महिलाएं, 39 फीसद अंडर रिप्रेजेंटेड समूहों और 53 फीसद दुनिया भर के 50 देशों से लोग शामिल किए गए। आपको बता दें कि इन दिनों विद्या फिल्म 'शेरनी' को लेकर चर्चाओं में हैं। फिल्म हाल ही में अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है। एकेडमी ने इस साल अपनी गवर्निंग बॉडी की जिस सूची में विद्या बालन को शामिल किया है, उसमें विद्या के नाम के आगे उनकी दो बेहद चर्चित फिल्मों- 'कहानी' और 'तुम्हारी सुल्लु' का जिक्र किया गया है। वहीं, एकता कपूर और शोभा कपूर दोनों ही बालीवुड और टीवी जगत की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर्स की सूची में शामिल हैं। उन्होंने द डर्टी पिक्चर, ड्रीम गर्ल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उड़ता पंजाब जैसी कई सुपरहिट फिल्में प्रोड्यूस की हैं।

▸ कमेटी में 50 देशों की 395 हस्तियों को किया गया शामिल


अभिनेत्री विद्या बालन। जागरण आर्काइव

▸ एकेडमी ने 2016 में रिकार्ड 928 लोगों को भेजा था निमंत्रण


एकता कपूर। जागरण आर्काइव

▸ 2020 में भी कई भारतीय फिल्मकारों और तकनीशियनों को निमंत्रण मिला था


शोभा कपूर। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

कनाडा में गिराई गईं विक्टोरिया और एलिजाबेथ की प्रतिमाएं

● पुराने आवासीय स्कूलों में बच्चों के अवशेष मिलने से आक्रोश

विनिपेग, रायटर : कनाडा में पुराने आवासीय स्कूलों में मिलीं कब्रों से सैकड़ों बच्चों के अवशेष पाए जाने से लोगों में गुस्सा है। इसके विरोध में विनिपेग शहर में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने महारानी विक्टोरिया व एलिजाबेथ द्वितीय की प्रतिमाएं गिरा दीं।

प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने गुरुवार को प्रतिमाओं को ढहाने से पहले जमकर नारेबाजी की। 'नरसंहार में कोई गर्व नहीं' जैसे नारे लगाए। यह घटना ऐसे दिन हुई, जब देशभर में एक जुलाई को कनाडा दिवस मनाया जाता है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया और सैसकैचवेन प्रांतों में पूर्व के आवासीय स्कूलों में करीब एक हजार कब्रें मिली हैं। इन स्कूलों का संचालन कैथोलिक चर्च की ओर से किया जाता था। इसकी जांच करने वाले आयोग ने बताया था कि ये स्कूल मूल निवासियों के बच्चों को उनके परिवारों से जबरन अलग कर देते थे। वे न सिर्फ कुपोषण का शिकार होते थे बल्कि उनका यौन शोषण भी किया जाता था। इस तरह का कृत्य 165 वर्षों से चल रहा था और 1996 तक जारी रहा। कनाडा दिवस पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने संदेश में कहा कि पूर्व के स्कूलों से बच्चों के अवशेष मिलने से जाहिर होता है कि देश में अन्याय का अस्तित्व अब भी है।


कनाडा में पुराने आवासीय स्कूलों में अज्ञात कब्रें मिलने से आक्रोशित लोगों ने देशभर में एवरी चाइल्ड मैटर्स रैलियां निकालीं। रायटर

मालदीव में मीडिया के दुष्प्रचार से भारतीय उच्चायोग आहत

माले, एएनआइ : मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने स्थानीय मीडिया और इंटरनेट मीडिया की भूमिका पर नाखुशी जाहिर की है। दोनों मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय उच्चायुक्त और अन्य अधिकारियों के खिलाफ व्यक्तिगत अपमानजनक हमले किए जा रहे हैं। सभ्यता की सीमा से परे जाकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। इससे मालदीव में रह रहे भारतीय आहत हैं।

भारतीय उच्चायोग ने पिछले सप्ताह इस दुष्प्रचार पर मालदीव के विदेश मंत्रालय से लिखित शिकायत की थी। अनुरोध किया था कि इस तरह के दुष्प्रचार पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। पता चला है कि मालदीव सरकार ने इस पत्र को गंभीरता से लिया है। उसने अखबारों और न्यूज वेबसाइटों की गैर जिम्मेदाराना और शरारतपूर्ण रिपोर्टिंग का संज्ञान लिया है।

सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति इब्राहीम सोलिह के कार्यकाल में भारत और मालदीव के संबंध काफी प्रगाढ़ हुए हैं। भारत के सहयोग से वहां पर बड़ी संख्या में विकास कार्य किए जा रहे हैं। ये विकास कार्य सफल भी रहे हैं और उनसे जनता को लाभ भी हो रहा है।

भारत समेत 130 देशों ने किया वैश्विक न्यूनतम कर समझौता

▸ इस समझौते पर बरमुडा व केमन आइलैंड जैसे टैक्स हैवेन देशों ने भी किए दस्तखत

फ्रैंकफर्ट (जर्मनी), एपी : भारत समेत लगभग 130 देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा समर्थित वैश्विक न्यूनतम कर पर सहमति जताई है। इस समझौते पर भारत चीन जैसी आर्थिक महाशक्तियों के साथ बरमुडा और केमन आइलैंड जैसे टैक्स हैवेन देशों ने भी दस्तखत किए हैं। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम दरों वाले देशों में अपने मुनाफे को स्थानांतरित करके कर देनदारी से बचने से रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर जारी प्रयास के बीच इन देशों ने कर लगाए जाने का समर्थन किया है।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने गुरुवार को समझौते की घोषणा की। समझौते में उन देशों में वैश्विक कंपनियों पर भी कर लगाने की बात कही गई है, जहां वे ऑनलाइन कारोबार के जरिये मुनाफा कमाते हैं लेकिन भौतिक रूप से उनकी मौजूदगी नहीं है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा कम-से-कम 15 प्रतिशत की दर से कर लगाने के प्रस्ताव के बाद यह समझौता सामने आया है। अमेरिकी प्रस्ताव से इस मामले में बातचीत में तेजी आई है।

अब इस समझौते पर इस साल जी-20 देशों की बैठक में चर्चा की जाएगी। उम्मीद है कि इस संदर्भ में विस्तृत ब्योरा अक्टूबर में तैयार कर लिया जाएगा और समझौते को 2023 में लागू किया जाएगा।

पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा घोषित समझौता, उन देशों में सबसे बड़ी वैश्विक कंपनियों के मुनाफे के हिस्से पर कर लगाने का प्रविधान करता है, जहां वे आनलाइन व्यापार तो करते हैं लेकिन उनकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती। फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायेर ने इसे इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कर समझौता बताया है।

फ्रांस के नेतृत्व वाले देशों ने अमेजन, गूगल और फेसबुक जैसे अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों पर एकतरफा डिजिटल कर लगाना शुरू कर दिया है। डील के तहत वे वैश्विक दृष्टिकोण के पक्ष में उन करों को वापस लेने के लिए सहमत होंगे जिन्हें अमेरिका द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं के रूप में माना जाता है।

इजरायल ने आग के गुब्बारों के जवाब में गाजा पर हवाई हमला किया

यरुशलम, एपी : गाजा से रात में आग लगाने वाले गुब्बारे उड़ाए जाने पर इजरायली युद्धक विमानों ने एक निर्माण स्थल पर हमला करके उस क्षेत्र को ही ध्वस्त कर दिया।

इस हमले से किसी के हताहत होने की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इस्लामिक आतंकी संगठन हमास के हथियार बनाने के इस परिसर को इजरायली वायुसेना ने पूरी तरह तहस-नहस कर दिया है। फलस्तीन से हुए 11 दिनों के युद्ध के समाप्त होने के बाद यह तीसरा मौका है जब इजरायल ने फलस्तीनी इलाके में हवाई हमला किया है। इजरायल ने यह सभी जवाबी हमले तब किए जब इजरायल के कृषि सामुदायिक क्षेत्र पर हमास ने आग वाले गुब्बारों से हमला किया। हमास ऐसा इजरायल और अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाने के लिए करता है। वर्ष 2007 से इजरायल ने हर छोटे से छोटे हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का प्रण कर रखा है। उल्लेखनीय है कि इजरायल और फलस्तीन के बीच दशकों से संघर्ष चल रहा है।

'चोकसी के कथित अपहरण में हमारी संलिप्तता नहीं'

डोमिनिका के पीएम बोले

कहा, डोमिनिका सरकार और एंटीगुआ सरकार की भारत के साथ साठगांठ की खबरें पूरी तरह बकवास

नई दिल्ली, प्रेट्र : डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के कथित अपहरण में उनकी सरकार के शामिल होने के दावों को पूरी तरह बकवास करार दिया है। 23 मई को चोकसी को एंटीगुआ एवं बारबुडा से कथित तौर पर अपहरण कर डोमिनिका ले जाया गया था।

'डोमिनिका न्यूज आनलाइन' की खबर के अनुसार, स्केरिट ने अपने साप्ताहिक कार्यक्रम 'लेट्स टाक' में कहा कि सरकार चोकसी के संबंध में अदालत को उसकी कार्यवाही पूरी करने देगी। साथ ही आश्वासन दिया कि चोकसी के अधिकारों और दायित्वों का सम्मान किया जाएगा। खबर में स्केरिट के हवाले से कहा गया है, 'डोमिनिका सरकार और एंटीगुआ सरकार की भारत के साथ साठगांठ की खबरें पूरी तरह बकवास हैं। हम खुद को इस तरह के कृत्यों, गतिविधियों में कभी शामिल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब है कि यह बेतुका है और हम इसका खंडन करते हैं...।'

उन्होंने सवाल किया, 'क्या यह एक स्थानीय नागरिक के लिए उचित होगा जो डोमिनिका में किसी की हत्या करे और दूसरे देश में भाग जाए। उसे पकड़ने और आरोपों का सामना करने के लिए डोमिनिका वापस भेजने के बजाय उसे आजाद घूमने की अनुमति दी जाए।'


मेहुल चोकसी। जागरण आर्काइव

स्केरिट ने चोकसी पर आरोपों के संबंध में अमेरिका द्वारा वांछित डोमिनिका के एक नागरिक का हवाला दिया जिसकी प्रत्यर्पण की कार्यवाही अदालतों में चल रही है। स्केरिट ने कहा कि देश इस आधार पर लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं कर सकता कि उनके पास कितना पैसा है। उन्होंने कहा, 'हम सभी कानून के अधीन हैं, चाहे हम किसी भी पद पर हों या हमारे पास कितना भी पैसा हो या ना हो। मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में... डोमिनिका को इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और अदालत के समक्ष पेश करने का अधिकार है। अदालत को इस पर फैसला करने दें।'

उन्होंने कहा, 'हम यहां डोमिनिका में चोकसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक युवा लड़का ग्रैंड बे भी है... अमेरिकी सरकार ने सेंट थामस में अपराध को अंजाम देने के आरोपों में उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है और हम उसे पकड़ने के लिए बाध्य हैं। पुलिस ने डीपीपी (लोक अभियोजन निदेशक) के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया है और उसकी प्रत्यर्पण सुनवाई तक उसे जेल में रखा गया है। उसके वकील उसका केस लड़ेंगे। अगर अदालतों को भरोसा हुआ कि उसे अमेरिका प्रत्यर्पित करने का कोई कारण नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा।

अमेरिका-पाकिस्तान संबंध पहले जैसे नहीं हो सकते : विशेषज्ञ

वाशिंगटन, प्रेट्र: दो प्रख्यात अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ पहले की तरह मधुर संबंध की इच्छा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक वह आतंकवाद पर अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता है। इसके साथ ही उसे चीन और भारत के साथ अपने संबंधों को भी दुरुस्त करना होगा।

अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी में पूर्व वरिष्ठ निदेशक लिसा कर्टिस ने एक सेमिनार में कहा कि रणनीतिक साझीदारों को रणनीतिक हितों में बदलाव करना होगा। अमेरिका और पाकिस्तान फिलहाल अफगानिस्तान और चीन के मुद्दों पर एकमत नहीं हैं। कर्टिस ने कहा कि अगर तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता हासिल नहीं होती है, तो हम अपने लक्ष्य में कामयाब है। लेकिनइससे वहां पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों में रुकावट आएगी। इसलिए वह इस प्रक्रिया के खिलाफ है।



चीन में भारी बारिश से आई बाढ़...

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के जश्न में डूबे देश में भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हैं और बाढ़ जैसा हालात उत्पन्न हो गए हैं। दक्षिणी गुआंग्सी क्षेत्र के रोंगन में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। उससे रोंगजियांग नदी उफान पर आ गई है और तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है। एएफपी

चेक गणराज्य के किले को उड़ाने की कोशिश करेंगे डेनिश डायनामाइट

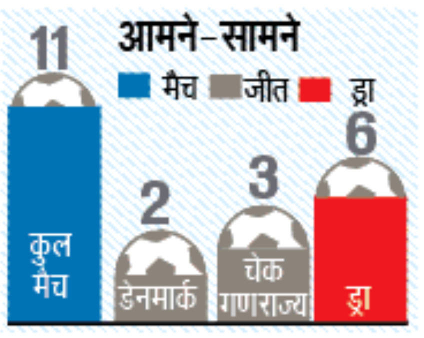
दनादन गोल दागने में आगे रही है डेनमार्क की टीम तो चेक गणराज्य का डिफेंस भी रहा है मजबूत

बाकू, एपी : आज का मुकाबला चेक गणराज्य के डिफेंडरों व डेनिश डायनामाइट के स्ट्राइकरों के बीच में होगा। यूरो कप की शुरुआत के पहले मैच में ही डेनमार्क के खिलाड़ी क्रिस्टियन एरिक्सन को बीच मैदान में दिल का दौरा पड़ गया। इस भावनात्मक पल को दिल में सहेज डेनमार्क की टीम ने एक घायल शेर की तरह टूर्नामेंट में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। रूस को ग्रुप चरण में 4-1 से हराने के बाद डेनमार्क ने वेल्स को 4-0 से हराया। इससे प्रशंसक उन्हें डेनिश डायनामाइट भी कहने लगे। ऐसे में चेक गणराज्य के खिलाड़ियों को शनिवार को क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के स्ट्राइकरों को पकड़ना टेढ़ी खीर साबित होने वाला है।

डेनमार्क ने जहां रूस और वेल्स के खिलाफ गोलों की बारिश की है तो वहीं चेक गणराज्य का डिफेंस अद्भुत रहा है। चेक गणराज की टीम ने टूर्नामेंट में अभी तक सिर्फ दो ही गोल खाए हैं। नीदरलैंड्स और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमें भी उनके खिलाफ कोई गोल नहीं दाग सकी थीं। ऐसे में चेक गणराज्य का डिफेंस ही डेनमार्क के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। डेनमार्क के स्ट्राइकर युसुफ पाल्सेन की वापसी हो सकती है, जो वेल्स के खिलाफ मांसपेशियों में खिंचाव के कारण नहीं खेले थे।

आज के मैच

डेनमार्क vs चेक गणराज्य	
रात 9:30 बजे	स्थान : बाकू
यूक्रेन vs इंग्लैंड	
रात 00:30 बजे	स्थान : रोम
सोनी नेटवर्क	




अभ्यास सत्र के दौरान दौड़ लगाते डेनमार्क टीम के खिलाड़ी • एपी

50 मीटर से गोल करने वाले चिक करेंगे कमाल : चेक गणराज्य के पास भी यूरो कप में लगभग 50 मीटर की दूरी से गोल दागने वाले पैट्रिक चिक हैं। उनके इस गोल ने दर्शकों को दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर कर दिया था। डेनमार्क की टीम का डिफेंस कितना भी मजबूत क्यों ना हो वह अगर इतनी दूर से दोबारा गोल मारते हैं तो विपक्षी टीम खतरे में होगी। वेल्स के खिलाफ पिछले नाकआउट मैच में जब डेनमार्क की टीम दबाव में नजर आ रही थी तभी उनके कोच कैस्पर हुलमंड ने अपने सबसे पसंदीदा टीम फोर्मेशन 3-4-3 को बदलकर 4-3-3 कर दिया था।

2004 के यूरो कप क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य ने 3-0 से डेनमार्क को दी थी मात

1 गोल करते ही पैट्रिक चिक इस सत्र में कुल 5 गोलो करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बराबरी कर लेंगे

"एरिक्सन की घटना के बाद हमारी टीम काफी भावुक पलों से गुजरी है। मगर अब हम रोलर कोस्टर पर सवार हैं। हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि टीम में अभी भी जीत की भूख बाकी है। **पिएरे-एमिल होजबर्ज,** मिडफील्डर डेनमार्क

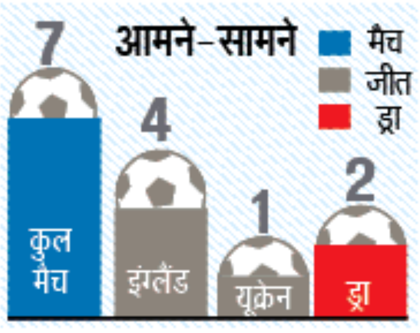
हम बाकू में लोगों से खुद के समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। इस मैच को जीतेंगे और अगले मैच में भी प्रशंसकों को आने का मौका देंगे। **मीकल सादिलेक,** मिडफील्डर चेक गणराज"

इंग्लैंड के डिफेंस को टाइटेनिक की तरह डुबाना चाहेगा यूक्रेन

रोम, एपी : यूरो कप में शनिवार देर रात को मजबूत डिफेंस वाली इंग्लैंड का सामना यूक्रेन की टीम से होगा। हालांकि, यूक्रेन के सहायक कोच मौरो तस्सोटी का मानना है कि फुटबाल के मैदान में इंग्लैंड के डिफेंस को डुबाना बिलकुल टाइटेनिक को डुबाने जैसी चुनौती साबित होने वाला है। हालांकि उनका टूर्नामेंट में पहली बार घर से बाहर खेलना हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकता है।

यूरो कप में इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल तक का सफर सिर्फ अपने मजबूत डिफेंस के दम पर तय किया है। उन्होंने टूर्नामेंट में अभी तक एक भी गोल नहीं खाया है। हालांकि पिछले मैच में उनके स्ट्राइकर और कप्तान हैरी केन और आक्रामक मिडफील्डर रहीम स्टर्लिंग जरूर शानदार लय में दिखाई दिए थे। इन दोनों ने जर्मनी के खिलाफ एक-एक गोल मारा था, जिससे टीम ने 2-0 से जीत दर्ज की थी। इंग्लैंड के डिफेंस को जर्मनी, चेक गणराज्य और स्काटलैंड जैसी टीमें अभी तक नहीं भेद सकी हैं। यही कारण है कि यूक्रेन के सहायक कोच ने उनके डिफेंस की तुलना टाइटेनिक जहाज से कर दी है। यूक्रेन की बात करें तो उनकी टीम कप्तान एंड्री यरमोलेंको और कोच एंड्री शेवचेंको के भरोसे टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल तक आ पहुंची है। 31 साल के स्ट्राइकर यरमोलेंको अभी तक अपने करियर में 42 गोल दाग चुके हैं, जो कि यूक्रेन के लिए सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की फेहरिस्त में भी शामिल हैं। इस तरह इंग्लैंड के डिफेंस में घुसकर गोल करने के लिए उन्हें ही अपनी टीम से आगे आना पड़ेगा।


अभ्यास करते इंग्लैंड की फुटबाल टीम के खिलाड़ी • रायटर



एक नजर में

थंगावेलू टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक होंगे

नई दिल्ली : शीर्ष पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलू को शुक्रवार को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया। टोक्यो पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से पांच सितंबर तक होंगे। राष्ट्रीय संस्था की कार्यकारी समिति ने ध्वजवाहक के लिए रियो पैरालंपिक में टी-42 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतने वाले ऊंची कूद के एथलीट थंगावेलू का चयन किया।' (प्रेट्र)

राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता रद

नई दिल्ली : बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों 2022 से पहले चंडीगढ़ में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल तीरंदाजी और निशानेबाजी चैंपियनशिप को कोरोना के कारण रद कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के सहयोग से भारतीय राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड ने यह फैसला लिया। (प्रेट्र)

पहलवान सुमित मलिक पर दो साल का प्रतिबंध

नई दिल्ली : भारतीय पहलवान सुमित मलिक की ओलंपिक में भाग लेने की उम्मीदें शुक्रवार को खत्म हो गईं, जब उनके बी नमूने में भी प्रतिबंधित पदार्थ के अंश पाए जाने के बाद यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने उन पर दो साल का प्रतिबंध लगा दिया। मलिक को फैसले के खिलाफ अपील करने या उसे मानने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालीफायर में डोप टेस्ट में नाकाम रहने के बाद उन पर अस्थायी निलंबन लगाया गया था। उसी टूर्नामेंट में उन्होंने 125 किग्रा वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। उनके बी नमूने की 30 जून को हुई जांच में उसी प्रतिबंधित पदार्थ के अंश मिले हैं। (प्रेट्र)

भारतीय हैंडबाल संघ की संयुक्त सचिव बनीं स्वाति


स्वाति शुक्ला • फाइल फोटो ट्विटर

नई दिल्ली : स्वाति शुक्ला को भारतीय हैंडबाल संघ का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। खेलकूद और सामाजिक कार्यों में स्वाति के योगदान को देखते हुए उनकी नियुक्ति जयपुर में हुई एचएफआइ की कार्यकारिणी की बैठक में महिला कोटे से की गई। (जेएनएन)

माना को मिला टोक्यो टिकट

नई दिल्ली : भारतीय महिला तैराक माना पटेल को विश्वविद्यालय कोटा से टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिल गया है। भारतीय तैराकी महासंघ ने इसकी पुष्टि की। माना टोक्यो खेलों में 100 मीटर बैकस्ट्रोक में भाग लेंगी। वह इन खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाली तीसरी भारतीय तैराक हैं। श्रीहरि नटराज और साजन प्रकाश ने हाल में ओलंपिक क्वालीफिकेशन टाइमिंग (ओक्यूटी) में ए स्तर हासिल करके क्वालीफाई किया था। विश्वविद्यालय कोटा से किसी एक देश के एक पुरुष और एक महिला प्रतिस्पर्धी को भाग लेने का मौका मिलता है, बशर्ते उस देश के किसी अन्य तैराक ने उस वर्ग (पुरुष या महिला) में क्वालीफाई नहीं किया हो या ओलंपिक चयन समय (बी) के आधार पर अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ से निमंत्रण हासिल नहीं किया हो। (प्रेट्र)

दुनिया का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा

जयपुर, प्रेट्र : राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव ने जयपुर में बनने जा रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जमीन का पट्टा जयपुर विकास प्राधिकरण से हासिल कर लिया। यह स्टेडियम जयपुर के चौंप में बनने जा रहा है।

वैभव ने कहा कि करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा। यह देश का दूसरा एवं दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इसमें 75,000 दर्शक बैठ सकेंगे। मालूम हो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दर्शक क्षमता करीब 1.10 लाख और मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम की एक लाख है। जयपुर में स्टेडियम का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में 40 हेक्टेयर में 40,000 दर्शक क्षमता के साथ 11 पिच, दो अभ्यास मैदान, एक अकादमी बनेगी।

मेसी के नए करार में नियमों की वजह से देरी : लपोर्ता

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी का फुटबाल क्लब बार्सिलोना के साथ करार भले ही 30 जून को खत्म हो गया, लेकिन वह एक बार फिर बार्सिलोना के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बार्सिलोना क्लब के अध्यक्ष जोन लपोर्ता का कहना है कि मेसी के नए करार में ला लीगा के वित्तीय नियमों की वजह से देरी हो रही है।

34 साल के अर्जेंटीनी खिलाड़ी मेसी अभी कोपा अमेरिका में खेल रहे हैं। कई रिपोर्टों में यह कहा जा रहा है कि वह क्लब के साथ अगले दो साल के लिए के लिए नया करार करने के करीब हैं तो वहीं, पेरिस सेंट जर्मेन और इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी भी उनके साथ करार कर सकते हैं। वह एक जुलाई से किसी भी क्लब के साथ नया करार करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, अब क्लब के अध्यक्ष लपोर्ता ने इस मामले में चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने स्थिति को साफ करते हुए कहा कि क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल दागने वाले मेसी अब भी उनके साथ जुड़े रहना चाहते है। रेडियो स्टेशन ओंडा सेरो से बात करते हुए लपोर्ता ने कहा, 'सब अच्छा चल रहा है, वह क्लब में रहना चाहते हैं और हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें इसे वित्तीय निष्पक्ष खेल नियमों के साथ संतुलित करना होगा। कई विकल्प हैं और हम उस पर विचार कर रहे हैं, जो दोनों पक्षों के लिए सबसे अच्छा हो। हम चाहते हैं कि वह हमारे साथ बने रहें और वह भी यहीं चाहते है।' बार्सिलोना के साथ मेसी का रिश्ता 20 वर्षों से रहा है। उन्होंने क्लब के लिए 778 मैचों में 672 गोल दागे हैं जबकि 288 मैचों में उन्होंने गोल करने में मदद की है। 2020-21 सत्र में उन्होंने 47 मैच खेले और 38 गोल दागे और साथ 12 गोल करने में सहायता भी की।

रोमांचक जीत के साथ जोकोविक आगे बढ़े


शाट लगाते जोकोविक • एएफपी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : विश्व नंबर एक सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने शुक्रवार को टाईब्रेकर तक गए तीसरे सेट में रोमांचक जीत दर्ज कर विंबलडन के चौथे दौर में प्रवेश किया। जोकोविक ने तीसरे दौर में 114वीं रैंकिंग वाले अमेरिकी डेनिस कुडला को 6-4, 6-3, 7-6 (9-7) से हराया।

पांच बार के विंबलडन चैंपियन जोकोविक को शुरुआती दो सेट जीतने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और ऐसा लग रहा था कि वह तीसरे सेट को भी आसानी से जीतकर मैच अपने नाम कर लेंगे। लेकिन, अमेरिकी क्वालीफायर कुडला ने उनकी राह मुश्किल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। रिकार्ड 20वें ग्रैंडस्लैम खिताब की बराबरी करने पर नजरें जमाए जोकोविक तीसरे सेट में कुडला को पहले तीन गेम जीतने से नहीं रोक पाए, जिससे कुडला तीसरे सेट में 3-0 से आगे हो गए। इसके बाद जोकोविक ने वापसी की और पहले 4-4, फिर 5-5 और उसके बाद 6-6 से बराबरी कर वह तीसरे सेट को टाईब्रेकर में ले गए। हालांकि, इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने एक-एक बार अपनी-अपनी सर्विस भी गंवाई। हालांकि, टाईब्रेकर में जाने के बावजूद लग रहा था कि कुडला मैच को चौथे सेट में ले जा सकते हैं, लेकिन जोकोविक ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया।

आर्यना सबालेंका ने चौथे दौर में बनाई जगह : दूसरी वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका विंबलडन के चौथे दौर में पहुंच गई हैं और वह शीर्ष-20 खिलाड़ियों में एकमात्र ऐसी महिला हैं, जो किसी ग्रैंडस्लैम के क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच सकी हैं।

75वीं जीत दर्ज की विंबलडन में जोकोविक ने। साथ ही उन्होंने 13वीं बार इस प्रतिष्ठित ग्रैंडस्लैम के चौथे दौर में प्रवेश किया

बोपन्ना-सानिया ने जीता ऐतिहासिक मैच

भारत की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने शुक्रवार को मिक्सड डबल्स के पहले दौर के मैच में हमवतन रामकुमार रामनाथन व अंकिता रैना को 6-2, 7- 6 से हराकर ऐतिहासिक मैच जीता। मिक्सड डबल्स में पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में दो भारतीय टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेल रही थीं। रामनाथन ने इस मैच के जरिये ग्रैंडस्लैम में पदार्पण किया। पहला सेट सानिया और बोपन्ना ने आसानी ने जीत लिया, लेकिन दूसरे सेट में उन्हें कड़ी चुनौती मिली। बोपन्ना अपनी दमदार सर्विस और बेसलाइन पर ग्राउंड स्ट्रोक्स से चारों में सबसे बेहतर साबित हुए। सानिया और अमेरिका की बेथानी माटेक सैंड्स की जोड़ी महिला डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच चुकी है।

लंगर की रोटियां खाकर प्रियंका ने तय किया ओलंपिक तक का सफर


प्रियंका गोस्वामी • जागरण

विश्व रिकार्ड
एक घंटा 23 मिनट 49 सेकेंड में 20 किमी की रेस पूरी करके चीन की यांग जियाउ ने इसी साल चाइना पैदल चाल चैंपियनशिप में बनाया था विश्व रिकार्ड

सर्वश्रेष्ठ समय
एक घंटा 28 मिनट और 45 सेकेंड

ओलंपिक के लिए
लगभग एक घंटा 26 मिनट से कम में आ सकता है पदक

पदक के दावेदार
TOKYO 2020
20 दिन शेष

विकास मिश्र • लखनऊ

प्रियंका गोस्वामी जब 14 साल की थीं तब पापा की नौकरी चली गई। करीब 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक आर्थिक तंगी ठीक नहीं हुई। वह रोडवेज बस में कंडक्टर थे। ऐसी स्थिति में खिलाड़ी बनना तो दूर, दो जून की रोटी की डगर भी कठिन दिखने लगी। मन में देश के लिए कुछ करने की ललक थी, लेकिन आर्थिक संकट के चलते परिवार में बात करने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद एक दिन स्कूल में कोच ने प्रियंका से पूछा कि खेल में रुचि है? उन्होंने हां कह दिया। इसके बाद शुरू हुआ प्रियंका के ट्रैक में दौड़ने का सफर।

वर्ष 2006 में मुफ्फरनगर के सागड़ी गांव से मदनपाल गोस्वामी, पत्नी अनीता और दोनों बच्चे प्रियंका व कपिल को लेकर मेरठ आ गए। पिता मदनपाल ने कहा कि 2010 में रोडवेज के उच्चाधिकारियों ने मिलीभगत कर मुझे नौकरी से निलंबित करा दिया। बहाली के लिए सालों तक चक्कर लगाता रहा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मैंने टैक्सी चलाकर बेटी का सपना पूरा किया। यह उन लोगों के लिए मिसाल है, जो आर्थिक संकट का बहाना बनाकर मैदान से दूरी बना लेते हैं।

परिवार ने मनोबल बढ़ाया : दैनिक जागरण से बातचीत में प्रियंका ने अपने संघर्ष को साझा किया। प्रियंका ने कहा, 'जब पापा की नौकरी चली गई तो कोई सहारा नहीं बना। मैंने जब कैलाश खेल स्टेडियम में दाखिला लिया तो रिश्तेदार और गांव के लोग मनोबल बढ़ाने की जगह पापा और मां को अपने निर्णय पर फिर से विचार करने के लिए कहने लगे। लेकिन, पापा ने सबकी बातों को दरकिनार कर मुझे कड़ी मेहनत करने की सलाह दी, क्योंकि पापा ने मेरी आंखों से अपने लिए सपना देखा था। वर्ष 2011 में मैंने अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए पटियाला के नेताजी सुभाषचंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पोर्ट्स (एनआइएस) में दाखिला लिया। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पटियाला में भी संघर्ष जारी रहा। पैसे बहुत कम होते थे, लिहाजा सुबह का खाना बनाती तो शाम के खाने के लिए लंगर खाने गुरुद्वारा पहुंच जाती। ये वो दिन थे जिन्हें मैं कभी नहीं भुला सकती।'

राष्ट्रीय रिकार्ड से हासिल किया ओलंपिक टिकट

पिछले साल कोरोना के चलते कई प्रतियोगिताएं निरस्त हुईं। हालांकि प्रियंका के लिए 13 फरवरी 2021 इतिहास रचने का दिन था। मौका था रांची में आयोजित राष्ट्रीय पैदल चाल चैंपियनशिप का। मेरठ की स्टार एथलीट ने इस चैंपियनशिप में अपने धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत ना सिर्फ नया राष्ट्रीय रिकार्ड भी स्थापित किया, बल्कि 20 किलोमीटर की पैदल चाल एक घंटा 28 मिनट और 45 सेकेंड में पूरी कर ओलंपिक का टिकट भी हासिल किया। भारत में इससे पहले यह रिकार्ड राजस्थान की एथलीट भावना जाट (एक घंटा 29 मिनट 54 सेकेंड) के नाम था।

श्रीलंका क्रिकेट में बगावत

कोलंबो, प्रेट्र : भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज से पहले पांच क्रिकेटरों ने श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) द्वारा प्रस्तावित अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया, जिसके बाद उन्हें आवासीय कैंप से बाहर निकाल दिया गया है। लसिथ एंबुलडेनिया, विश्वा फर्नांडो, लाहिरू कुमार, आशेन बंडारा और कसून रजित को भारत के खिलाफ सीरीज से पहले एसएलसी ने दौरे अनुबंध का प्रस्ताव दिया था जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया।

भारत ने शुरू किया अभ्यास : शिखर धवन की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 13 जुलाई से शुरू होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज के लिए शुक्रवार को पहले अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया।

रणतुंगा बोले, भारत की दूसरी श्रेणी की टीम की मेजबानी करना अपमानजनक : श्रीलंका की 1996 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने दूसरी श्रेणी की भारतीय टीम की मेजबानी करने के लिए एसएलसी की आलोचना करते हुए कहा, 'यह हमारे क्रिकेट का अपमान है। मैं मार्केटिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके साथ खेलने पर सहमत होने के लिए वर्तमान प्रशासन को दोषी मानता हूं। भारत ने अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम इंग्लैंड भेजी है और कमजोर टीम यहां भेज दी।' श्रीलंका बोर्ड ने कहा है कि भारत की यह टीम भी बेहद मजबूत है।

कोहली ने बेस्ट आफ थ्री फाइनल पर राय दी : अश्विन

लंदन : भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने विराट कोहली का बचाव करते हुए कहा कि कप्तान ने केवल अपनी राय जताई थी कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल एक टेस्ट के बजाय बेस्ट आफ थ्री (तीन मैच) होना चाहिए, लेकिन कभी इसके प्रारूप को बदलने की मांग नहीं की थी। न्यूजीलैंड से हार के बाद कोहली ने कहा था कि सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम का निर्णय एकमात्र टेस्ट मैच के बजाय बेस्ट आफ थ्री से होना चाहिए।

घरेलू खिलाड़ियों की मैच फीस बढ़ाने की तैयारी

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

20 या ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को 60,000, उससे कम मैच खेलने वालों को 45,000 रुपये प्रति दिन देने का प्रस्ताव

बीसीसीआइ कोरोना से बेहाल घरेलू क्रिकेटरों के लिए खजाना खोलने की तैयारी में है। बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, सचिव जय शाह और कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने मुंबई में दो दिन तक मैराथन बैठकें कीं और उसमें यह तय किया गया कि घरेलू क्रिकेटर को नई ऊर्जा देने के लिए फीस बढ़ाई जाएगी।

बीसीसीआइ पदाधिकारी के अनुसार अभी एक प्रस्ताव आया है जिस पर सहमति मिलने के पूरे आसार हैं। पदाधिकारी ने कहा कि पिछला घरेलू सत्र खराब हो गया। उसके लिए मुआवजा देने पर तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। उस पर समिति तय करेगी कि कैसे मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा हमने 2021-22 सत्र के लिए भी योजना बनाई। इसमें घरेलू क्रिकेट में सीनियर पुरुष टीम (रणजी, विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली ट्राफी) की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन खिलाड़ियों ने 20 या उससे ज्यादा मैच खेले हैं, उन्हें अगले सत्र से 35 की जगह 60,000 रुपये प्रति दिन मिलेंगे जबकि 20 से कम मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को 45,000 रुपये प्रति दिन मिलेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब घरेलू पुरुष टीम के खिलाड़ियों मैच खेलने के आधार पर फीस मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू क्रिकेटरों का काफी फायदा होगा। जल्द ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। अभी पुरुष खिलाड़ियों को प्रति दिन 35,000 रुपये मैच फीस मिलती है। उन्होंने कहा कि जैसे अगले सत्र के टूर्नामेंट शुरू होने से पहले किसी के 18 मैच हैं। तो उसे 45,000 रुपये प्रति दिन मिलेंगे। जैसे ही उसके 20 मैच हो जाते हैं, उस खिलाड़ी को 60,000 रुपये प्रति दिन मैच फीस मिलने लगेगी।

योजना | वीसीसीआइ ने दो तरह के प्रस्ताव तैयार किए, नवंबर में रणजी ट्रॉफी के आयोजन की तैयारी

अक्टूबर में शुरू हो सकता है घरेलू क्रिकेट सत्र

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने 2021-22 के घरेलू सत्र को एक अक्टूबर से शुरू करने की योजना बनाई है। बीसीसीआइ ने दो तरह के प्रस्ताव (पेनडेमिक और नान पेनडेमिक) बनाए हैं। अगर कोरोना महामारी का प्रभाव नहीं रहता है तो एक अक्टूबर से 12 अप्रैल के बीच सभी घरेलू टूर्नामेंट के कुल 1971 मैचों का आयोजन होगा। अगर कोरोना महामारी का असर होता है जिसकी संभावना ज्यादा है तो 15 अक्टूबर से 20 अप्रैल के बीच कुल 1487 घरेलू मैच कराए जाएंगे। अभी इसमें मुहर लगना बाकी है।

बीसीसीआइ पिछले सत्र में सिर्फ मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी का ही आयोजन करा सका था। बाकी टूर्नामेंट नहीं होने के कारण जूनियर क्रिकेटरों का बहुत नुकसान हुआ। नए प्रस्ताव के तहत अगर महामारी की स्थितियां काबू में रहती हैं तो पुरुष सीनियर्स की सैयद मुश्ताक अली (टी-20), विजय हजारे ट्राफी (वनडे), रणजी ट्राफी, अंडर-23 वनडे और सीके नायुडू ट्राफी (बहुदिवसीय) के अलावा अंडर-19 के तीनों, अंडर-16 के एक, महिला सीनियर्स के चारों, महिला अंडर-23 के दो, अंडर-19 के तीन व विज्जी ट्राफी कराई है। अगर महामारी की परिस्थितियां बनी रहती हैं तो भी यह सभी टूर्नामेंट आयोजित होंगे लेकिन उनके ग्रुप बढ़ा दिए जाएंगे जिससे कोरोना का खतरा कम रहे।

महामारी बनी रहने पर

- घरेलू टीमों को छह ग्रुपों में बांटा जाएगा
- हर टूर्नामेंट के लिए सात दिनों का क्वारंटाइन रहेगा
- रणजी, सीके नायुडू, कूच बिहार, वनडे में ग्रुप की शीर्ष टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगी। एलीट ग्रुप की दो और ज्यादा अंकों वाली टीमें क्वार्टर फाइनल में जाएंगी
- टी-20 टूर्नामेंट में छह ग्रुप होंगे। इसमें क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल 2020-21 सत्र की तरह रहेंगे

महामारी की परिस्थिति में घरेलू टूर्नामेंट

वर्ग	टूर्नामेंट	तारीख
पुरुष सीनियर	सैयद मुश्ताक अली (टी-20)	15-10-21 से 13-11-21
	विजय हजारे (वनडे)	18-02-22 से 20-03-22
	रणजी ट्रॉफी (बहुदिनी)	21-11-2021 से 10-02-22
अंडर-23	वनडे	20-02-22 से 22-03-22
	सीके नायुडू (बहुदिनी)	23-11-21 से 08-02-22
अंडर-19	वीनू मांकड़ ट्राफी (वनडे)	15-09-21 से 15-10-21
	वनडे चैलेंजर	20-10-21 से 02-11-21
	कूच बिहार ट्राफी (बहुदिनी)	11-11-21 से 27-01-22
अंडर-16	विजय मर्चेंट ट्राफी (बहुदिनी)	15-01-22 से 25-03-22
महिला सीनियर	टी-20 लीग	11-01-22 से 08-02-22
	वनडे लीग	15-09-21 से 15-10-21
	वनडे चैलेंजर ट्राफी	22-10-21 से 02-11-21
	महिला दो दिवसीय	08-11-21 से 02-12-21
महिला अंडर-23	टी-20 लीग	25-03-22 से 20-04-22
	वनडे लीग	15-02-22 से 17-03-22
महिला अंडर-19	टी-20 लीग	18-10-21 से 17-11-21
	वनडे लीग	09-01-22 से 08-02-22
	वनडे चैलेंजर	16-02-22 से 27-02-22
यूनिवर्सिटी	विज्जी ट्राफी (वनडे)	16-03-22 से 29-03-22

क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी महिला टीम

वार्सेस्टर, प्रेट्र : इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में शनिवार को यहां भारतीय महिला टीम के सामने अपना सूपड़ा साफ होने से बचाने की चुनौती होगी, जबकि भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय उप कप्तान हरमनप्रीत कौर का लंबे समय से रन बनाने के लिए जूझना है।

पिछले सात वनडे मैचों में से छह हारने के बाद मिताली राज की अगुआई वाली टीम को लय हासिल करने में मुश्किल हो रही है। उसे घरेलू धरती पर दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम से भी हार झेलनी पड़ी थी। टीम के लिए सबसे अधिक चिंता का सबब हरमनप्रीत की लचर बल्लेबाजी है, जिनके प्रदर्शन में पिछले चार साल से निरंतरता नहीं रही है। आस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 विश्व कप में 171 रन की शानदार पारी के बाद वह सिर्फ दो मैचों में ही अर्धशतक लगा सकी हैं। इस दौरान उन्हें 28 मैचों में 22 बार बल्लेबाजी का मौका मिला।

मिताली और जेमिमा रोड्रिग्स के अलावा पूनम राउत, दीप्ति शर्मा और तानिया भाटिया के पास बड़े शाट खेलने की क्षमता नहीं होने के कारण, सलामी बल्लेबाजों स्मृति मंधाना और 17 साल की शेफाली वर्मा पर बहुत दबाव बन रहा है।

जोश नई राहों का



शनिवार, 3 जुलाई, 2021

महान उपलब्धि हासिल करने वाले सफलता की खोज से नहीं, बल्कि असफलता के डर से चलते हैं। -लैरी एलिसन, फाउंडर, ओरेकल

टर्निंग प्वाइंट



डा. ब्रजेश कुमार तिवारी
एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल आफ मैनेजमेंट, जवाहरलाल नेहरू विवि, नई दिल्ली

फिर बेहतर होगा कल

आने वाला कल हमें कई सारे अवसर प्रदान करेगा। विजेता वे युवा होंगे जो क्या, क्यों, कैसे और कौन का विश्लेषण कर कार्य करेंगे। हारने वाले वे होंगे, जो सब कुछ वापस आने का इंतजार करेंगे। जीवन एक सुंदर यात्रा है। हौसले के हथौड़े से हम कहीं भी सफलता की कील लगा सकते हैं और इसलिए हम सबको यह आशा रखनी चाहिए कि कल बेहतर होगा...



फोटो : इमेजेज बाजार

मानव का भविष्य हमेशा से अप्रत्याशित रहा है। लगभग दस हजार साल पहले नवपाषाण क्रांति से लेकर औद्योगिक सभ्यता तक लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। इसी तरह कोविड-19 ने भी नये सामान्य (न्यू नार्मल) से हम सभी का परिचय कराया है। महामारी से पहले हम जिस तरीके की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आज उसी तरीके से जिंदगी चल रही है। कोरोना ने वर्क फ्रॉम होम को जीवन का हिस्सा बना दिया है। रिमोट वर्चुअल मीटिंग अब आम बात हो गई है। ब्रिटेन में पहली बार जूम सॉफ्टवेयर के माध्यम से संसद सत्र का आयोजन किया गया। ऐसा वहां 700 से अधिक वर्षों में पहली बार हुआ है कि सांसद 'हाउस ऑफ कॉमंस' में नहीं बैठे थे।

प्रगाढ़ता बढ़ाने का मिला मौका: कुल मिलाकर, महामारी ने हमें सिखा दिया है कि जीवन में जो कुछ भी स्थिर है, वह बदल सकता है। कल तक हम आजाद घूमते थे पर आज कोई दरवाजे पर भी आ जाये तो डर लगता है। वहीं दूसरी ओर इस महामारी ने जोखिम और अवसर दोनों बढ़ा दिए हैं। मुश्किल वक्त हमें नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है। कोरोना और लाकडाउन ने भी वैसा ही किया है। नये अनुभव जहां हमारा अस्तित्व बचाने में मदद करते हैं, वहीं ये अनुभव जीवन में आगे बढ़ने की ताकत भी देते हैं। कोविड-19 से पहले की जिंदगी और बाद की जिंदगी में बहुत अंतर आया है। कोरोना ने जहां जीवन जीने के तरीके बदले हैं, वहीं पुराने संबंधों के प्रति एक ऊर्जा भी प्रदान किया है। कोरोना ने अपने परिवारों के साथ भोजन साझा करने का अवसर दिया है। साथ ही, होमस्कूलिंग व बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के लिए समय भी दिया है। लाकडाउन में महिलाओं का व्यक्तित्व भी कहीं ज्यादा उभर कर सामने आया है। कोरोना काल में महिलाओं ने दोगुनी मेहनत से घर-परिवार को संभाला। कामकाजी महिलाओं ने लगातार घर से काम करते हुए न केवल परिवार के साथ संतुलन बनाये रखा, बल्कि घरों में कैद रहने से होने वाली मानसिक परेशानियों से भी डटकर मुकाबला किया।

आनलाइन कामकाज बना जीवन का हिस्सा: महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है और डिजिटल शब्द की व्याख्या और अर्थ उदाहरण सहित बता दिया है। आज आनलाइन बैंकिंग, आनलाइन लेनदेन, आनलाइन शिक्षा व आनलाइन जॉब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। नई तकनीकों पर काम करना, घर में ज्यादा समय व्यतीत करना, घर से काम करना, खेल व मनोरंजन के नये तौर-तरीकों को स्वीकार करना, रिश्तेदारों-दोस्तों से संबंधों को फिर से मजबूत बनाना, ये सब हमें कोरोना ने सिखाया है। कोरोना ने महंगे सामान बटोरने और पैसे खर्च करने की संस्कृति के बारे में पुनर्विचार करने का भी एक मौका दिया है। यह सही है कि महामारी एक कठिन समय है, परंतु यह अभूतपूर्व रचनात्मकता का समय भी हो सकता है। वर्चुअल इंटरैक्शन इनोवेशन को बढ़ा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम ने ऑफिस ऑवर नौ से पांच को पूरी तरह से बदल दिया है और घर व कार्यालय के बीच की दूरी को बहुत कम कर दिया है।

बदलें बदलाव के अनुरूप: महामारी ने लाइफ को भी रीसेट करने के लिए मजबूर किया है। श्रीमद्भगवद्गीता में बताया गया है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। इस महामारी ने हमारी सभी योजनाओं को बदल दिया है और करियर के बारे में अनिश्चित महसूस कराया है। याद रखें करियर और काम हमेशा परिवर्तनीय होते हैं। जहां कुछ नौकरियां अप्रचलित हो जाती हैं, वहीं कुछ समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए उभरती हैं। एक सर्वे के अनुसार, खोई हुई सभी नौकरियों में से 35 फीसद वापस नहीं आएंगी। हालांकि, सर्वे से ही यह भी पता चलता है कि कार्य पुनर्वितरण व नई मांग नुकसान को कम करेगी। क्रॉस-इंडस्ट्री टैलेंट एक्सचेंजों में कर्मचारियों को साझा किया जा रहा है। यह उन संगठनों में अभिनव प्रतिक्रिया है, जिनके पास काम की अधिकता है, जैसे कि स्वास्थ्य, रसद, खुदरा स्टोर व आनलाइन स्टोर। इन जगहों पर होटल, एयरलाइंस व पर्यटन से जुड़े लोगों को भेजा जा रहा है। यह नये कौशल और नेटवर्क विकसित करने में बहुत सहायक है। आज के आर्थिक माहौल में ऑटोमेशन नौकरी मारने वाला नहीं है, यह संकट से निपटने के लिए एक अनिवार्य क्षमता बनता जा रहा है। 5जी नेटवर्क और कनेक्टेड मशीनों के उदय से वर्चुअल 'आन-द-गो वर्कस्टेशन' बन रहे हैं। हमें भविष्य के बारे में कई नये विकल्प मिल सकते हैं। बस जरूरत है इसमें समय और प्रयास लगाने की।

न्यू नार्मल से नया अवसर: नया सामान्य नये अवसर लाएगा। एक नया बाजार जो पहले अछूता था, अब वह पकड़ में आ रहा है। हर तरफ कयामत नहीं है। बहुत-सी कंपनियां और स्टार्ट-अप हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और युवा उनमें काम करके अच्छा अनुभव हासिल कर सकते हैं। कई नियोक्ता अब अलग-अलग कौशल रखने वाले स्नातकों की तलाश कर रहे हैं, ताकि वे घर से प्रभावी ढंग से काम कर सकें। देश वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। आज भारत विदेशी निवेशकों और कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए पर्याप्त जमीन, प्रशिक्षित मैनपावर और अच्छा-खासा बाजार उपलब्ध करा सकता है। हमारे देश में पैंतीस साल से कम उम्र की सबसे बड़ी जनसंख्या है और साइंस-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की बहुत बड़ी तादाद है। कुल मिलाकर सस्ता श्रम, बड़ा टैलेंट पूल और स्किल्ड मैनपावर की उपलब्धता भारत को बाकी देशों की तुलना में काफी आकर्षक बना रही है।

जीवन है सुंदर यात्रा: आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए हमें रणनीतिक रूप से योजना बनानी चाहिए। नौकरी की कठोर बाधाओं को कम करके, व्यावसायिक चुनौतियों को हल करने के लिए सही प्रतिभा और काम का मिलान किया जा सकता है। अगर हम मेडिकल उपकरणों को भारत में ही बनाने और निर्यात करने को प्रोत्साहन दें, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था का भी भला होगा और भारत जैसी जरूरतों वाले अन्य देश इन नई खोजों के निर्यात का बाजार बन सकेंगे। कोरोना ने हमें खुद और अपनों के बारे में सोचने का मौका दिया है। लाकडाउन के अनुभवों ने हमें यह भी सिखाया है कि जिंदगी दूसरे तरीकों से भी चल सकती है। प्रकृति के दोहन के बदले उसे बचाते हुए समाज का विकास हो सकता है। सड़कें भी सांस ले सकती हैं। हम जानते हैं कि एक कल होगा और वह कल हमारे जीवन को कई सारे अवसर प्रदान करेगा। विजेता वे युवा होंगे जो क्या, क्यों, कैसे और कौन का गहन विश्लेषण कर अपना कार्य करेंगे। हारने वाले वे होंगे, जो पहले की तरह सब कुछ वापस आने का इंतजार करेंगे। जीवन अभी भी एक सुंदर यात्रा है। हौसले के हथौड़े से हम कहीं भी सफलता की कील लगा सकते हैं और इसलिए हम सबको यह आशा रखनी चाहिए कि कल बेहतर होगा।



स्किल, री-स्किल और फ्यूचर स्किल का समय

यह एक नवीन व्यवसाय माडल का समय है। व्यवसाय शुरू करने के लिए मंदी से बेहतर कोई समय नहीं है। युवा कोरोना काल में कम लागत, अच्छी प्रतिभा व श्रम के माध्यम से बेहतर सप्लाईचेन मैनेजमेंट को पूरा कर सकते हैं। किसी विद्वान ने लिखा है कि, 'सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है।' अतीत में जाएं, तो हम पाएंगे कि वैश्विक आर्थिक मंदी 2008 की चुनौतियों के बाद कई सारी स्टार्ट-अप कंपनियां शुरू हुई थीं, जिनमें वाट्सएप (2009), उबर (2009) व इंस्टाग्राम (2010) प्रमुख हैं, जो आज समूचे संसार में अपना लोहा मनवा रही हैं। वास्तव में चुनौती और अवसर एक दुधारी तलवार की तरह होते हैं। जीवन भी ऐसा ही है, आवश्यकता है तो निर्णय लेने की। इसीलिए स्किल, री-स्किल और फ्यूचर स्किल पर ध्यान दें। ब्रुक्स ब्रदर्स और न्यू बैलेंस जैसी परिधान कंपनियों के कर्मचारी अब सर्जिकल मास्क और गाउन का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि टेस्ला, फोर्ड और जनरल मोटर्स उपभोक्ता मांग में गिरावट के कारण अपने संयंत्रों में वेंटिलेटर व अन्य मेडिको मशीन का उत्पादन करने में लगे हैं।

कार्य को बनाएं आसान



टेक लर्निंग

वर्कप्लेस पर अक्सर ऐसा होता है कि आपको एक साथ कई सारे कार्य करने पड़ जाते हैं। हालांकि अलग-अलग तरह के कार्यों को एक साथ करना आसान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आनलाइन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके कार्यों को आसान बना देगा...

वर्कोना: अगर आप उन लोगों में हैं, जिनका अधिकतर कार्य इंटरनेट सर्विस के इर्द-गिर्द रहता है, तो फिर क्रोम एक्सटेंशन वर्कोना (workona.com) की मदद ले सकते हैं। यह प्रोडक्टिविटी वेब एप है, जो आपके ब्राउजर टैब को आर्गेनाइज करने में मदद करता है। आनलाइन कार्य ज्यादा करते हैं, तो फिर यहां आपको स्मार्ट ब्राउजर विंडोज मिलता है, जिसका इस्तेमाल प्रोजेक्ट्स, वर्कफ्लो, मीटिंग्स, डैशबोर्ड के साथ दूसरे कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। अगर ब्राउजर पर कार्य कर रहे हैं, तो फिर अलग-अलग टैब को सर्च और ओपन करना भी आसान हो जाता है। इसका इस्तेमाल टैब को सेव और सर्च करने के लिए भी किया जा सकता है।

निंबस कैप्चर

आफिस कार्य के दौरान स्क्रीनशाट और स्क्रीन वीडियो रिकार्डर के लिए निंबस कैप्चर (nimbusweb.me) इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खासियत है कि आप पूरे वेबपेज का स्क्रीनशाट ले सकते हैं या फिर पेज के किसी खास हिस्से का। इसके साथ स्क्रीन वीडियो रिकार्डर की सुविधा भी है। इसकी मदद से स्क्रीन से ही वीडियो को रिकार्ड कर पाएंगे। इसके अलावा, पूरे ब्राउजर विंडो को भी कैप्चर कर सकते हैं। स्क्रीनशाट को जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ आदि फार्मेट में सेव करने की सुविधा है।

पेपियर: अगर आफिस वर्क के दौरान नोट्स लिखने के लिए कागज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो फिर पेपियर (getpapier.com) आपके लिए अच्छा टूल हो सकता है। इस क्रोम एक्सटेंशन को ब्राउजर के साथ जोड़ने के बाद आनलाइन तेजी से नोट्स तैयार करना आपके लिए आसान हो जाएगा।

फीचर डेस्क

लाइफ स्किल



डा. अनिल सेठी
मोटिवेटर एवं लाइफ कोच

सिखाएं पैसे की अहमियत

हमारे समाज में सभी माता-पिता अपने बच्चों को सबसे बेहतर सुख-सुविधाएं देना चाहते हैं। चाहे वे समाज में किसी भी स्तर पर हों लेकिन बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे में जब बच्चों को सबकुछ आसानी से या बिना मेहनत के मिलने लगता है, तो वे अक्सर पैसे के लिए माता-पिता का संघर्ष और पैसे की सही अहमियत नहीं समझ पाते हैं।

एक पुरानी कहावत है-'पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय।' कहने का आशय यह है कि अगर हम अपने बच्चों को सही समझ, सही संस्कार नहीं दे पा रहे, तो अन्य सब कुछ व्यर्थ है। आज महानगरों में माता-पिता दोनों नौकरी करते हैं और बच्चों को अपना समय न दे पाने के बोझ से दबे होते हैं। इसके बदले वे बच्चों को पैसे या गैजेट्स आदि देकर अपने को अपराध बोध से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि बचपन में अगर बच्चे को सही संस्कार न मिले, तो उसके जीवन की बुनियाद ही गलत हो जाएगी। फिर उसके ऊपर बनने वाली इमारत में भी कभी मजबूती नहीं आएगी।



फोटो : इमेजेज बाजार

समय का सदुपयोग: मुझे बचपन में दादाजी द्वारा सुनाई गई एक कहानी याद आ रही है। कहानी ऐसे है कि एक लड़का बहुत शरारती था। स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं। उसका सारा दिन तरह-तरह की शरारतों की योजना बनाने और उनके द्वारा लोगों को तंग करने में गुजरता था। सारे मोहल्ले वाले उससे परेशान थे और रोजाना उसकी शिकायत करने आते रहते थे। रोज-रोज की उसकी शरारतों से तंग आकर उसके पिताजी ने एक दिन शाम को उसे बुलाया और कहा कि कल से अगर शाम तक कुछ पैसे कमा कर नहीं लाया, तो उसे घर में खाना नहीं मिलेगा। अगला दिन गुजरा, शाम को जब घर जाने का समय हुआ, तो उसको पिताजी की शर्त याद आई। तुरंत ही वह अपने चाचाजी के पास गया और उनसे कुछ पैसे मांगे। वह पैसे लेकर घर पहुंच गया। जब पिताजी ने पूछा कि क्या कमाया, तो उसने पैसे उनको दिखा दिए। पिताजी ने कहा इस पैसे को कुएं में फेंक दो। वह दौड़ता हुआ गया और पैसे कुएं में फेंक दिए, उसके बाद खाना खाया और सो गया। अगले कुछ दिनों तक दिनचर्या ऐसे ही चली। वह किसी अंकल-आंटी से पैसे लाता रहा। अब रोज-रोज कब तक लोग उसको पैसे देते। आखिर वह दिन भी आ गया, जब किसी ने उसको पैसे नहीं दिए। उस दिन उसको काम करने के बाद 25 पैसे मिले और जब शाम को पिताजी ने उसको कुएं में फेंकने को कहा, तो उसने कहा-मैं नहीं फेंक सकता, क्योंकि मुझे आज पैसे की अहमियत समझ में आ गई है। अब मैं खूब पढ़ूंगा और अपनी मेहनत से कुछ बनकर दिखाऊंगा। उसने अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगी और जीवन में आगे अग्रसर हो गया।

जायज-नाजायज मांगों की पहचान: आज के जमाने में भी इसका संशोधित प्रारूप बच्चों को सही राह दिखाने में काम आ सकता है। सबसे पहले हमको यह निर्णय करना होगा कि बच्चों की सभी जायज और नाजायज मांगों को नहीं मानेंगे। उनके लिए जो जरूरी है वह बेशक उपलब्ध कराएं, लेकिन नाजायज मांगों के लिए न बोलना भी बहुत जरूरी है।

आज जब स्कूल-कालेज बंद हैं और बच्चों के पास समय है, तो उनको अपने बिस्तर को ठीक से लगाने, बुक्स आदि को ठीक से रखने, घर की सफाई, अपने कपड़े खुद धोने और घर के अन्य कामों में मदद के लिए कुछ पैसे तय कर दें। उनके कमाए हुए पैसे को उनकी इच्छानुसार खर्च करने की सुविधा प्रदान करें। ऐसा करने से उनको किसी भी काम को छोटा-बड़ा समझने की परेशानी नहीं होगी और पैसे को समझदारी से व्यय करने की आदत भी पड़ेगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि यह ज्यादती है, तो जरा याद कीजिये। जब आप छोटे थे, तो क्या आप घर का छोटा-बड़ा काम नहीं करते थे? तब अपने माता-पिता को कभी किसी काम के लिए न नहीं कह सकते थे। तब के मुकाबले बदले हुए परिवेश में यह तो बहुत आसान है। मेरे विचार से पुराने जमाने में गुल्लक भी हम सबको बचत की अहमियत समझने में मदद करने वाली प्रथा थी। कुल मिलाकर, हमारे ऐसे छोटे-छोटे प्रयास से उनके सुनहरे भविष्य की बुनियाद बन सकती है।

सक्सेस मंत्रा

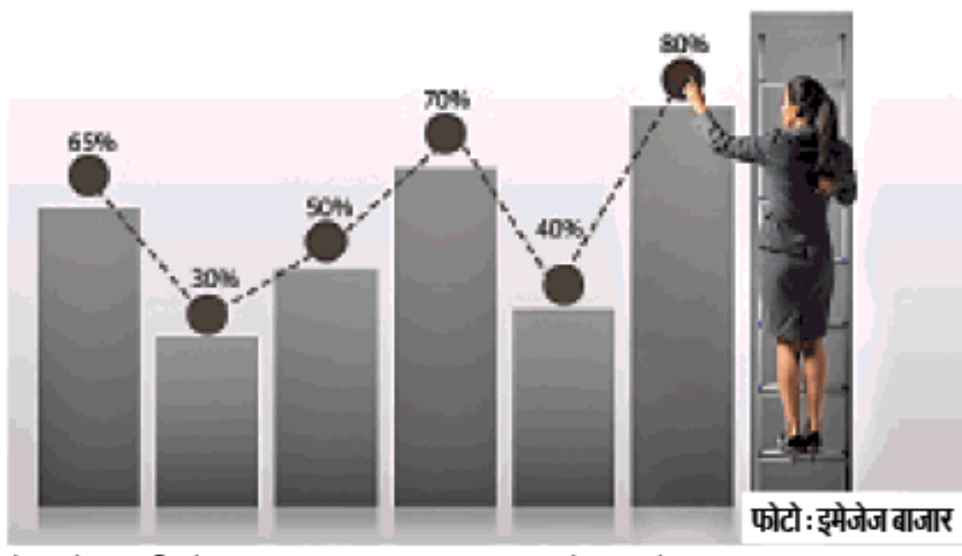


फरीदा गुप्ता
संस्थापक, फरीदा गुप्ता डाट काम

रोजगार देने में संतुष्टि का सुख

बिजनेस के साथ समाज के हाशिये पर बैठी महिला कारीगरों को आगे बढ़ते हुए देखना, उन्हें सबसे अधिक खुशी एवं संतुष्टि देता है। एक गृहिणी से डिजाइनर और फिर उद्यमी बनने का इनका सफर चुनौतीपूर्ण रहा। लेकिन नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने वाली फरीदा गुप्ता ने अपने हौसले एवं इच्छाशक्ति से फरीदा गुप्ता डाट काम को बाजार का एक स्थापित नाम बना दिया। 2017 में इन्हें देश की सबसे इनोवेटिव एसएमबी (डिजिटल) का खिताब भी मिल चुका है...

फरीदा का जन्म मुंबई में हुआ। वहीं पली-बढ़ीं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इनका दिल्ली आना हुआ। यहां से इन्होंने 1987 में फ्रेंच ट्रांसलेशन एवं इंटरप्रेटेशन में मास्टर्स किया। पीजी के बाद सोचा नहीं था कि क्या करेंगी। इसी बीच दिल्ली में ही इनकी शादी हो गई और वे घर-गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त हो गईं। लेकिन आर्ट्स एवं क्राफ्ट्स में रुचि थी, तो मन में कहीं न कहीं देश की पारंपरिक हस्तकला के संरक्षण के लिए कुछ करने की इच्छा जरूर थी। कई वर्ष फैशन इंडस्ट्री में काम करने के बाद 2011 में इन्होंने अपना वेंचर फरीदा गुप्ता लेबल लांच कर दिया।



फोटो : इमेजेज बाजार

टेक्नोलाजी ने बनाया आनलाइन बिजनेस को आसान

2016 में फरीदा ने कारोबार को डिजिटल प्लेटफार्म पर ले जाने का फैसला किया। इसमें इनके बेटे ने काफी मदद की। वह बताती हैं, 'हमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात के अलावा बरेली, लेह, पोर्ट ब्लेयर, कोच्चि, पांडिचेरी से आर्डर आने लगे। रेवेन्यू में करीब 400 फीसद की बढ़ोत्तरी हुई। मैं मानती हूं कि टेक्नोलाजी ने आनलाइन बिजनेस को काफी आसान बना दिया है। महिला उद्यमियों को भी इससे सहूलियत मिली है। फिलहाल तो हमारी कंपनी बूटस्ट्रैप्ड है। लेकिन आने वाले समय में ग्लोबल स्तर पर अपने ब्रांड को पहुंचाने का लक्ष्य जरूर रखा है।'

घर के दो कमरों से हुई शुरुआत: फरीदा बताती हैं, 'शुरुआत में मेरा सारा ध्यान हैंड एम्ब्रायडरी एवं ब्लाक प्रिंटिंग पर था। लेकिन इनके कारीगरों को तलाशना एक चुनौती थी। काफी शोध एवं अध्ययन के बाद मैंने स्वयं महिलाओं को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। दक्षिणी दिल्ली स्थित अपने आवास के दो कमरों में महिलाओं को हैंड एम्ब्रायडरी, ब्लाक प्रिंटिंग, डाइंग, वीविंग आदि का प्रशिक्षण देना शुरू किया।' फरीदा ने देश के सुदूर इलाकों के हस्तकरघा कारीगरों से भी संपर्क किया। इस तरह, दो महिलाओं के साथ हुई शुरुआत ने कुछ ही वर्षों में उन्हें एक स्थापित उद्यमी बना दिया।'

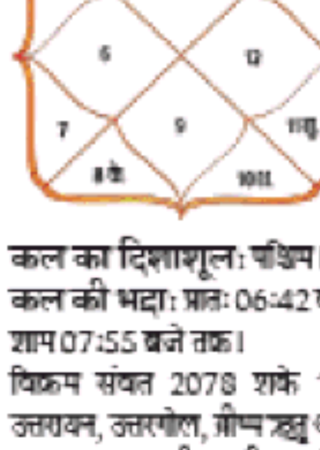
बातचीत: अंशु सिंह

आज का भविष्यफल

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: 3 जुलाई, 2021 शनिवार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष नवमी का राशिफल।
आज का राहुकाल: प्रातः 09:00 बजे से 10:30 बजे तक।
आज का दिशाशूल: पूर्व।
विशेष: पंचक (प्रातः 06:14 बजे पर समाप्त)

कल 4 जुलाई का पंचांग



कल का दिशाशूल: पश्चिम।
कल की भद्रा: प्रातः 06:42 बजे से शाम 07:55 बजे तक।
विक्रम संवत 2078 शके 1943 उत्तरायन, उत्तरगोल, ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की दशमी 19 घंटे 55 मिनट तक, तत्पश्चात् एकादशी अश्वनी नक्षत्र 09 घंटे 06 मिनट तक, तत्पश्चात् भरणी नक्षत्र सुकर्मा योग 12 घंटे 23 मिनट तक, तत्पश्चात् धृति योग मेष में चंद्रमा।

मेष: भावुकता में नियंत्रण रखें। रिश्तों में मधुरता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, लेकिन किसी पारिवारिक सदस्य से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं।

वृष: शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफल होंगे। बहन-भाई का भरपूर सहयोग मिलेगा। अज्ञात भय से ग्रसित हो सकते हैं। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य पूर्ण होगा।

मिथुन: शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। व्यावसायिक मामलों में तनाव मिलेगा। संयम से काम लेना हितकर है।

कर्क: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखमय होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

सिंह: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिल सकता है। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। रिश्तों में मधुरता आएगी।

कन्या: व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। जीवनसाथी का सहयोग एवं सान्निध्य मिलेगा।

तुला: मानसिक तनाव पर नियंत्रण होगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। रचनात्मक प्रयासों में सफलता मिलेगी।

वृश्चिक: गृह कार्य में व्यस्त हो सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। नए संबंध बनेंगे।

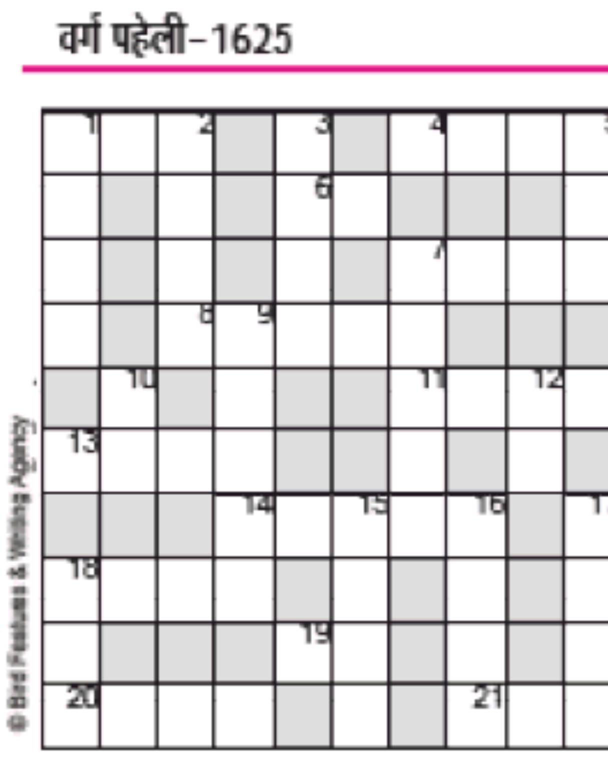
धनु: पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मकर: स्थानांतरण, विभागी परिवर्तन आदि की दिशा में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी।

कुंभ: निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मीन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रिश्तों में निकटता आएगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वर्ग पहेली-1625



© Best Features & Writing Agency

बाएं से दाएं
1 [illegible] (3)। 4 [illegible] (4)। 6 [illegible] (2)। 7 [illegible] (4)। 8 [illegible] (5)। 11 [illegible] (4)। 13 [illegible] (2,2)। 14 [illegible] (5)। 18 [illegible] (4)। 19 [illegible] (2)। 20 [illegible] (4)। 21 [illegible] (3)।

ऊपर से नीचे
1 [illegible] (4)। 2 [illegible] (4)। 3 [illegible] (4)। 5 [illegible] (3)। 7 [illegible] (5)। 9 [illegible] (5)। 10 [illegible] (2)। 12 [illegible] (2)। 15 [illegible] (4)। 16 [illegible] (4)। 17 [illegible] (4)। 18 [illegible] (3)।

कल का हल



जागरण सुडोकू-1625

		7				6		2
3				6				7
	6	2	3		7	5	8	
2			7			1		8
		1	6		5		2	
8	3			2			9	
9			8				5	
	1	8		7		9		3
	2		9		3			1

कल का हल

9	8	7	4	6	1	5	2	3
2	1	4	9	3	5	8	7	6
6	3	5	2	8	7	9	4	1
4	5	8	1	2	6	3	9	7
7	9	2	3	5	8	1	6	4
1	6	3	7	9	4	2	5	8
5	7	9	6	1	3	4	8	2
8	4	1	5	7	2	6	3	9
3	2	6	8	4	9	7	1	5

मौसम



काम की पढ़ें



गूगल असिस्टेंट के जरिए होती है जासूसी!

अगर आप गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब कोई गूगल असिस्टेंट से कुछ पूछता है तो उस रिकार्डिंग को गूगल के कर्मचारी भी सुन सकते हैं। ऐसे में जानें अपनी प्राइवेसी को कैसे सिक्योर कर सकते हैं...

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 3 जुलाई, 2021
आजकल
14
www.jagran.com

भाप के इंजन मालार्ड ने बनाया सबसे तेज गति का रिकार्ड

1938 में आज ही के दिन इंग्लैंड के मालार्ड नामक भाप इंजन ने सबसे तेज गति से चलने का रिकार्ड बनाया था। इसने 202.58 किलोमीटर प्रति घंटे की सर्वोच्च गति हासिल की थी। 24 लाख किमी के सफर के बाद सेवामुक्त हुआ यह इंजन अब यार्क के नेशनल रेलवे म्यूजियम में खड़ा है।





जेएल बेयर्ड ने पहली बार किया रंगीन टीवी पर प्रसारण

विज्ञानी जेएल बेयर्ड ने 1928 में आज ही के दिन पहली बार रंगीन टीवी पर प्रसारण किया था। बेयर्ड द्वारा टीवी पर रंगीन सजीव प्रसारण में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी ही आगे चलकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए चांद से सीधे रंगीन प्रसारण का आधार बनी थी।

एक लेखक जिनके नाम पर गढ़ा गया 'काफ्काएस्क' शब्द

लेखक शब्द गढ़ते हैं, लेकिन फ्रेंज काफ्का ऐसे लेखक हैं, जिनके नाम पर 'काफ्काएस्क' शब्द गढ़ा गया है। यह शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मुश्किलों में घिरा हो और कोई रास्ता न सूझ रहा हो। काफ्का की कहानियों में ऐसे कई चरित्र रहे हैं। काफ्का का जन्म 1883 में आज ही के दिन चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुआ था। उनकी रचनाएं आधुनिक समाज का बेजोड़ चित्रण हैं और साहित्यकार आज भी इनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी रचनाएं द ट्रायल, मेटामोर्फोसिस और द कैसल आज भी सराही जाती हैं।



ब्लैक होल में मिलीं गुरुत्वाकर्षण तरंगें खोलेंगी राज

रहस्यमय ब्रह्मांड ▶ नौ अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर खगोल विज्ञानियों ने रिकार्ड की अद्भुत घटना

वाशिंगटन, एएनआइ : हमारा ब्रह्मांड अनंत रहस्यों से भरा पड़ा है। दुनिया भर के विज्ञानी इन रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में खगोल विज्ञानियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल, विज्ञानियों ने पहली बार ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के विलय के कारण गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया है। विज्ञानियों का मानना है कि इस खोज से भविष्य में ब्लैक होल व ब्रह्मांड के कई रहस्य खुल सकते हैं।



इस खोज से उत्साहित हैं विज्ञानी। फाइल फोटो

दो मुख्य सिद्धांत करते हैं काम

न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल के विलय में दो मुख्य सिद्धांत काम करते हैं। पहले में दो तारे एक-दूसरे की परिक्रमा कर रहे होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। वहीं, दूसरे सिद्धांत में सुपरनोवा विस्फोट विलय की वजह हो सकता है। विज्ञानियों ने न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल के विलय की जो नई घटना का पता लगाया है उससे इनकी उत्पत्ति का पता चलने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का भी पता चला है।

अभी और अध्ययन की जरूरत

मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण इस खोज पर साल भर चलने वाले तीसरे अवलोकन को कम करके एक महीने का कर दिया गया था। वहीं, चौथा अवलोकन 2022 की गर्मियों में शुरू होने की उम्मीद है। इसमें और बेहतर डिटेक्टरों का प्रयोग किया जाएगा, ताकि और जानकारी जुटाई जा सके।

दरअसल, शोधकर्ताओं की टीम ने जनवरी, 2020 में 10 दिनों की अवधि के भीतर गुरुत्वाकर्षण तरंगों से जुड़ी दो घटनाओं का पता लगाया, जो हमसे नौ अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर घटित हुईं। इस अध्ययन को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित किया गया।

विलय की इन घटनाओं की प्रमुख विशेषताओं की पहचान करने में रोचेस्टर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी के सेंटर फार कंप्यूटेशनल रिलेटिविटी एंड ग्रेविटेशन (सीसीआरजी) के शोधकर्ताओं ने मदद की। भारत की खगोल भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी की पीएचडी छात्रा अंजलि येलिकर ने भी इस खोज में अहम भूमिका निभाई है। एसोसिएट प्रोफेसर रिचर्ड ओ शॉनेस्सी और पूर्व छात्र जैकब लैंग द्वारा विकसित पैरामीटर अनुमान कोड का प्रयोग अंजलि ने अंतरिक्ष में जिस स्थान पर यह घटना हुई वहां की दूरी, स्थिति, तारों का द्रव्यमान, घूर्णन गति आदि का पता लगाने के लिए किया। अंजलि के मुताबिक, इस तरह की खोज का हिस्सा बनना किसी सपने के सच होने जैसा है। 2016 में मैं एक स्नातक छात्रा थी, जब लीगो (लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी) ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पहचान करने की घोषणा की थी। यह देखना अद्भुत होगा कि विज्ञान इस दिशा में कितनी दूर तक जा सकता है और मैं यह देखने के लिए बेहद उत्साहित हूं कि वैज्ञानिक समुदाय कितने अधिक संवेदनशील डिटेक्टरों का विकास कर सकता है, ताकि ब्रह्मांड के और रहस्यों पर से पर्दा उठाया जा सके।

ओ शॉनेस्सी के मुताबिक, अभी तक खगोलविदों के पास इन तारों के परिवार की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इस नई खोज से हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। अब हम इसके पूरे परिवार को देख सकते हैं। इस वजह से इनका पूरा मानचित्र तैयार किया जा सकता है। साथ ही इनकी वंशावली का भी पता लगाया जा सकता है। इन नई जानकारियों की मदद से हमें ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों की उत्पत्ति और इनके विलय होने के साथ-साथ ब्रह्मांडीय विस्फोट कैसे होते हैं यह भी पता चल सकता है। वहीं, इस खोज के दौरान जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता चला है, अभी विज्ञानियों ने उनके बारे में अधिक विश्लेषण नहीं किया है। अगले अवलोकन में उस पर भी काम किए जाने की संभावना है। विज्ञानियों ने उम्मीद जताई है कि इस नई खोज का जब पूरी तरह अध्ययन कर लिया जाएगा तो इसके निष्कर्ष ब्रह्मांड के कई रहस्यों पर से पर्दा उठा देंगे।

इधर-उधर की

बिल्ली को बचाने पेड़ पर चढ़ा शख्स खुद फंसा

वाशिंगटन, एजेंसी : इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता न केवल सबसे पुराना है, बल्कि दोनों एक-दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं।



अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने की मदद। इंटरनेट मीडिया

अमेरिका के ओक्लाहोमा प्रांत में रहने वाले जेरेमी ब्रूक्स ने यह बात उस समय साबित कर दी, जब वह पेड़ पर चढ़ी बिल्ली को बचाने के लिए स्वयं पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ की ऊंचाई ज्यादा होने के चलते वह खुद फंस गए। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने दोनों को सुरक्षित निकाला। टुल्सा अग्निशमन विभाग ने राहत और बचाव कार्य से जुड़ा एक 50 सेकेंड का वीडियो अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर शेयर किया है और दोनों को सुरक्षित बचाने की बात कही है।



डिज्नीलैंड खुलने का जश्न...

अमेरिका के फ्लोरिडा में लेक बुएना विस्टा में स्थित वॉल्ड डिज्नी वर्ल्ड मैजिक किंगडम करीब 15 माह बाद खोला गया। इस मौके पर आतिशबाजी करके जश्न मनाया गया। इस मैजिक किंगडम की परिकल्पना एक अलग ही दुनिया के रूप में की गई है। यह पार्क विक्टोरिया काल की याद दिलाता है। इस दुनिया में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है मानो धरती की सभ्यता और संस्कृति से अलग किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। यह भी अपने आप में एक रिकार्ड है कि यहां दुनियाभर से 51 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से इसे पिछले साल बंद कर दिया गया था। एपी

टीका लगवाने वालों में कोरोना के गंभीर होने का खतरा कम

अनुसंधान



कोरोना से जंग में टीका अहम हथियार है। फाइल

वैक्सीन लगवाने के बावजूद कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इसमें पाया गया है कि टीका लगवाने के बावजूद अगर कोई कोरोना से पीड़ित होता है तो उसमें संक्रमण के गंभीर होने का खतरा काफी हद तक कम रहता है। इन पीड़ितों में संक्रमण भी कम समय तक रहता है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, वैक्सीन कोरोना संक्रमण की रोकथाम में बेहद प्रभावी होती हैं, लेकिन कोई भी टीका 100 फीसद कारगर नहीं है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी आफ एरिजोना हेल्थ साइंसेज के प्रोफेसर जेफ बर्गेस ने कहा, 'अगर आपने टीका लगवा लिया है तो कोरोना की चपेट में आने का खतरा करीब 90 फीसद तक कम हो जाता है। इसके बावजूद अगर कोई पीड़ित होता है तो संक्रमण का स्तर मामूली रह सकता है।' अध्ययन के नतीजों को न्यू इंग्लैंड जर्नल आफ मेडिसिन में प्रकाशित किया गया है। यह अध्ययन कोरोना से मुकाबले में अग्रिम मोर्चे पर तैनात रहे 3,975 स्वास्थ्यकर्मियों पर किया गया था। इन प्रतिभागियों का 14 दिसंबर, 2020 से 10 अप्रैल, 2021 के दौरान कोरोना टेस्ट किया गया। इनमें से उन प्रतिभागियों में से सिर्फ पांच लोग संक्रमित पाए गए, जिनका टीकाकरण पूरा हो चुका था। सिर्फ एक डोज लगवाने वालों में से 11 पीड़ित पाए गए, जबकि टीका नहीं लगवाने वाले प्रतिभागियों में से 156 कोरोना से बीमार मिले। -प्रेट्र

फिल्म रिव्यू

हसीन दिलरुबा

प्रमुख कलाकार : तापसी पन्नू, विक्रांत मेस्सी, हर्षवर्धन राणे, आदित्य श्रीवास्तव
निर्देशक : विनिल मैथ्यू
अवधि : दो घंटा 15 मिनट
डिजिटल प्लेटफार्म : नेटफ्लिक्स

कहानी हसीन नहीं बन पाई



फिल्म के शीर्षक से ही जाहिर है कि यह एक हसीन लड़की के इर्दगिर्द होगी। कनिका ढिल्लन की लिखी कहानी का आरंभ ज्वालापुर में रह रही रानी कश्यप (तापसी पन्नू) से होता है। वह घर के बाहर कुत्तों को मांस खिला रही है। अचानक उसके घर में ब्लास्ट होता है। बदहवास रानी घर के अंदर भागती है। वहां कटे हुए हाथ पर रानी नाम का टैटू देखकर वह शोक संतप्त हो जाती है। यह हाथ उसके पति ऋषभ सक्सेना (विक्रांत मेस्सी) का है। शक की सुई रानी की ओर जाती है। पुलिस अधिकारी (आदित्य श्रीवास्तव) रानी से पूछताछ करते हैं। कहानी रानी के फ्लैशबैक में जाती है।

दिल्ली की रहने वाली रानी हिंदी साहित्य में एमए है। वह पार्लर में काम करती है। वह घरेलू काम में निपुण नहीं है, लेकिन सैलून के काम अच्छी तरह करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि वह क्राइम उपन्यासकार दिनेश पंडित की दीवानी है, जो छोटे-छोटे शहरों में बड़े-बड़े कत्ल करा देते हैं। ज्वालापुर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर ऋषभ के साथ उसकी अरेंज मैरिज होती है। वैवाहिक जीवन की अंतरंग बातें मायके वालों को बताने से ऋषभ नाराज हो जाता है। इस बीच ऋषभ का दूर का रिश्तेदार नील (हर्षवर्धन राणे) उनके घर आता है। रानी उसे दिल दे बैठती है। ऋषभ का रिश्ता रानी के साथ इतना बिगड़ जाता है कि वह उसकी जान लेने की कोशिशें करता है।

विनिल मैथ्यू ने इस फिल्म से पहले 'हंसी तो फंसी' फिल्म का निर्देशन किया था। मिस्ट्री थ्रिलर वाली फिल्मों में कातिल को ढूंढने का जो रोमांच अंत तक बने रहना चाहिए, उसमें कनिका और विनिल चूक गए हैं। दिल्ली की आधुनिक और तेजतर्रार लड़की का इस तरह के उपन्यासों से लगाव भी थोड़ा अटपटा लगता है, खासकर जब कहानी इसी दौर की है।

तापसी फिल्म में हसीन ही लगी हैं, क्योंकि उनके चेहरे के भाव और डायलाग बोलने का अंदाज उनकी पिछली फिल्मों की याद दिलाता है। रोमांच वाले दृश्य विक्रांत को मिले हैं, जिनमें वे चौंकाते हैं। 'तैश' फिल्म के बाद हर्षवर्धन को इस तरह के किरदार में देखना निराशाजनक रहा।

फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले कमजोर है। साथ ही किरदारों में भी गहराई नहीं दिखाई पड़ी। पुलिस स्टेशन में रानी की कहानी सुनने के लिए सभी पुलिसकर्मी मजमा लगा लेते हैं, जैसे वहां रानी के अलावा कोई केस ही न हो। फिल्म में पुलिस की जांच का तरीका भी बचकाना दिखाई देता है। 'सीआइडी' जैसे शो में सशक्त अधिकारी के तौर पर नजर आए आदित्य श्रीवास्तव यहां पर प्रभावित नहीं करते। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी अच्छी है।

-प्रियंका सिंह

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

स्क्रीन शॉट

न अपना वक्त बर्बाद करती हूं, न दूसरों का : तनुश्री दत्ता

करियर के शुरुआत में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, जिनकी समझ तब नहीं होती है, लेकिन जैसे-जैसे करियर में लोग आगे बढ़ते हैं, काम और लोगों को लेकर समझ बढ़ने लगती है। अभिनेत्री तनुश्री दत्ता का मानना है कि वह अब पहले के मुकाबले काफी समझदार हो गई हैं। वह पुरानी गलतियों को नहीं दोहराती हैं। एक लाइव चैट के दौरान तनुश्री ने कहा कि मैं पहले के मुकाबले अब बहुत फिट हो गई हूं। इंडस्ट्री के लोगों को पता है कि मैं दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार हूं। ऐसे में मेरे पास कई प्रोजेक्ट को लेकर आफर आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि मैं चूजी हूं। हां, मैं अब चूजी हो गई हूं। मुझे दूसरों का वक्त और ऊर्जा बर्बाद करना पसंद नहीं है और न ही मैं चाहती हूं कि लोग मेरा वक्त बर्बाद करें। पहले ऐसे कई अनुभव हो चुके हैं। मैं प्रोजेक्ट के लिए यह सोचकर हां कर देती थी, अनुभव न सही, लेकिन मुझे उन्हें मौका देना चाहिए। कुछ वक्त काम करने के बाद महसूस होता था कि उनमें तो काम को लेकर स्पष्टता ही नहीं थी। तब बुरा लगता था कि इससे अच्छा कोई और बेहतर काम कर लिया होता। दरअसल, मैं बहुत जल्द भरोसा कर लेती थी। अब मैं इस बिजनेस को अच्छी तरह से सीख गई हूं। अब मैं सोच-समझकर स्क्रिप्ट्स चुन रही हूं। अब मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चुनने के बजाय क्वालिटी पर ध्यान दे रही हूं। हालांकि, कई बार प्रोजेक्ट्स को छोड़ना भी आसान नहीं होता है।



फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार हैं तनुश्री। इंस्टाग्राम

चाय, कचौड़ी की दुकान भी लगा चुका हूं

जीवन के संघर्ष इंसान को कामयाब बनाते हैं। कामयाब होने के बाद संघर्ष की कहानियां मिसाल बन जाती हैं, जिसे बाद में चाव से लोगों को सुनाया जाता है, ताकि दूसरे भी उससे प्रेरित हों। ऐसी कई बातें मिस्टर इंडिया और ड्रीमगर्ल फिल्म के अभिनेता अन्नू कपूर ने भी एक लाइव चैट के दौरान बताईं। अपनी पहली कमाई के बारे में बताते हुए अन्नू ने कहा कि मुझे लखनऊ में एक प्रोग्राम में स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए पांच रुपये मिले थे, लेकिन उससे ज्यादा प्रिय थे पापा के दिए हुए दो रुपये। ऐसा नहीं था कि 60 रुपये महीने की पॉकेट मनी थी। वह दो रुपये तभी मिलते थे, जब मैं उनकी नाटक कंपनी द्वारा मंचित नाटक में काम करता था। मैंने मध्य प्रदेश के जावरा में चाय का ठेला और कचौड़ी की दुकान भी लगाई थी, लेकिन पापा की नाटक कंपनी में काम करने जैसा सुख कहीं नहीं था। उस वक्त मेरे बड़े भाई ने कहा था कि जब अभिनय ही करना है तो नेशनल स्कूल आफ ड्रामा (एनएसडी) ज्वाइन कर लो। पहला रिजेक्शन भी मुझे एनएसडी में मिला था। वहां एक नाटक के लिए सबको परफॉर्म करने के लिए बोला गया था। जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता उसे नंबर दिए जाने वाले थे और उस नंबर के आधार पर नाटक के लिए चुना जाने वाला था। मुझे सबसे ज्यादा नंबर मिले थे, लेकिन फिर भी मुझे उस नाटक में काम नहीं मिला था, क्योंकि शायद मैं उन्हें किरदार के लिए उतना सुंदर नहीं लगा था। शक्ल की वजह से वह किरदार मुझे नहीं मिला था। वह खलिश जिंदगी भर मन में रह गई थी।



अन्नू कपूर को याद आए संघर्ष के दिन। इंस्टाग्राम

पहले हालीवुड में भारतीय एक्टर के लिए रोल नहीं लिखे जाते थे : कबीर बेदी

बड़े-बुजुर्ग अपनी आगे की पीढ़ी से अपने अनुभव साझा करते हैं, ताकि वह उनसे कुछ सीखकर अपने जीवन को बेहतर बना सके। हाल ही में कबीर बेदी और उनकी नातिन अलाया एक इंस्टाग्राम लाइव पर जुड़े। कबीर बेदी की आटोबायोग्राफी स्टोरीज आइ मस्ट टेल : द इमोशनल लाइफ आफ एन एक्टर पढ़ने के बाद अलाया ने अपने नाना का इंटरव्यू किया। अलाया ने कबीर बेदी से पूछा कि जब से वह फिल्मों में काम करने लगी हैं, तब से लोग उन्हें यही कहते हैं कि सफलता को सिर पर मत चढ़ने देना, अभिमानी मत बनना। ऐसे में कबीर में भी क्या सफलता देखने के बाद अभिमान आ गया था? इस पर कबीर कहते हैं कि मैं भीतर से कभी अभिमानी नहीं रहा। हालांकि, मैंने मेहनत बहुत की है, सफलता देखने के बाद भी। बालीवुड में अच्छा समय देखने के बाद मैं इतालवी फिल्मों में बड़ा स्टार बन गया था। मुझे लगा कि हालीवुड में करियर बनाना आसान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां मैंने बोल्ड एंड ब्यूटीफुल और जेम्स बांड की फिल्मों में काम किया, लेकिन उस वक्त तक भारतीय कलाकारों के लिए वहां कोई किरदार नहीं लिखे जाते थे। वहां काम पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। अब माहौल बहुत अलग है। पिछले कुछ वर्षों से वहां लोग भारतीय कलाकारों को भी जानने लगे हैं। इस लाइव के दौरान वह अलाया से कहते हैं कि तुम्हारी पीढ़ी की दुनिया बहुत अलग है। गुलजार साहब की लिखी एक लाइन याद आती है कि खुद से ज्यादा मैं अपने मोबाइल को संभालकर रखता हूं, क्योंकि अब सारे रिश्ते इसी में कैद हैं। अब सारे रिश्ते जब मोबाइल पर कैद हैं तो यह पीढ़ी नए दोस्त कैसे बनाती है। इस पर अलाया ने कहा कि यह इंटरनेट मीडिया का जादू है। इंटरनेट की वजह से कई दोस्त बने, कई नए लोगों से मिली हूं। फोन के बिना घर से बाहर जाने का मतलब होता है जैसे जीवन में कुछ खो गया है। कोरोना काल में कई काम फोन पर ही किए हैं।

पर्यावरण संरक्षण की तरफ दीपशिखा की पहल



'रीसाइकिल मैन' के तौर पर विख्यात डा. बिनिश देसाई के साथ काम करेंगी दीपशिखा। सौ. पीआर टीम

कोविड 19 के प्रकोप को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण की पैरोकारी जोर-शोर से की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई सितारे जागरूक भी करते हैं। वहीं, इस दिशा में निर्माता दीपशिखा देशमुख ने 'रीसाइकिल मैन' के तौर पर विख्यात डा. बिनिश देसाई के साथ सेट पर होने वाले कचरे को रीसाइकिल करने के लिए हाथ मिलाया है। दीपशिखा ने 'कुली नंबर 1' और 'बेल बॉटम' जैसी फिल्मों के निर्माण के दौरान सिंगल-यूज प्लास्टिक के उपयोग से यथासंभव दूरी बनाई थी। वह कहती हैं, 'मैं इस बारे में बहुत चिंतित थी कि सेट पर इस्तेमाल होने वाले मास्क और पीपीई किट का क्या किया जाए। अब डा. बिनिश हमारे साथ हैं। वह एक प्रेरक सामाजिक उद्यमी हैं, जो औद्योगिक अपशिष्ट के रीसाइकिल पर काम कर रहे हैं। वह हमारा उन विभिन्न तरीकों के बारे में मार्गदर्शन करेंगे, जिनसे हम अपने उत्पादित कचरे को रीसाइकिल कर सकते हैं। फिर चाहे वह निर्माण सामग्री हो, जिसका उपयोग सेट बनाने के लिए किया जाता है या प्लास्टिक का इस्तेमाल, पीपीई किट और मास्क या यहां तक कि कप में छोड़े गए चाय और कॉफी के तलछट। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम पर्यावरण-संवेदनशीलता को अपनी परियोजनाओं का हिस्सा बनाएं।' इन बातों का ध्यान वह अपने पूजा एंटरटनेमेंट आफिस में भी रखेंगी। डा. बिनिश प्रोडक्शन हाउस और फिल्मों के लिए सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। डा. बिनिश के मुताबिक, उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना 2016 में की जो किफायती दाम में पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियां और समाधान प्रदान करती है।

फिल्म को दूसरी भाषा में रीमेक करने से संस्कृति और सेटअप का अंतर पड़ जाता है। दूसरी भाषा में डबिंग का विकल्प हमेशा होता है, लेकिन जब कहानी को एक संस्कृति से निकालकर दूसरी संस्कृति में सेट किया जाता है तो उससे फिल्म नई दिखने लग जाती है।

फॉरेंसिक फिल्म में विक्रांत का बदलेगा किरदार

दक्षिण भारतीय फिल्मों की हिंदी में बनती रीमेक में मलयालम फिल्म फॉरेंसिक का नाम भी शामिल है। यह फिल्म पिछले साल रिलीज हुई थी। कुछ समय पहले इस फिल्म की हिंदी रीमेक बनाने की घोषणा हुई थी, जिसका निर्देशन विशाल फुरिया कर रहे हैं। फिल्म में विक्रांत मेस्सी मुख्य किरदार में होंगे। इस फिल्म को हिंदी में बनाने को लेकर जो बदलाव होंगे उसके बारे में दैनिक जागरण से बात करते हुए विशाल ने बताया कि फिल्म को दूसरी भाषा में रीमेक करने से संस्कृति और सेटअप का अंतर पड़ जाता है। दूसरी भाषा में डबिंग का विकल्प हमेशा होता है, लेकिन जब कहानी को एक संस्कृति से निकालकर दूसरी संस्कृति में सेट किया जाता है, तो उससे फिल्म नई दिखने लग जाती है। जैसे मैंने जब अमेरिकी शो क्रिमिनल जस्टिस का रीमेक किया था, तो उस कहानी को भारत में सेट करते ही वह अलग बन गई थी। फॉरेंसिक फिल्म के साथ भी ऐसा ही होगा, जब वह फिल्म नए कल्चर में जाएगी, तो अलग दिखेगी। क्रिमिनल जस्टिस के पहले सीजन में विक्रांत अहम भूमिका में थे। विशाल कहते हैं कि विक्रांत के साथ मैंने 70-80 दिन शूट किया था। हमारी आपसी केमेस्ट्री बहुत बढ़िया है। वह बतौर निर्देशक मुझे समझते हैं और मैं उन्हें। मैं विक्रांत के किरदार को मूल फिल्म से बहुत अलग रखने वाला हूं। साथ ही विक्रांत को इस रूप में दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। फिलहाल विक्रांत अपनी आगामी फिल्म लव हास्टल पर काम कर रहे हैं, जो शाह रुख खान के प्रोडक्शन कंपनी की फिल्म है। जैसे ही उसकी शूटिंग खत्म होगी, हम अगस्त से फॉरेंसिक की शूटिंग शुरू कर देंगे।



अगस्त से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे विक्रांत ● इंस्टाग्राम

क्विज शो की मेजबानी करेंगे रणवीर सिंह

छोटे पर्दे पर कई विदेशी शो के देसी संस्करणों को लांच किया गया है। इन शो की मेजबानी हिंदी सिनेमा के प्रख्यात कलाकारों ने की है। अब इस फेहरिस्त में रणवीर सिंह का नाम जुड़ने जा रहा है। सिंबा अभिनेता रणवीर कलर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले क्विज शो द बिग पिक्चर की मेजबानी करेंगे। यह पहला मौका है जब वह टीवी पर किसी शो की मेजबानी करते नजर आएंगे। यह देश का पहला विजुअल आधारित क्विज शो होगा। आज इस शो का प्रोमो जारी किया जाएगा। द बिग पिक्चर डिजिटल प्लेटफार्म वूट पर भी उपलब्ध होगा। यह अंतरराष्ट्रीय शो द बिग पिक्चर का भारतीय संस्करण होगा। द बिग पिक्चर का संवादपूर्ण फॉर्मेट दर्शकों को अपने घर बैठकर खेलने और पुरस्कार जीतने का मौका देगा। विजेता बनने के लिए प्रतिभागियों को बारह प्रश्नों के जवाब देने होंगे। टेलीविजन पर शुरुआत करने के बारे में रणवीर सिंह ने कहा, कलाकार के रूप में मेरे सफर में प्रयोग करने व खोज करने की मेरी लालसा निरंतर चलती रहती है। भारतीय सिनेमा ने मुझे सब कुछ दिया। यह अभिनेता के रूप में आगे बढ़ने और कौशल का प्रदर्शन करने का मंच बना रहा।



शो से टीवी पर डेब्यू कर रहे हैं रणवीर ● पीआर टीम

इसलिए शुरू नहीं हो पाया है अक्षय का शो द एंड

कोरोना संक्रमण की वजह से कई प्रोजेक्ट्स शुरू नहीं हो पाए हैं। इनमें अभिनेता अक्षय कुमार का वेब शो द एंड भी शामिल है। इस शो को विदेश में शूट किया जाना है, लेकिन महामारी की वजह से विदेश यात्रा पर लगी पाबंदियों की वजह से इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। हालांकि यूरोप ने वैक्सीन लगवा चुके लोगों को यात्रा की अनुमति दे दी है। 'खिलाड़ी' अभिनेता इस शो से डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं। इसकी घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी। इस शो के निर्माता विक्रम मल्होत्रा हैं। उनके मुताबिक कई चीजों पर स्पष्टता न होने से वह भी इंतजार कर रहे हैं। विक्रम ने दैनिक जागरण के सहयोगी अखबार मिड डे से बातचीत में कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा के प्रोटोकॉल को समझने के लिए हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि यात्रा के लिए वैक्सीन प्रमाणपत्र स्वीकार्य हैं या नहीं। हमने लाकडाउन का इस्तेमाल स्क्रिप्ट को पूरा करने और प्री प्रोडक्शन में किया है। वह व्यवधानों के बावजूद अपने इस शो को भव्य बनाने की प्रक्रिया में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शो के लिए दो चीजें अहम हैं पहला अक्षय कुमार की तारीखें दूसरा अंतरराष्ट्रीय यात्रा। विक्रम इसके अलावा फिल्म छोरी का भी निर्माण कर रहे हैं। उसमें नुसरत भरुचा प्रमुख भूमिका में हैं।



फिलहाल अपनी अधूरी फिल्मों की शूटिंग पूरी करने में लगे हैं अक्षय कुमार ● इंस्टाग्राम >>

अगले महीने से नई फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगी तापसी



खासी व्यस्त हैं तापसी पन्नू ● इंस्टाग्राम

बीते दिनों रूस से छुट्टियां मनाकर लौटीं तापसी पन्नू इन दिनों खासी व्यस्त हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के पहले उन्होंने अपनी चार अधूरी फिल्मों की शूटिंग पूरी कर ली थी। उनकी फिल्म हसीन दिलरुबा शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। अब वह अपनी नई फिल्म की तैयारी में हैं। खबरें हैं बीए पास और सेक्शन 375 फिल्म का निर्देशन कर चुके अजय बहल के साथ वह अपनी अगली फिल्म शुरू करने जा रही हैं। बताया जाता है कि यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म तीन किरदारों के ईर्दगिर्द घूमती है। इसमें गुलशन देवैया अहम भूमिका में होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने से नैनीताल में होगी। तापसी इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिट्ठू शुरू करने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म के निर्देशन की बागडोर श्रीजित मुखर्जी के हाथों में आने से इसकी शूटिंग स्थगित हो गई है। फिल्म के बाद वह सिद्धार्थ राय कपूर की फिल्म वो लड़की है कहां की शूटिंग आरंभ करेंगी उसमें उनके अपोजिट प्रतीक गांधी होंगे। इसके अलावा उनकी फिल्म रश्मि रॉकेट, लूप लपेटा, दो बारह रिलीज की कतार में हैं।